राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 10, अंक- 337, पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, बुधवार , 16 जून 2021 मूल्य रु. 1.50

एक नज़र...

एमएसएमई पंजीकरण के लिए आधार, पैन जरूरी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पंजीकरण के लिए प्रक्रिया को सरल करने की घोषणा करते हुए मंगलवार को कहा कि इसके लिए केवल आधार और पैन कार्ड आवश्यक होगा। श्री गडकरी ने मंगलवार शाम यहां 'एसएमई स्ट्रीट गेमचेंजर्स फोरम' के एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि अब एमएसएमई के पंजीकरण के लिए केवल पैन और आधार की आवश्यकता होगी। पंजीकृत होने के बाद एमएसएमई इकाई को प्राथमिकता और वित्त मिलेगा। उद्यमिता और अन्य संबंधित पहलुओं के क्षेत्र में छोटी इकाइयों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। उन्होंने एमएसएमई मंत्रालय के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

18 + को कोविन एप पर रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण के लिए कोविन एप पर रजिस्ट्रेशन कराने की बाध्यता समाप्त कर दी है। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोविड वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं है। सरकार के अनुसार, 18 साल या उससे अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति सीधे निकटतम वैक्सीनेशन सेंटर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाकर वैक्सीन लगवा सकता है। मंत्रालय ने ये भी कहा कि 18 साल से अधिक उम्र के हर शख्स ऑनलाइन या ऑफलाइन (सेंटर पर) रजिस्ट्रेशन करा सकता है। पीआईबी द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि कोविन प्लेटफॉर्म, टीकाकरण के लिए पंजीकरण के कई तरीकों में से एक है और इनमें वॉक-इन भी शामिल है।

ट्विटर में अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्र सरकार की ओर से ट्विटर को नोटिस जारी करने के कुछ दिनों बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर की अध्यक्षता वाली एक संसदीय समिति ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के शीर्ष अधिकारियों को शुक्रवार को बयान दर्ज कराने और सोशल मीडिया मंच के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए प्रतिवेदन देने के लिए तलब किया है। इसके अलावा ट्विटर ने जानकारी दी है कि उसने नए आईटी नियमों के तहत अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त कर दिया है। इसके साथ ही उसने यह भी कहा है कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ विवरण साझा किया जाएगा। इधर, मंत्रालय से संबंधित संसद की स्थायी समिति की 18 जून को होने वाली बैठक के संदर्भ में जारी एक नोटिस के मुताबिक इसका एजेंडा ट्विटर के प्रतिनिधियों के पक्ष को सुनना है।

दिल्ली हिंसा केस में नताशा कलिता, तन्हा को मिली बेल

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 जून को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दिल्ली हिंसा केस में नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत दे दी। कोर्ट ने कई तथ्यों को ध्यान में रखते हुए माना कि विरोध जताना कोई आतंकी गतिविधि नहीं है। हाईकोर्ट के फैसले का कई राजनीतिक हस्तियों व एक्टिविस्ट ने स्वागत किया है। जस्टिसद्वय सिद्धार्थ मृदुल व अनूप भंभानी की पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया, यूएपीए की धारा 15, 17 या 18 के तहत कोई भी अपराध, तीनों के खिलाफ मौजूदा केस में, रिकॉर्ड सामग्री के आधार पर नहीं बनता है। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने फैसले का स्वागत करते हुए लिखा तीनों कार्यकताओं को जमानत देने पर दिल्ली हाईकोर्ट को बधाई।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मानसून सीजन की तैयारियों को लेकर बैठक की

नई दिल्ली । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को देशभर में मानसून सीजन की तैयारियों को लेकर बैठक की। इसमें गृह मंत्रालय से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। इस बार मानसून देशभर में करीब 10 दिन पहले आ गया है। पछुआ हवाओं के कारण मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने से उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में मानसून का इंतजार बढ़ सकता है। इन क्षेत्रों में अब कुछ दिनों की देरी से मानसून पहुंचने की उम्मीद है। यह पूर्वानुमान सोमवार को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) ने व्यक्त किया।

आइएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि मौसम विभाग ने दक्षिण-पश्चिम मानसून के 15 जून तक देश की राजधानी में पहुंचने की उम्मीद जताई थी। हालांकि, मौजूदा परिस्थितियों में ऐसा होने की संभावना नहीं है। महापात्रा ने कहा कि आइएमडी के अनुसार मानसून की उत्तरी सीमा (एनएलएम) दीव, सूरत, नंदूरबार, भोपाल, नौगांव, हमीरपुर, बाराबंकी, बरेली, सहारनपुर, अंबाला और अमृतसर से होकर गुजर रही है।

आइएमडी के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून अब तक पूरे प्रायद्वीप (दक्षिण भारत), पूर्व मध्य और पूर्व और उत्तरपूर्वी भारत और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में सक्रिय मानसून परिसंचरण और बिना किसी अंतराल के कम दबाव वाले क्षेत्र के गठन के साथ आगे बढ़ा है।

रामजन्मभूमि के जमीन मामले में बीजेपी चीफ नड्डा और गृहमंत्री शाह ने मांगी रिपोर्ट- अयोध्या में रामजन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के दौरान जमीन का विवाद तूल पकड़ता जा रहा है. आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है. समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं. इस विवाद की गूंज सुनते ही सूत्रों की मानें तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह ने इस पूरे मामले की तथ्यात्मक जानकारी मांगी है. वहीं बताया जा रहा है कि संघ नेतृत्व ने भी इस पूरे विवाद की रिपोर्ट श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट से मांगी है.

हालांकि श्रीराम जन्मभूमि भूमि ट्रस्ट की तरफ से पहले ही इस संबंध में सभी तथ्यों के साथ आधिकारिक तौर पर सफाई दी गई है. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से दावा किया गया है कि अभी तक जितनी भी जमीनें खरीदी गई हैं, उनकी कीमत खुले मार्केट से काफी कम हैं. ट्रस्ट के महासचिव और विश्व हिंदू परिषद के नेता चंपत राय की तरफ से आधिकारिक बयान जारी किया गया कि जिस जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर आरोप लग रहे हैं, उस जमीन का कई साल पहले रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हो गया था.

पहले से ज्यादा चालाक हो गया कोरोना की नया वेरिएंट, ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत:डॉ. वीके पॉल

नई दिल्ली । देश में कोरोना के कम होते मामले और टीकाकरण की स्थिति पर प्रेस कांफ्रेंस करते नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल ने कहा कि अभी वायरस का संचरण बहुत कम है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट 2020 के मुकाबले ज़्यादा चालाक हो गया है। अब हमें ज्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हमें ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मास्क लगातार पहने रखना होगा। कोविड प्रोटोकाल का सख्ती से पालन करना होगा। इसके बिना परिस्थिति फिर खराब हो सकती है।

उन्होंने कहा कि डेल्टा वेरिएंट ने कोरोना की दूसरी लहर में प्रमुख भूमिका निभाई। इस वेरिएंट के एक अतिरिक्त म्यूटेशन का पता लगा है, जिसे डेल्टा प्लस के रूप में जाना जाता है। इसका वैश्विक डेटा सिस्टम प्रस्तुत किया गया है। इसे मार्च से यूरोप में देखा गया है और इसे 13 जून को सार्वजनिक डोमेन में लाया गया है।डॉ. पॉल उन्होंने कहा कि नोवावैक्स वैक्सीन के रिजल्ट आशाजनक हैं। हम सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध आंकड़ों से परख रहे हैं कि यह टीका बहुत सुरक्षित और अत्यधिक प्रभावी है। इसका उत्पादन भारत में किया जाएगा। क्लिनिकल परीक्षण किए जा रहे हैं और एडवांस चरण पूरा होने की ओर है। नोवावैक्स वैक्सीन के उत्पादन में कुछ समय के लिए रहेगा। मैं यह भी उम्मीद कर रहा हूं कि वे (अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स) बच्चों पर भी परीक्षण शुरू करेंगे।

स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश में 9 लाख के करीब सक्रिय मामले बने हुए हैं। 20 राज्यों में 5,000 से कम सक्रिय मामले हैं। अन्य राज्यों में भी सक्रिय मामलों में कमी आ रही है। रिकवरी दर भी बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में देश में 1,17,525 रिकवरी हुई है। उन्होंने कहा कि कोरोना की पहली लहर में 1-10 वर्ष के आयु वर्ग में 3.28 फीसद बच्चे संक्रमित हुए, जबकि दूसरी लहर के दौरान 3.05 फीसद संक्रमित हुए। पहली लहर में 11-20 साल के आयु वर्ग में 8.03 फीसद और दूसरी लहर में 8.5 फीसद संक्रमित हुए।

लव अग्रवाल ने कहा कि अब तक देश में कुल 26 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज़ दी जा चुकी है। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में टीकाकरण एक अतिरिक्त उपकरण है। मैं सभी से स्वच्छता को प्राथमिकता देने और मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग समेत कोविड प्रोटोकाल का पालन करने का आग्रह करता हूं। जितना हो सके, यात्रा से बचें।

गलवान में शहीद वीरों की बहादुरी राष्ट्र की स्मृति में सदैव अंकित रहेगी : सेना प्रमुख

नई दिल्ली, (एजेंसी)। सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे ने पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में अप्रत्याशित चीनी आक्रामकता का सामना करते हुए देश की क्षेत्रीय अखंडता की खातिर एक साल पहले अपने प्राण न्यौछावर कर देने वाले 20 जवानों की बहादुरी की मंगलवार को प्रशंसा की।

सेना ने घातक झड़पों की पहली बरसी पर कहा कि जवानों का अत्यधिक ऊंचाई वाले सबसे कठिन इलाके में दुश्मन से लड़ते हुए दिया गया यह सर्वोच्च बलिदान राष्ट्र की स्मृति में सदैव अंकित रहेगा। सेना ने ट्वीट किया, जनरल एमएम नरवणे और भारतीय सेना के सभी रैंक के अधिकारी देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करते हुए लद्दाख की गलवान घाटी में सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि देते हैं। उनकी वीरता राष्ट्र की स्मृति में सदैव अंकित रहेगी। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ पिछले साल 15 जून को भीषण झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, जिसके बाद पूर्वी लद्दाख में संघर्ष के बिंदुओं पर दोनों सेनाओं ने बल और भारी हथियार तैनात किए थे। सेना की लेह स्थित 14 कोर ने भी हिंसक झड़पों की पहली बरसी पर गलवान में शहीद बहादुरों को श्रद्धांजलि दी। इस कोर को 'फायर एंड फ्यूरी कोर' के नाम से जाना जाता है। सेना ने कहा कि 20 भारतीय सैनिकों ने अप्रत्याशित चीनी आक्रमण का सामना करते हुए हमारी भूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए।

गलवान संघर्ष में शहीद कर्नल की प्रतिमा का तेलंगाना में अनावरण

हैदराबाद, (एजेंसी)। पिछले साल 15 जून को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के साथ खूनी संघर्ष में शहीद हुए कर्नल बी. संतोष बाबू की प्रतिमा का मंगलवार को तेलंगाना के सूर्यापेट शहर में अनावरण किया गया।

घटना से जुड़े हालात अब तक स्पष्ट नहीं,देश को भरोसे में ले केंद्र- सोनिया

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गलवान घाटी में शहीद 20 जवानों की पहली बरसी पर मंगलवार को कहा कि एक वर्ष का समय गुजरने के बाद भी इस घटना से जुड़े हालात साफ नहीं है। सरकार देश को विश्वास में ले और यह सुनिश्चित करे कि उसके कदम देश के जवानों की प्रतिबद्धता के अनुकूल रहे हैं। सोनिया ने जवानों के बलिदान को याद किया और यह दावा किया कि सैनिकों के पीछे हटाने का जो समझौता चीन के साथ हुआ है उससे भारत का नुकसान दिखाई पड़ता है। कांग्रेस अध्यक्ष ने एक बयान में कहा कि 14-15 जून, 2020 की रात को चीन की पीएलए के साथ हुई झड़प को एक साल पूरा हो गया है। इसमें बिहार रेजीमेंट के हमारे 20 जवानों की जान चली गई थी। कांग्रेस हमारे जवानों के सर्वोच्च बलिदान को याद करने में राष्ट्र के साथ शामिल है।

पीएम ने कहा था-कोई घुसपैठ नहीं हुई

सोनिया गांधी के मुताबिक, इसका बहुत ही धैर्य के साथ इंतजार किया गया कि सरकार सामने आएगी और देश को उन हालात के बारे में बताएगी, जिनमें यह अप्रत्याशित घटना घटी तथा वह लोगों को विश्वास दिलाएगी की हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अब कांग्रेस पार्टी अपनी इस चिंता को फिर से प्रकट करती है कि अब तक कोई स्पष्टता नहीं है और इस विषय पर प्रधानमंत्री का आखिरी वक्तव्य पिछले साल आया था कि कोई घुसपैठ नहीं हुई।

कांग्रेस और शिवसेना में जुबानी जंग, फिर भी महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक होने का दावा

मुंबई, (एजेंसी)। महाराष्ट्र में तीन पार्टियों की सरकार है, जिसमें शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर सरकार चलाने के लिए महा विकास अघाड़ी का गठन किया है। तीनों पार्टियों के नेताओं का दावा है कि सबके बीच अच्छा तालमेल है और सरकार भी अब तक अच्छे से चल रही है, लेकिन, कुछ दिनों से कांग्रेस और शिवसेना के नेताओं में जुबानी जंग चल रही है। कांग्रेस की तरफ से महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले लगातार शिवसेना पर हमला कर रहे हैं, तो अब शिवसेना के बड़े नेता भी महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले पर शद प्रहार कर रहे हैं।

दरअसल पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ, जब महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि आने वाले सभी चुनाव चाहे वो महानगरपालिका के हो या फिर विधानसभा चुनाव हो। सब जगहों पर कांग्रेस अकेले लड़ेगी और पटोले के नाम को मुयमंत्री पद के उमीदवार के तौर पर सबसे आगे रखा जाएगा। पटोले के इस ऐलान के बाद शिवसेना ने पलटवार करते हुए कहा कि नाना पटोले को उतना ही पैर पसारना चाहिए जितनी कि चादर हो।

इस बयान के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने शिवसेना पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी चादर कितनी लंबी है, यह आने वाले चुनावों में सबको पता चल जाएगा। हालांकि दोनों पार्टियों के नेताओं का साफ कहना है कि यह सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी और महा विकासअघाड़ी सरकार में एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस एक साथ सबको मदद करेगी। कांग्रेस ने कर दिया है अकेले चुनाव लड़ने का ऐलानः इन सबके बीच 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि वह महाराष्ट्र में 288 सीटों पर अकेले लड़ेगी।

जवानों की शहादत को याद कर सोनिया गांधी का केंद्र पर हमला

नई दिल्ली । गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प को आज एक साल पूरा हो गया है. इस मौके पर कांग्रेस ने हिंसक झड़प में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी है. कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बयान जारी शहीद जवानों को याद किया है. उन्होंने कहा, 15-16 जून 2020 की रात चीन के पीएलए सैनिकों के साथ टकराव में बिहार रेजिमेंट के 20 बहादुर सैनिक शहीद हो गए. इसमें कमांडिंग ऑफिसर भी शामिल थे. इस घटना की पहली बरसी पर कांग्रेस पार्टी पूरे देश के साथ इस महान बलिदान को याद कर रही है.

सोनिया गांधी ने कहा हम पूरे धैर्य के साथ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार सामने आकर एक साल पहले हुई इस घटना की पूरी जानकारी दें और स्थिति देश के सामने रखें और लोगों को बताए कि बहादुर सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, हालांकि इस मामले में अभी भी कोई स्पष्टता नहीं दी गई है. उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी सरकार से देश को विश्वास में लेने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह करती है कि उनका प्रदर्शन उन सैनिकों की प्रतिबद्धता के योग्य है जो सीमाओं पर बहादुरी और दृढ़ता से खड़े हैं.

15 जून को चीनी सेना को खदेड़ते हुए भारतीय सैनिकों ने अद्भय साहस का परिचय दिया. चीनी सैनिकों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन 20 जवानों ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब देते हुए देश के नाम अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया. इस इस साल फरवरी में चीन ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया था कि गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में चीनी सैनिक भी मारे गए थे. चीन ने कहा था कि भारतीय सैनिकों के साथ हुई उस हिंसक झड़प में पांच चीनी सैन्य अधिकारी और जवान मारे गए थे, जबकि रिपोर्ट्स की मानें तो मारे गए चीनी सैनिकों की संख्या इससे कहीं ज्यादा थी.

जमा देने वाली ठंड में देशरक्षा के लिए मुस्तैदी से खड़ी है भारतीय सेना

गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच गतिरोध आज भी देखने को मिल रहा है और कई दौर की बातचीत होने के बाद भी दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव जारी है, लेकिन भारतीय सेना का मनोबल आज भी उतना ही ऊंचा है, जितना कि पहले था. आज भी खून जमा देने वाली ठंड में सेना बड़ी ही मुस्तैदी के साथ देश की रक्षा के लिए डटी हुई है. गलवान घाटी में हुई उस हिंसक झड़प के बाद दोनों सेनाओं ने टकराव वाले कई स्थानों पर बड़े पैमाने पर जवानों और हथियार समेत साजो-सामान की तैनाती कर दी. भारतीय वायुसेना लद्दाख में राफेल, मिग-29 और सुखोई-30 समेत अपने लड़ाकू विमानों की टुकड़ियों को तैनात कर रही है.

सेलवम होंगे पुडुचेरी विधानसभा अध्यक्ष

पुडुचेरी, (एजेंसी)। केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी के विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए मंगलवार को निर्धारित समय तक केवल भाजपा विधायक आर सेलवम ने नामांकन दाखिल किया है, जिससे उनके निर्विरोध निर्वाचन का मार्ग प्रशस्त हो गया। मानावेली निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि श्री सेलवम के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध निर्वाचन की औपचारिक घोषणा बुधवार को की जाएगी। इस बीच अटकलें थीं कि विधानसभा अध्यक्ष चुनाव के बाद बुधवार की शाम मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, हालांकि उपराज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन को मंत्रियों की सूची अभी सौंपी नहीं गई है।

इजराइल व फिलिस्तीन जंग जैसा माहौल राज्य में बता रहे राज्यपाल धनखड़

टीएमसी ने लगाए आरोप

कोलकाता, (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जारी हिंसा को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ के कड़े व चिंताजनक रुख को लेकर सत्तारूढ़ टीएमसी ने उन पर आरोप लगाया है। मंगलवार को जारी बयान में टीएमसी ने कहा कि राज्यपाल धनखड़ ऐसा बताने का प्रयास कर रहे हैं कि राज्य में इजराइल व फिलिस्तीन युद्ध जैसे हालात हों। वहीं भाजपा नेता मुकुल राय और उनके बेटे सुभ्रांशु के टीएमसी में शामिल होने के बाद केंद्र सरकार ने सुभ्रांशु की सिक्योरिटी हटा ली है। संभावना है कि बहुत जल्द ही मुकुल राय की भी केंद्रीय सुरक्षा हटाई जा सकती है। उधर राज्य में कानून व्यवस्था की कथित तौर पर खराब होती स्थिति को लेकर भाजपा विधायकों द्वारा शिकायत किए जाने के एक दिन बाद के राज्यपाल जगदीप धनखड़ मंगलवार देर रात दिल्ली पहुंचे। राज्यपाल ने ट्वीट किया कि वह राजधानी पहुंचे और 18 जून को कोलकाता लौटेंगे।

राहुल गांधी ने देशवासियों से किया आग्रह, कहा- कोरोना वायरस हमारे बीच है, जल्द लगवाएं वैक्सीन

नई दिल्ली । कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को देशवासियों से सुरक्षा नियमों का पालन करने और कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि जब तक सभी लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, अनलॉकिंग हो रही है लेकिन कोरोना वायरस हमारे बीच है और रहेगा। ऐसे में सुरक्षा नियमों का पालन करते रहें और जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं।

राहुल ने कहा, जब तक सबको टीका नहीं लग जाता, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। अपना ख्याल रखें। राहुल गांधी हर किसी को टीका लगाने में मदद करने के लिए वैक्सीन नीति का आह्वान करते रहे हैं। दूसरी लहर के दौरान कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के बाद दिल्ली और कुछ अन्य राज्यों ने अनलॉक करना शुरू कर दिया है।

संक्रमण कम होने के साथ अनलॉक शुरू

कोरोना संक्रमण कम होने के साथ ही देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजधानी दिल्ली में सोमवार से बाजार, माल और शापिंग कांप्लेक्स पूरी तरह खुलने शुरू हो गए हैं। वहीं, रेस्टोरेंट व सैलून को आधी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, जम्मू, बिहार और दूसरे राज्यों ने भी राहतों की घोषणा की है।

75 दिन बाद कोरोना संक्रमण के सबसे कम मामले दर्ज- देश में संक्रमण की रफ्तार अब धीमी पड़ने लगी है। 75 दिनों बाद संक्रमण के सबसे कम मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 60 हजार 471 नए मामले सामने आए हैं, यह आंकड़ा पिछले 75 दिनों में सबसे कम है। वहीं, इस दौरान 2,726 लोगों की मौत के मामले सामने आए हैं। देश में अब तक वैक्सीन की 25,90,44,072 डोज लग चुकी हैं।

सियासत | सूरजभान सिंह को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया

लोजपा प्रमुख के पद से हटाए गए चिराग पासवान

पटना ■ एजेंसी

लोजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक मंगलवार को संसदीय दल के नेता पशुपति कुमार पारस के आवास पर हुई। बैठक में सर्वसम्मति से चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से मुक्त कर दिया गया। उनकी जगह सूरजभान सिंह को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष को यह निर्देश दिया गया कि वह पांच दिन मे राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाएं। पार्टी पर अपना प्रभाव बनाए रखने की कोशिशों के तहत चिराग पासवान सोमवार को जब दिल्ली में चाचा पशुपति कुमार पारस के घर पहुंचे थे तब वह एक प्रस्ताव लेकर गए थे जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से उनके इस्तीफे की पेशकश के साथ ही उनकी मां रीना पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग शामिल थी। लेकिन अपने चाचा के घर के बंद गेट पर न सिर्फ उन्हें 20 मिनट तक इंतजार कराया बल्कि डेढ़ घंटा इंतजार के बाद भी चाचा से मुलाकात नहीं हो सकी।

पांचों बागी सांसदों को पार्टी से निकाला

चिराग पासवान ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में पांचों सांसदों (पशुपति कुमार पारस, प्रिंस राज, वीणा देवी, चंदन सिंह और महबूब अली कैसर) को लोजपा से हटाने की अनुशंसा कर दी। वहीं पार्टी कार्यालय के बाहर पशुपति कुमार पारस समेत पांचों बागी सांसदों के पोस्टरों पर कालिख पोती। बैठक में यह फैसला भी किया गया कि अगले साल होने वाले चार राज्यों के चुनाव में पार्टी अपना उम्मीदवार देगी। लोजपा नेता राजू तिवारी ने इस संबंध में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और इस बैठक में पांचों सांसदों को पार्टी से हटाए जाने का फैसला लिया गया। चिराग पासवान बुधवार को पार्टी में उठे घमासान की परते खोलेंगे।

चिराग का ट्वीट, पार्टी मां के समान

गौरतलब है कि पार्टी में हुई बगावत को लेकर चिराग पासवान ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। उन्होंने अपने चाचा के नाम के नाम भावुक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि पापा की मौत के बाद आपके व्यवहार से मैं टूट गया। मैं पार्टी और परिवार को साथ रखने में असफल रहा। बता दें कि चिराग एक पुराना पत्र भी ट्विटर पर साझा किया। चिराग पासवान ने ट्वीट में लिखा, पापा की बनाई इस पार्टी और अपने परिवार को साथ रखने के लिए किए मैंने प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। पार्टी मां के समान है और मां के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। पार्टी में आस्था रखने वाले लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं। एक पुराना पत्र साझा करता हूं।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुवाहाटी के राजभवन में राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी से मुलाकात की।

संक्षिप्त समाचार

यूएन में पाकिस्तान को दो-टूक ; सामान्य संबंध चाहता है भारत, अनुकूल माहौल बनाने की जिम्मेदारी पड़ोसी देश की

संयुक्त राष्ट्र । भारत ने कहा है कि वह पाकिस्तान सहित सभी पड़ोसी देशों के साथ सामान्य संबंध चाहता है। साथ में यह भी कहा कि इसके लिए अनुकूल माहौल बनाने की जिम्मेदारी इस्लामाबाद की है। उसे अपने क्षेत्र का किसी भी तरीके से भारत के खिलाफ सीमापार आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर आर मधुसूधन ने शुक्रवार को यह बात 2020 के लिए सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में कही। मधुसूधन ने आगे कहा, भारत, पाकिस्तान सहित सभी पड़ोसी देशों के साथ सामान्य संबंध चाहता है। हम इस बात पर कायम हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी मुद्दे को आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त माहौल में द्विपक्षीय और शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाना चाहिए। इस तरह के अनुकूल माहौल बनाने के लिए पाकिस्तान पर है। उसे अपने क्षेत्र का किसी भी तरीके से भारत के खिलाफ सीमापार आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए। इसके लिए उसे विश्वसनीय और पुष्ट कदम उठाने चाहिए। इससे पहले बोलते हुए, संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने अपनी टिप्पणी के दौरान जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाया। जवाब देते हुए सूधन ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान लगातार ऐसी हरकतें करता है, जो इस मंच के लिहाज से शोभा नहीं देती। अब स्पष्ट हो गया है कि अंतराष्ट्रीय समुदाय को यह प्रतिनिधिमंडल मूर्ख नहीं बना पाएगा। सूधन ने आगे कहा कि पाकिस्तान ने यूएनजीए मंच का फायदा उठाने की कोशिश की और एक बार फिर मेरे देश के आंतरिक मामलों को उठाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख पर भारत की संसद द्वारा लिया गया निर्णय उसका आंतरिक मामला है। भारत ने 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 को हटा दिया था और जम्मू- कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था।

नेपाल में राजनीतिक उठापटक जारी, कार्यवाहक प्रधानमंत्री ओली को एक विपक्षी नेता ने दी जान से मारने की धमकी

काठमांडू । नेपाल में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच विपक्षी नेपाली कांग्रेस के एक विधायक ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को जान से मारने की धमकी दी है। बागमती प्रांत के विधायक नरोत्तम वैद्य ने कैबिनेट के हालिया विस्तार और असंवैधानिक कदमों की आलोचना करते हुए ओली को जान से मारने की धमकी दी। वैद्य ने हवा में हाथ उठाते हुए कहा कि नेपाल के वर्तमान परिदृश्य की बात करें, तो ओली सत्ता में बने रहने और अपनी कुर्सी बचाने के लिए वह शासन के हर पहलू से समझौता कर रहे हैं। अगर हम उन्हें को छोड़ देंगे तो देश का पतन हो जाएगा। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का जिक्र करते हुए, वैद्य ने इस देश को बचाने की अपील की और कहा कि अगर कोई तैयार नहीं है तो वे इस काम को करेंगे। बागमती प्रांत विधानसभा में प्रांतीय विधायक के बयाम की पार्टी के साथ-साथ सीपीएन-यूएमएल (केपी ओली के नेतृत्व वाले गुट) की भी तीखी आलोचना की। नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता बिशोप्रकाश शर्मा ने शुक्रवार देर शाम को वैद्य से अपना बयान वापस लेने को कहा। नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता बिशोप्रकाश शर्मा ने कहा कि चाहे आप रोड पर हो या संसद में किसी को भी अपना विवेक नहीं खोना चाहिए। आपा खोने के बाद दिए गए बयानों को वापस लेना चाहिए और उस पर आत्म-निंदा करना चाहिए। पार्टी इस तरह के बयान देकर की गई गलतियों पर पर्दा नहीं डालेगी।

बता दें कि नेपाल भंग हो चुके संसद (प्रतिनिधि सभा) के स्पीकर ने शुक्रवार को संसद के निचले सदन को भंग करने से जुड़े मुद्दों और देश में राजनीतिक संकट को खत्म करने के लिए एक समाधान खोजने के लिए एक सर्वदलीय बैठक की। द हिमालयन टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, स्पीकर अग्नि प्रसाद सपकोटा द्वारा बुलाई गई बैठक में अधिकांश वरिष्ठ राजनेताओं ने भाग लिया, जिसमें चल रहे राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के उपायों पर चर्चा की गई।

चीन का दावा, अब तक 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगाई कोविड-19 की वैक्सीन

बीजिंग, एजेंसी । चीन ने करीब 60 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का दावा किया है। चीन के एक स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक वो जून के अंत तक देश की करीब 40त्न आबादी को कोरोना वैक्सीन लगाने के टारगेट के तरफ बढ़ रहे हैं। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग (एनएचसी) के अधिकारी कुई गैंग ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि, गुरुवार तक 84.5 करोड़ खुराक प्रशासित किए गए हैं। जिसमें 622 मिलियन लोग शामिल हैं। लेकिन कुई ने साफ तौर पर ये नहीं बताया कि, कितने लोगों को पूरी तरह से टीका लगाया गया था। उधर, चाइना के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के उप निदेशक ज़ेंग यिक्सिन ने बीते दिनों एजेंसी से बातचीत में कहा थी कि, चीन ने साल 2021 के अंत तक अपने टारगेट ग्रुप के करीब 70 फीसद लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। चीन के कोविड-19 टीकाकरण में, सात शॉट्स में से पांच को दो खुराक की आवश्यकता होती है, तो वहीं एक को एक खुराक की आवश्यकता होती है और एक को तीन इंजेक्शन की आवश्यकता होती है। ब्रीफिंग के दौरान चीनी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के शोधकर्ता शाओ यिमिंग ने बताया कि, बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की सिनोफार्म युनिट में बनी कोविड-19 वैक्सीन को चीन में 3 से 17 साल की आयु बच्चों पर इस्तेमाल करने की मंजूरी मिल गई है। साथ ही शाओ ने यह भी कहा कि बीजिंग वांताई बायोलॉजिकल फार्मेसी एंटरप्राइज तथा हांगकांग विश्वविद्यालय और ज़ियामेन विश्वविद्यालय के शोधकर्ता एक और वैक्सीन बना रहे हैं। जिसका लेट स्टेज क्लीनिकल ट्रायल चल रहा है।

संकट में भारत की मदद कर रहा अमेरिका- क्वाड के माध्यम से देश को मिलेगी अतिरिक्त कोरोना वैक्सीन

वाशिंगटन । कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ जंग में भारत अमेरिका का रणनीतिक साझीदार है। और इस लड़ाई में अमेरिका भारत की मदद करने जा रहा है।बाइडन के प्रशासन से अतिरिक्त वैक्सीनों को भारत के साथ साझा करने जा रहा है। इस बीच, अमेरिका की एक वरिष्ठ अधिकारी ने समाचार एजेंसी एएनआइ से बातचीत में कहा कि भारत के साथ हम क्वाड का हिस्सा हैं, जिसके माध्यम से हम भारत में कोरोना वैक्सीन की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए निवेश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को अमेरिका से अतिरिक्त टीके मिलेंगे।
अतिरिक्त वैक्सीनों को भारत से साझा करने की अपील-इससे पहले अमेरिका के वरिष्ठ सांसदों ने कहा था कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के खिलाफ जंग में भारत अमेरिका का रणनीतिक साझीदार है और इस लड़ाई में अमेरिका को भारत की मदद करनी चाहिए। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन से अतिरिक्त वैक्सीनों को भारत के साथ साझा करने का आग्रह किया है। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, भारत में कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद क्वाड देशों (आस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका) के दक्षिणपूर्व एशिया में वर्ष 2022 तक एक अरब कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराने का लक्ष्य अभी भी पटरी पर है। अमेरिका इस महीने के अंत तक आठ करोड़ खुराक उपहार स्वरूप देने की घोषणा पहले ही कर चुका है। इस घोषणा से भारत भी लाभान्वित होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति की घोषणा वाली 50 करोड़ फाइजर वैक्सीन खुराकों में से 20 करोड़ इसी साल 100 देशों को भेजी जाएंगी, जबकि बाकी की 30 करोड़ अगले साल 2022 के मध्य तक दी जाएंगी। ये सभी वैक्सीन खुराक विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुआई में बने कोवैक्स अलायंस के जरिये दी जाएंगी। मानवीय सहायता से जुड़े संगठनों ने जी 7 की इस घोषणा का स्वागत किया है। लेकिन यह भी कहा है कि उन्हें इससे ज्यादा मदद की उम्मीद थी। गरीब देशों को इससे ज्यादा मदद की जरूरत है।

हांगकांग के पास चीन के न्यूक्लियर प्लांट में रेडियोएक्टिव लीकेज! फ्रांस की कंपनी ने दी जानकारी

हांगकांग । चीन में हांगकांग के नजदीक ग्वांगडोंग प्रांत में स्थित ताइशान न्यूक्लियर प्लांट में रेडियोएक्टिव पदार्थ के लीक होने के बाद कुछ समय के लिए वहां पर अफरातफरी का माहौल पैदा हो गया था। इसकी जानकारी इस न्यूक्यिलर प्लांट के ज्वाइंट ऑपरेटर फ्रेंच मल्टीनेशनल इलेक्ट्रिक यूटिलिटी इलेक्ट्रिसिटी डे फ्रांस (फ्रेमोटॉम) ने दी है। इस कंपनी का कहना है कि फिलहाल प्लांट सुरक्षा के दायरे में ही हे और काम कर रहा है। गौरतलब है कि इस प्लांअ को चीन की कंपनी जनरल न्यूक्यिल पावर ग्रुप फ्रांस की कंपनी के साथ मिलकर ऑपरेट करता है। प्लांट में लीकेज की खबर आने के बाद प्लांट के डाटा की समीक्षा के लिए दोनों ही कंपनियों ने एक साझा बैठक भी की थी।

फ्रेमोटॉम से जारी एक बयान में कहा गया है कि कंपनी पर प्लांट की परफोर्मेंस की जिम्मेदारी है। इसमें ये भी कहा गया है कि कंपनी के विशेषज्ञ हालात का जायजा लेने में लगे हुए हैं। वो इस बात को भी तलाश रहे हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। हांगकांग से करीब 135 किमी दूर स्थित इस प्लांट में रेडिएशन लेवल को फिलहाल सही पाया गया है। इसकी जानकारी हांगकांग ऑब्जरवेटरी ने दी है जिसके पास इसके आस पास के शहरों का रेडिएशन लेवल नापने की जिम्मेदारी है।

सीएनएन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सोमवार को फ्रेमोटॉम ने अमेरिकी ऊर्जा विभाग को रेडियोएक्टिव लीकेज के खतरे की चेतावनी दी थी। साथ ही उसने चीन पर आरोप लगाया था कि वो इस प्लांट के बाहर क्षमता से अधिक रेडियोएक्टिव पदार्थ बाहर डाला जा रहा है जिससे इस प्लांट को बंद करने से रोका जा सके। सीएनएन ने अपनी रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि अमेरिकी अधिकारियों को लगता है कि मौजूदा हालातों में प्लांट की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। फ्रांस की कंपनी ने अपने एक बयान में ये भी कहा है कि उसको बताया गया है कि रिएक्टर वन के पास कुछ बेहद दुलर्भ गैसों का लेवल लगातार बढ़ रहा है। कंपनी का ये भी कहना है कि विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर उसने चीन से इस बात की अपील की है कि फिलहाल इस प्लांट को होल्ड पर डाल देना चाहिए।

दूसरी तरफ इस प्लांट में लीकेज की खबर आने के बाद अमेरिका भी इसके अध्ययन में जुट गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अमेरिका ने इस लीकेज की रिपोर्ट का आकलन करने में पूरा एक सप्ताह लगाया है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि फ्रांस की पावर कंपनी ने ही यहां पर रेडियोएक्टिव लीकेज की आशंका को देखते हुए खतरे की चेतावनी दी थी। इस मुद्दे पर सुरक्षा परिषद में भी बैठकों का दौर चला है। इसकी वजह यही है कि इसको संचालित करने वाली दोनों ही कंपनियां अलग-अलग बात कह रही हैं। आपको यहां पर ये भी बता दें कि हाल के कुछ वर्षों में चीन ने देश में परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाया है। देश में इस्तेमाल होने वाली करीब पांच फीसद बिजली का उत्पादन न्यूक्यिलर प्लांट के जरिए ही किया जा रहा है। वर्तमान समय में कई न्यूक्यिलर प्लांट देश में काम कर रहे हैं। गोरतल है कि चीन ने वर्ष 2009 में फ्रांस की कंपनी ईडीएफ (ईडीएफपीए) के साथ मिलकर ताइशन प्लांट का निर्माण शुरू किया था। यहां पर वर्ष 2018 और 2019 में बिजली का उत्पादन शुरू किया गया था।

वैक्सीन लगने के बाद भी डेल्टा वैरिएंट के चपेट में हवाई का एक शख्स, अमेरिका में डेल्टा वैरिएंट के 6 फीसद मामले

होनोलुलु । पिछले माह नेवादा गए ओआहु निवासी कोविड-19 के डेल्टा वैरिएंट से संक्रमित पाया गया है जबकि यह शख्स कोरोना वैक्सीन की खुराक ले चुका था। यह जानकारी हवाई की ओर से दी गई। बता दें कि इस घातक कोरोना वायरस के डेल्टा वैरिएंट से संक्रमण का पहला मामला भारत में आया था जो काफी संक्रामक है। अमेरिका में अभी कोरोना वायरस के इस वैरिएंट से संक्रमण के 6 फीसद मामले हैं। हवाई के हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर लिब्बी चार ने बताया कि इस मामले में कोविड-19 वैक्सीन संक्रमण को रोक नहीं पा रहा। हालांकि ब्रिटेन में शोधकर्ताओं का कहना है कि वहां डेल्टा वैरिएंट को रोकने में फाइजर वैक्सीन 96 फीसद असरदार है।

वर्ष 2019 के अंत में कोरोना वायरस संक्रमण का पहला मामला चीन के वुहान में आया था जिसके बाद दो-तीन माह के भीतर ही यह पूरी दुनिया में महामारी के रूप में फैल गया। 11 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे महामारी घोषित कर दिया था। अमेरिका की जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के अनुसार मंगलवार सुबह तक वैश्विक संक्रमण का आंकड़ा 176,195,220 हो गया और कुल मृतकों की संख्या 3,808,883 हो गई। महामारी की पहली लहर से लेकर अब तक दुनिया भर में सबसे बदतर हाल अमेरिका का रहा है। अभी तक यहां के कुल संक्रमितों का आंकड़ा 33,473,180 हो गया और 599,928 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। यहां अब तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा 29,510,410 हो चुका है।

पाक राष्ट्रपति बोले- कश्मीर पर इमरान खान का बयान यू-टर्न नहीं

इस्लामाबाद । पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने सोमवार को कहा कि कश्मीर पर प्रधानमंत्री इमरान खान का बदला बयान यू-टर्न नहीं है। खान बदलते हालात को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इमरान खान ने पिछले महीने कहा था कि कश्मीर में पहले जैसी स्थिति बहाल होने तक भारत के साथ संबंधों को सामान्य बनाना कश्मीर के लोगों के साथ विश्वासघात होगा। वहीं, इस महीने के शुरू में एक विदेशी समाचार न्यूज एजेंसी के साथ बातचीत में इमरान खान ने कहा कि अगर भारत कश्मीर को उसका पहले वाला दर्जा बहाल करने का खाका पेश करता है तो पाकिस्तान उसके साथ बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है। इमरान खान के बयान का बचाव करते हुए अल्वी ने डान न्यूज टीवी के से कहा कि प्रधानमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अफगानिस्तान और नए अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों को देखते हुए हालात को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तात्कालिक तौर पर पाकिस्तान यही चाहता है कि जम्मू कश्मीर का राय का दर्जा बहाल किया जाए। बता दें कि भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को रायसभा में एक ऐतिहासिक जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पेश किया

किसने दी है यूरोप को चीन से सुरक्षा की गारंटी और किसने कहा ड्रैगन को मिलकर जवाब देने की जरूरत

वाशिंगटन । उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) ने चीन को एक गंभीर चुनौती बताया है। ब्रसेल्स में नाटो के हैडक्वार्टर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है कि यूरोप की सुरक्षा उसकी एक अहम जिम्मेदारी है। उन्होंने चीन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उससे यूरोप को डरने की जरूरत नहीं है, अमेरिका उनके साथ मौजूद है। अमेरिका के रहते यूरोप का कोई कुछ नहीं कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि नाटो हम सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बयान इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि ये पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस नीति के विपरीत है जिसमें उन्होंने यूरोप की सुरक्षा की जिम्मेदारी न लेने की बात कही थी। उन्होंने अपने कार्यकाल में साफ कर दिया था कि अमेरिका बिना किसी फायदे को दुनिया का रखवाला नहीं बन सकता है। ट्रंप ने यूरोप को उसकी सुरक्षा से पीछे हटने तक की चेतावनी दे दी थी। इसके उलट राष्ट्रपति बाइडन ने यूरोप को एक बार फिर से उसकी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त किया है। उनके इस बयान का यूरोपीय देशों ने स्वागत किया है। नाटो सम्मेलन में बाइडन ने न सिर्फ चीन को चेतावनी दी बल्कि रूस भी उनके संबोधन का एक केंद्र बिंदु रहा। उन्होंने कहा कि रूस और चीन दोनों ने ही अपने रास्ते बदल लिए हैं। अब वो उस रास्ते पर नहीं है जैसी उनसे कल्पना की गई थी।

पहले दुनिया ये मानती थी कि वो उदारवादी लोकतंत्र की राह पकड़ेंगे जिससे दुनिया को उनसे खतरा कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीते कई वर्षों में लगातार बरतने के बाद भी चीन चीन अमेरिका का अच्छा सहयोगी नहीं बन सका। यही वजह है कि नाटो के सहयोगियों ने उसको लगातार साजिश रचने वाला देश बताया है।

इस मौके पर नाटो के महासचिव जेंस स्टॉटेनबर्ग ने कहा कि चीन लगातार अपनी सैन्य मौजूदगी में इजाफा कर रहा है। उसने बाल्टिक सागर से लेकर अफ्रीका तक अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि चीन की नीतियों के प्रति नाटो पूरी तरह से सजग और चौकन्ना रहे। उन्होंने कहा कि चीन लगातार अमेरिका के नजदीक आ रहा है। धरती ही नहीं चीन अंतरिक्ष में भी अमेरिका की बराबरी करने की इच्छा रखता है। वो लगातार अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़ा निवेश कर रहा है और अमेरिका का बड़ा प्रतिद्वंदी बन रहा है।

इतना ही नहीं वो लगातार दूरसंचार और बंदरगाहों के विकास में लगा हुआ है। ये सभी ऐसे रणनीतिक क्षेत्र हैं जिनसे अमेरिका को सतर्क रहने की जरूरत है। इतना ही नहीं हमें साथ मिलकर चीन को जवाब देना होगा।

जेंस ने रूसी सेनाओं के यूक्रेन के पास जमावड़े पर भी गहरी चिंता जताई है। इस मौके पर मौजूद जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति का यहां आना एक नए चेप्टर की शुरुआत है। इस सम्मेलन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी शामिल हुए थे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि चीन के साथ संबंधों को रखना जहां फायदे का सौदा है वहीं इसमें खतरा भी अधिक है। सभी देशों को उससे संबंध बनाने के समय हर परिस्थिति पर विचार करना जरूरी है। गौरतलब है कि अमेरिकी नेतृत्व वाले नाटो में 30 देश शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति नाटो सम्मेलन से इतर तुर्की के राष्ट्रपति रैसेप तैयप इर्दोगन से भी मिले। नाटो का अगला सम्मेलन 2022 में स्पेन में होगा।

डेल्टा वैरिएंट ने बढ़ाई ब्रिटेन के पीएम की चिंता, चार सप्ताह बाद मिल सकती है प्रतिबंधों में पूरी छूट

लंदन । ब्रिटेन में डेल्टा वैरिएंट के खतरे और लगातार बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने फिलहाल लॉकडाउन के तहत लगे प्रतिबंधों में ढिलाई देने के विचार को 19 जुलाई तक के लिए टाल दिया है। आपको बता दें कि ब्रिटेन में कुछ दिनों से लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और इनमें करीब साठ फीसद मामले डेल्टा वैरिएंट के ही हैं। गौरतलब है कि डेल्टा वैरिएंट का पता सबसे पहले भारत में ही चला था इसके बाद पूरी दुनिया के करीब साठ से अधिक देशों में अब तक इसके मामले सामने आ चुके हैं। विशेषज्ञ और कई देशों की सरकार इसको लेकर चिंता में हैं और इसको पहले के मुकाबले अधिक घातक बता रही हैं।

ब्रिटेन में भी वैज्ञानिकों ने सरकार को सलाह और चेतावनी दी है कि यदि प्रतिबंधों में किसी भी किस्म की ढिलाई दी गई तो स्थिति काफी खराब हो सकती है। विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि ऐसा करने पर अधिक संख्या में लोगों का अस्पताल आना हो सकता है। जानकारों को इस बात की भी आशंका है कि डेल्टा वैरिएंट का खतरा अधिक होने के चलते आने वाले दिनों में अधिक मरीज सामने आ सकते हैं। सरकार ने विशेषज्ञों की सलाह को मानते हुए फिलहाल प्रतिबंधों में ढील देने से इनकार कर दिया है। प्रधानमंत्री जॉनसन का कहना है कि ये ठीक होगा कि हम कुछ दिन और इंतजार करें। उन्होंने इस बात की भी उम्मीद जताई है कि 19 जुलाई से ब्रिटेन में सब कुछ सामान्य हो जाएगा और प्रतिबंधों को आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं होगी।

ब्रिटेन के पीएम के मुताबिक देश में 40 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वैक्सीन की दूसरी खुराक देने का काम जोरों पर है। सरकार ने अब तक अधिकतर लोगों को वायरस के प्रति सुरक्षा मुहैया करवाई है और अधिक से अधिक उन्हें सुरक्षा देने पर काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों को हटाने के लिए जो एक महीने का समय बढ़ाया गया है कि उससे सरकार को कुछ वक्त भी ज्यादा मिल गया है, हालांकि ये समय काफी संवेदनशील होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि डेल्टा वैरिएंट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसकी वजह से संक्रमण की रफ्तार में तेजी आई है। इतना ही नहीं इसके चलते मामले दोगुना हो गए हैं। इसकी वजह से देश के कुछ इलाके बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। हमें इसके साथ रहते हुए जीना सीखना होगा। वैक्सीन से खतरे को कम किया जा सकता है।

गौरतलब है कि ब्रिटेन में रविवार को 7490 नए मामले सामने आए थे। इसके अलावा आठ मरीजों ने देश में दम तोड़ दिया था। वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाने और प्रतिबंधो को फिलहाल टालने की अपील की थी। सरकार के वरिष्ठ सूत्रों का कहना है कि ये वैक्सीन और वायरस के बीच एक रेस है और देखना होगा कि इसमें किसकी जीत होती है। डेली टेलीग्राफ ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि देश के वरिष्ठ वैज्ञानिकों और विशेषज्ञो के अलावा कैबिनेट के साथ पीएम बोरिस जॉनसन ने एक बैठक की थी जिसमें इन सभी ने पीएम को फ्रीडम डे को टालने के लिए सलाह दी थी। इसमें विशेषज्ञों ने ताजा आंकड़े भी सरकार के समक्ष रखे थे। प्रतिबंधों से ढिलाई के फैसले को टालने के प्रस्ताव को अब सरकार को हाउस ऑफ कॉमन से पारित करवाना होगा। ये पीएम की पार्टी के लिए कुछ मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि कुछ सदस्य चाहते हैं कि प्रतिबंधों को कुछ समय के लिए हटाया जाए क्योंकि काफी लंबा समय गुजर चुका है।

कोरोना के मूल के करीब पहुंच गया था ट्रंप प्रशासन, वुहान लैब से हुआ था लिक, माइक पोंपियो का बड़ा दावा

वाशिंगटन । अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोंपियो ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन कोरोना संक्रमण की उत्पत्ति के विवरण को उजागर करने के करीब पहुंच गया था और उसके पास इसको लेकर बहुत यादा सुबूत थे। उन्होंने एक बार फिर यह बात कही कि कोरोना वायरस चीन के वुहान स्थित लैब से ही लीक हुआ है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में विदेश मंत्री रहे पोंपियो ने फाक्स न्यूज के साथ बातचीत में कहा कि उन लोगों को अच्छी तरह से पता था कि वुहान में क्या हुआ।

वुहान इंस्टीट्यूट आफ वायरोलोजी से कोरोना वायरस के लीक होने के संबंध में बहुत साक्ष्य हैं। हमने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर बहुत दबाव बनाया था। कोरोना वायरस के मूल का पता लगाने को लेकर ट्रंप प्रशासन गंभीर था और यह स्पष्ट कर दिया था कि चीन सरकार को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

वायरस के वुहान लैब से लीक होने को लेकर बढ़ रही विश्वसनीयता के बीच पिछले हफ्ते विश्व स्वास्थ्य संगठन के सलाहकार बोर्ड के सदस्य जेमी मेटजल ने फाक्स न्यूज को बताया था कि चीन का लीपापोती अभियान भी जोरों पर चल रहा है। चीनी प्रशासन नमूनों को नष्ट कर रहा है और रिकार्ड को छिपाने में लगा हुआ है। इस बीच, पोंपियो के उत्तराधिकारी एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि डब्ल्यूएचओ का कोरोना महामारी की उत्पत्ति पर अध्ययन का पहला चरण काफी अधूरा है। उन्होंने कहा कि सात देशों (जी 7) देशों के नेता चीन पर डब्ल्यूएचओ के अध्ययन के दूसरे चरण में सहयोग करने के लिए दबाव बनाएंगे।

तालिबान से शांति वार्ता में आई रुकावट के लिए पाकिस्तान नहीं लेगा कोई जिम्मेदारी, कुरैशी ने अफगानिस्तान नेतृत्व पर उठाए सवाल

इस्लामाबाद । अफगानिस्तान शांति वार्ता में आई रुकावट और बढ़ते तालिबानी हमलों के मद्देनजर पाकिस्तान ने ये साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी इसके लिए नहीं लेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने पाक-अफगान डायलॉग के दौरान वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि पाकिस्तान पर अफगानिस्तान में शांति वार्ता में बाधा पहुंचाने या उसको खराब करने का आरोप लगाएगा तो पाकिस्तान कभी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा।

आपको बता दें कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी जल्द ही अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरे में उनके साथ उनके करीबी लोग शामिल होंगे।

ये वार्ता अफगानिस्तान शांति वार्ता के लिए काफी अहम मानी जा रही है। इस वार्ता से पहले ही कुरैशी ने राष्ट्रपति गनी को इस दौरे की शुभकामनाएं देते हुए ये भी कहा कि वो इस बात को पहले ही बता देना चाहते हैं कि यदि इस वार्ता के दौरान अमेरिका ने पूरी प्रक्रिया के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया या उस पर इसकी जिम्मेदारी थोपने की कोशिश की तो पाकिस्तान किसी भी तरह की कोई मदद नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी हम सभी की है। इसमें यदि कुछ भी गलत होता है तो इसके लिए सिर्फ पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। हम कोई जिम्मेदारी इसके लिए नहीं लेंगे। पाक-अफगान डॉयलॉग में उन्होंने कहा कि अफगान शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान पूरी तरह से ईमानदार और गंभीर है। अब पाकिस्तान पर आरोप लगाने बंद होने चाहिए, ये बहुत हो चुका है।

पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने इस संवाद में अफगान शांति वार्ता के टूटने या रुकने का ठीकरा इशारों ही इशारों में अफगानिस्तान पर ही फोड़ दिया है। उनका कहना है कि अफगानिस्तान को ये तय करना था कि वो कैसे देश को आगे ले जा सकते हैं इसके लिए उसको ही लोगों का चयन भी करना था। अफगानिस्तान को एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो तालिबान से सफलतापूर्वक बात कर उसे किसी अंजाम तक ले जा सके और देश में शांति बहाल कर सके, न कि सत्ता में बने रहने के लिए चिंतित होता रहे। कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का सहयोगी बनना चाहता है और साथ ही वो अमेरिका के साथ आतंकवाद के खिलाफ सहयोग भी देना चाहता है।

भारत की मदद के नाम पर पाकिस्तानी एनजीओ ने जुटाया 158 करोड़ चंदा, टेरर फंडिंग में इस्तेमाल की आशंका

वाशिंगटन । कोरोना महामारी में भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित पाकिस्तान से जुड़े चैरिटी संगठनों ने कोविड संकट में भारत की मदद करने के नाम पर काफी चंदा इकट्ठा किया है। इसमें कहा गया है कि दान किए गए लाखों डॉलर का उपयोग विरोधों को भड़काने और एकमुश्त आतंकी हमलों को प्रायोजित करने के लिए किए जाने की संभावना है।

डिसइन्फो लैब ने कोविड-19 स्कैम 2021 का खुलासा किया। रिपोर्ट में इसे मानवीय सहायता के नाम पर किए गए इतिहास के सबसे बुरे घोटालों में से बताया गया है, क्योंकि हेल्पिंग इंडिया ब्रीद के नाम पर लाखों डॉलर की चोरी की गई है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहे भारत को दुनिया भर से मदद मिली। हालांकि, कुछ संगठनों ने दान के नाम पर अवैध रूप से धन इकट्ठा करने के लिए संकट का उपयोग किया।

डिसइन्फो लैब ने कई एसे चैरिटी संगठनों का पर्दाफाश किया, जो भारत के नाम का फायदा उठाकर धन जुटाने में कामयाब रहे। इन संगठनों के कट्टरपंथी इस्लामवादियों और आतंकवादी संगठनों के साथ घनिष्ठ संबंध हैं और इन्हें पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर चलाया जा रहा है।

ऐसा ही एक इस्लामिक संगठन है उत्तरी अमेरिका का आईएमएएनए-इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन नॉर्थ अमेरिका, जिसने कोरोना संकट में भारत की मदद के बहाने दुनिया भर के लोगों द्वारा दान किया गया दसियों करोड़ का फंड चोरी किया। आईएमएएनए इलिनोइस-आधारित चिकित्सा राहत संगठन है, जिसे औपचारिक रूप से 1967 में इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के रूप में स्थापित किया गया था और बाद में इसका नाम बदलकर आईएमएएनए कर दिया गया। कई अन्य संगठनों के विपरीत, आईएमएएनए कोविड संकट के दौरान अपने हाल के चैरिटी अभियान में अपारदर्शी था और इसने जिस तरह से करोड़ों रुपये एकत्र किया, उसके बारे में बेहद कम जानकारी दी है। आईएमएएनए के वर्तमान अध्यक्ष डॉ इस्माइल मेहर ने 27 अप्रैल, 2021 को इंस्टाग्राम पर #HelpIndiaBreathe अभियान शुरू किया था और 1.8 करोड़ का शुरुआती लक्ष्य रखा था। यहां आपको बता दें कि आईएमएएनए का न तो भारत में कोई कार्यालय है और ना ही कोई प्रतिनिधि। डिसइन्फो लैब की रिपोर्ट के अनुसार, आईएमएएनए को कम समय में भारी मात्रा में धन प्राप्त हुआ और तयकिए गए लक्ष्य के पूरा होते ही लक्ष्य राशि को बार-बार संशोधित भी किया गया। डिसइन्फो लैब की गणना के अनुसार, इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन को कुल राशि 30 करोड़ रुपये से 158 करोड़ रुपये के बीच दान प्रप्त हुआ है।

गरीबों को राशन देने के नाम पर आप सरकार ने किया 250 करोड़ का घोटाला: बीजेपी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। राजधानी में गरीबों के लिए खरीदे गए हजारों टन अनाज के सड़ने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। इसे लेकर 250 करोड़ रुपये के राशन घोटाले का आरोप झेल रही आम आदमी पार्टी सरकार पर अब शराब माफिया के इशारे पर यह अनाज सड़ाने का गंभीर आरोप लगा है। इसके साथ ही मामले को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन भी बताया जा रहा है। इसे लेकर उपराज्यपाल से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) को जांच सौंपने की मांग की जा रही है।

दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी ने रविवार को कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है, जिसकी जांच होनी चाहिए। भाजपा के इस सनसनीखेज आरोप पर आप से प्रतिक्रिया लेने का प्रयास किया गया, लेकिन पार्टी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। बिधूड़ी के नेतृत्व में भाजपा विधायकों, जिला भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सिरसपुर के दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (डीएससीएससी) के गोदाम के बाहर रविवार को प्रदर्शन किया, जहां सैकड़ों टन सड़ा हुआ अनाज पड़ा है। रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि कोरोना काल में हुए सैकड़ों टन राशन के घोटाले के लिए दिल्ली की सरकार ही दोषी है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी केजरीवाल सरकार ने गरीबों तक राशन नहीं पहुंचाया। बिधूड़ी का दावा है कि उन्हें दिल्ली सरकार के एक बड़े अफसर ने बताया है कि इस राशन का इस्तेमाल अब शराब बनाने के अलावा और किसी काम में नहीं हो सकता। बिधूड़ी का आरोप है कि राशन माफिया के इशारे पर ही दिल्ली सरकार ने गरीबों को बांटने के नाम पर राशन खरीदा और फिर स्कूलों में रखवाकर इसे सड़ा दिया, ताकि इसे शराब माफिया को देकर मोटी रकम वसूली जा सके। आवारा जानवरों को भी नहीं खिलाया जा सकता सड़ा अनाज-बिधूड़ी ने कहा कि अब यह अनाज जानवरों को भी नहीं खिलाया जा सकता। उपराज्यपाल से मांग है कि मामले की जांच सीबीआइ से करवाई जाए। अनाज सड़ने का ताजा मामला उत्तर-पश्चिमी दिल्ली जिले का है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली के स्कूलों में एक वर्ष से सड़ रहे सैकड़ों टन अनाज का मुद्दा जब भाजपा सांसदों व विधायकों ने उपराज्यपाल के समक्ष उठाया तो केजरीवाल सरकार ने मामले को रफा-दफा करने के लिए वहां से राशन उठाकर गोदाम में रखवा दिया। ऐसे सामने आया मामला पिछले लाकडाउन के दौरान बिना राशन कार्ड वाले गरीब परिवारों को बांटने के लिए दिल्ली सरकार ने राशन की खरीदारी की थी। भाजपा का दावा है कि यह 250 करोड़ रुपये से दिल्ली सरकार ने हजारों टन राशन की खरीदारी की थी, लेकिन यह राशन गरीबों में नहीं बांटा गया और स्कूलों में पड़े-पड़े सड़ गया। दरअसल, 28 मई को वसंत कुंज वार्ड के मसूदपुर स्थित निगम स्कूल में सबसे पहले सैकड़ों टन अनाज सड़ने का मामला सामने आया था।

सके बाद भाजपा नेताओं ने स्कूलों का दौरा शुरू किया तो अनाज की बर्बादी की परतें खुलती चली गई। दक्षिणी दिल्ली के खानपुर, बदरपुर, महरौली, मोलड़बंद, श्रीनिवासपुरी, कालकाजी व गोविंदपुरी आदि इलाकों के स्कूलों में हजारों टन सड़ा हुआ अनाज मिला। वहीं, पूर्वी दिल्ली के घोंडा विधानसभा के तीन स्कूलों के अलावा बाहरी दिल्ली में भी अनाज सड़ने का मामला सामने आ चुका है। सांसद रमेश बिधूड़ी का दावा है कि अब तक करीब 20 हजार टन सड़ा हुआ अनाज स्कूलों में मिल चुका है।

उपराज्यपाल दे चुके हैं मुख्य सचिव को जांच के आदेश स्कूलों में जब जगह-जगह सड़ा हुआ अनाज मिला तो राजनीतिक दल भी इसे लेकर मुखर होने लगे। इसके बाद दिल्ली भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और रोहिणी के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने इस मामले की शिकायत उपराज्यपाल अनिल बैजल से की थी। इस पर नौ जून को बैजल ने अनाज की बर्बादी पर कार्रवाई करने के लिए दिल्ली के मुख्य सचिव को आदेश दिए थे।

दिल्ली सरकार से सब्सिडी प्राप्त कर कोई भी शख्स लगा सकता है ईवी चार्जर

नई दिल्ली । चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए गठित कार्य समूह ने सोमवार को चौथी बैठक की। इस बैठक में दिल्ली में निजी और अर्ध-सार्वजनिक स्थानों पर ईवी चार्जर की त्वरित स्थापना के लिए नवीन सिंगल विंडो प्रक्रिया को मंजूरी दी गई। बैठक की अध्यक्षता दिल्ली सरकार के संवाद एवं विकास आयोग के उपाध्यक्ष जस्मिन शाह ने की। इसमें कार्यदल के सदस्यों के अलावा भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार ने भी भाग लिया। जस्मिन शाह ने बताया कि इस व्यवस्था के तहत अपार्टमेंट, ग्रुप हाउसिंग सोसायटी, अस्पताल और वाणिज्यिक जैसे संस्थागत भवनों के परिसर में चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के स्विच दिल्ली अभियान के बाद अनुरोध प्राप्त हुए थे, जिसके चलते नवीन सिंगल विंडो प्रक्रिया को मंजूरी देने का निर्णय लिया गया है। विशेष रूप से अपार्टमेंट, सोसायटियों, आरडब्ल्यूए, माल मालिकों ने अनुरोध किया था कि वे ईवी चार्जर स्थापित करना चाहते हैं। जस्मिन शाह ने कहा कि कोई भी व्यक्ति सरकार से सब्सिडी प्राप्त कर ईवी चार्जर लगा सकता है।

बता दें कि दिल्ली सरकार ने कुछ महीने पहले स्विच दिल्ली अभियान शुरू करते हुए कहा था कि 6 महीने के भीतर सरकार के बेडे में सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन ही होंगे। बता दें कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार कई योजनाएं चला रही है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दावा किया था कि सरकारी वाहनों के बेडे को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बेडे में तब्दील करने वाली दिल्ली सरकार भारत ही नहीं दुनिया की पहली सरकार बन गई है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने पिछले साल अगस्त में इलेक्ट्रिक वाहन नीति शुरू की थी.

संक्षिप्त खबर

नोएडा में आधी रात स्वीमिंग पूल का नजारा देख चौंकी पुलिस, चल रही थी शराब पार्टी; 15 युवतियों समेत 61 लोग गिरफ्तार

नोएडा । एक्सप्रेस-वे पुलिस ने रविवार रात नोएडा सेक्टर-135 स्थित एक फार्म हाउस में पूल व शराब पार्टी कर रही 15 युवतियों समेत 61 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि सभी युवक-युवतियों कोविड-19 की गाइडलाइन के नियमों का उल्लंघन करते हुए पूल व शराब पार्टी कर रहे थे। आरोपितों के खिलाफ लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने के तहत कार्रवाई की गई है। एडिशनल डीसीपी नोएडा रणविजय सिंह ने बताया कि रविवार शाम डूब क्षेत्र के सेक्टर-135 स्थित चौधरी फार्म हाउस में कुछ लोगों द्वारा पूल पार्टी किए जाने की सूचना मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पार्टी कर रही 15 युवती और 46 युवकों को गिरफ्तार किया है। मौके से शराब व बियर की बोतलें मिली हैं। आरोपित कोविड-19 नियमों का उल्लंघन कर पार्टी करते हुए स्वीमिंग पूल में नहा रहे थे। बिना मास्क लगाए झुंड बनाकर इधर-उधर खुले में थूक रहे थे। फार्म हाउस में शराब व बियर की बोतलें भी मिली हैं। सभी आरोपित दिल्ली, ग्रेटर नोएडा व नोएडा के अलग-अलग इलाकों के रहने वाले हैं। अधिकतर आरोपितों में कुछ छात्र हैं और कुछ निजी कंपनियों में नौकरी करते हैं। फार्म हाउस में पकड़ी गए युवक व युवतियां आपस में दोस्त हैं।

वहीं कोतवाली प्रभारी यतेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपित पूल व शराब पार्टी के लिए सेक्टर-135 स्थित फार्म हाउस को आनलाइन बुक किया था। जिसके लिए 20 हजार रुपये भी आनलाइन दिया गया था। फार्म हाउस का संचालक धर्मवीर है। गिरफ्तार आरोपित में साथ सात लोग वह जिन्होंने पार्टी आयोजित करवाने में मदद की थी। इन आरोपितों के खिलाफ महामारी अधिनियम के साथ गैर कानूनी तरीके से शराब परोसने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं बाकी के खिलाफ महमामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।

पहले भी सामने आ चुके हैं रेव सहित अन्य पार्टी के मामले-जिले में रेव सहित अन्य पार्टी के पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। एक्सप्रेस-वे कोतवाली क्षेत्र में ऐसे तो कई बार रेव पार्टी और पूल पार्टी के मामले सामने आ चुके हैं। अवैध रूप से संचालित फार्म हाउस में बिना अनुमति पार्टी की जाती है। पिछले एक सप्ताह में कोरोना कर्फ्यू में छूट मिलते ही लोगों ने कोविड-19 से बचाव की गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए पार्टी शुरू कर दी है। इसके लिए आनलाइन बुकिंग की जाती है।

इंस्टाग्राम ने हिंदू देवी देवताओं का किया अभद्र चित्रण और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

नई दिल्ली । इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम पर हिंदू-देवी देवताओं से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री को हटाने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता जी तुषार राव व आयुष सक्सेना के माध्यम से दायर याचिका में आदित्य सिंह देशवाल ने कहा कि इंस्टाग्राम ने हिंदू देवी देवताओं का अभद्र चित्रण किया और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इसके इलावा याचिका में दावा किया गया कि इंस्टाग्राम नए आइटी नियमों का अनुपालन नहीं कर रहा है। याचिका पर सुनवाई के दौरान इंस्टाग्राम की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ को बताया कि इंस्टाग्राम से आपत्तिजनक सामग्री को हटा दिया गया है। वहीं, डिजिटल मीडिया पर लागू नई नीति के अनुपालन की मांग पर पीठ ने फेसबुक व इंस्टाग्राम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। इस दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से मांग की गई कि कार्रवाई नए नियमों के तहत की जाए और आपत्तिजनक सामग्री संरक्षित रखने का निर्देश दिया जाये, ताकि बाद में अदालती कार्यवाही में इसका उपयोग किया जा सके। नई नीति के अनुपालन पर इंस्टाग्राम की तरफ से जवाब दिया कि नई नीति के तहत फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए एक शिकायत अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। इस पर याची ने दलील दी कि दोनों मीडिया प्लेटफार्म के लाखों उपयोगकर्ताओं की शिकायत सुनने के लिए एक ही अधिकारी पर्याप्त नहीं है।

थाने का सिपाही व निगमकर्मी लॉकडाउन के दौरान किराया देने के लिए बना रहे थे दबाव, युवक ने कर लिया सुसाइड

नई दिल्ली । कालिंदी कुंज थाना क्षेत्र में लाकडाउन के दौरान मकान का किराया देने का दबाव बनाने पर एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके से चार पेज का सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें मकान मालिक और कालिंदी कुंज थाने में तैनात एक पुलिसकर्मी व निगमकर्मी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कालिंदी कुंज थाना पुलिस ने केस दर्ज कर मकान मालिक बालाजी को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि पुलिसकर्मी और नगर निगमकर्मी के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार, करण सिंह अपने परिवार के साथ कालिंदी कुंज के खादर इलाके में रहता था और मुर्गा बेचता था, जबकि उसके माता-पिता सब्जी बेचते हैं। रविवार को करण ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने करण के शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की। प्राथमिक जांच के दौरान पुलिस को करण के कमरे से एक चार पेज का सुसाइड नोट मिला। जिसमें मकान मालिक पर किराये के लिए दबाव बनाने व कालिंदी कुंज थाने में तैनात एक पुलिसकर्मी व नगर निगम कर्मी पर पैसे मांगने की बात लिखी थी। सुसाइड नोट में लिखा है कि मकान मालिक बालाजी घर आकर किराया मांगता था और गाली गलौज व मारपीट करता था, जबकि पुलिसकर्मी खान ने लाकडाउन के दौरान उन्हें दुकान नहीं लगाने दी। दुकान लगाने के लिए पहले पुलिसकर्मी और निगमकर्मी तीन हजार रुपये लेते थे, लेकिन लाकडाउन के बाद दुकान खोलने के लिए 28 हजार रुपये की मांग की। पैसे नहीं देने पर दुकान नहीं खोलने दी।

6 वीं और 9 वीं क्लास में एडमिशन प्रक्रिया शुरू, उम्र सीमा में मिली छह माह की छूट

नई दिल्ली । दिल्ली के सरकारी स्कूलों में छठीं से नौवीं में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा निदेशालय ने सत्र 2021-22 में दाखिले के लिए उम्र सीमा में छह माह की छूट दी है। ये छूट सामान्य श्रेणी के छात्रों को अधिकतम और न्यूनतम उम्र सीमा दोनों में मिलेगी। वहीं, दिव्यांग श्रेणी के छात्रों को अधिकतम उम्र सीमा में चार साल और न्यूनतम उम्र सीमा में छह माह की छूट मिलेगी।

निदेशालय के मुताबिक ये छूट प्रधानाचार्य के स्तर पर ही दी जाएगी। ऐसे में अभिभावकों को स्कूल के प्रधानाचार्य से ही उम्र सीमा में छूट को लेकर संपर्क करना होगा। पहले चरण में दाखिले के लिए 30 जून तक आनलाइन माध्यम से पंजीकरण करा सकेंगे।

गलत दिशा में तेज रफ्तार से जा रही बीएमडब्ल्यू ने आटो में मारी जबरदस्त टक्कर, ड्राइवर की मौत

नई दिल्ली । मोती नगर थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह गलत दिशा में तेज रफ्तार से चल रही बीएमडब्ल्यू (एक्स 1 माडल) कार ने सामने से आ रही आटो में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबर्दस्त थी कि आटो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद कार चालक ने अपने दोस्तों के साथ घायल आटो चालक को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपित चालक को गिरफ्तार कर लिया। मृतक का नाम बिंदेश्वरी महतो है। वह त्रिलोकपुरी इलाके में अपने परिवार के साथ रहते थे।

पुलिस ने बिंदेश्वरी के भाई के बयान पर मामला दर्ज कर आरोपित चालक को गिरफ्तार कर लिया। मामला शनिवार सुबह छह बजे का है। बिंदेश्वरी के भाई चंदेश्वर ने पुलिस को दिए बयान में कहा है कि वह शनिवार को ख्याला इलाके से आटो लेकर मोतीनगर की ओर आ रहे थे। बिंदेश्वरी भी अपने आटो से चंदेश्वर की आटो के आगे आगे चल रहे थे। रमेश नगर मेट्रो स्टेशन से आगे बढ़ने पर बिंदेश्वरी की आटो का सामना इसी लेन पर गलत दिशा में आ रही सफेद रंग की बीएमडब्ल्यू कार से हो गया। कार ने आटो को टक्कर मार दी। टक्कर से आटो के परखच्चे उड़ गए।

उधर बीएमडब्ल्यू कार भी डिवाइडर से टकराने के बाद रुक गई। इसके बाद कार चालक कार से निकला और घायल बिंदेश्वरी को आटो से निकालने में जुट गया। इस बीच चंदेश्वर मौके पर पहुंचे। कार चालक ने अपने साथियों के साथ मिलकर घायल बिंदेश्वरी को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने बिंदेश्वरी को मृत घोषित कर दिया। हादसे की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची मोती नगर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और आरोपित हर्षवीर को गिरफ्तार कर लिया। हर्षवीर पंजाबी बाग में रहता है। पुलिस के अनुसार पूछताछ में पता चला कि आरोपित कार में अपने दोस्तों के साथ बैठा था। उसने सड़क को खाली देखकर अपनी लेन बदली और विपरीत दिशा में कार ले जाने लगा।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता और पार्टी सांसद गौतम गंभीर नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान।

बस खरीद मामले में बढ़ सकती हैं केजरीवाल सरकार की मुश्किलें

नई दिल्ली । लो फ्लोर बसों की खरीद के मामले में दिल्ली सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सरकार ने जनवरी में दो कंपनियों को एक हजार बसें खरीदने के लिए ऑर्डर दिए थे। इन कंपनियों ने अब तक बसें तो उपलब्ध नहीं कराई हैं, लेकिन इस खरीद में गड़बड़ी के आरोप लगने लगे हैं। कहा जा रहा है कि बसों की कीमत से ज्यादा खर्च इनके तीन साल के रखरखाव पर किया जाएगा, जबकि खरीद की शर्तों के मुताबिक तीन साल तक इन बसों के रखरखाव की जिम्मेदारी आपूर्ति करने वाली कंपनी की होनी चाहिए।

इस मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने राज्य सरकार से अनुमति मांगी, लेकिन सरकार की ओर से मंजूरी नहीं दी गई। इस बाबत अब भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने उपराज्यपाल (एलजी) अनिल बैजल को पत्र लिखा है।

पत्र में उन्होंने दावा किया है कि बसों की खरीद को लेकर परिवहन विभाग की अंदरूनी जांच में वित्तीय गड़बड़ी का पता चला है। उन्होंने उपराज्यपाल से एसीबी को जांच की जल्द अनुमति दिलाने का अनुरोध किया है।

उपराज्यपाल अनिल बैजल को सोमवार को लिखे पत्र में विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि जनवरी में 890 करोड़ रुपये में एक हजार लो फ्लोर बसें खरीदने के लिए आर्डर दिए गए। इनमें से 700 बसों का आर्डर जेबीएम आटो लिमिटेड और 300 बसों का टाटा कंपनी को दिया गया। बसों की खरीद के लिए किए गए अनुबंध में तीन वर्षों या 2.10 लाख किलोमीटर चलने तक इसके रखरखाव की जिम्मेदारी शामिल थी। इसके बावजूद बसों के रखरखाव के लिए इन्हीं बस कंपनियों को अलग से प्रतिवर्ष 350 करोड़ रुपये का टेंडर दे दिया गया और उसमें तीन साल की वारंटी की अवधि को भी शामिल कर लिया गया। यानी रखरखाव के लिए पहले दिन से ही भुगतान किया जाना है।

विजेंद्र गुप्ता का दावा है कि भाजपा विधायकों की शिकायत का संज्ञान लेकर एसीबी ने जब दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशक को पत्र लिखकर जांच की अनुमति मांगी तो परिवहन विभाग द्वारा मामले की आंतरिक जांच कराई गई। उसमें भी खरीद प्रक्रिया में वित्तीय गड़बड़ी की बात सामने आई है। उनका आरोप है कि सरकार इस मामले को दबाने के लिए एसीबी को जांच की अनुमति नहीं दे रही है। इस मामले में वाट्सएप और ईमेल भेजकर सरकार से पक्ष मांगा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष मार्च में 1,250 बसें खरीदने का टेंडर निकाला गया था। उसके बाद 27 नवंबर को दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बोर्ड बैठक में बसों की खरीद व रखरखाव का अनुबंध देने का फैसला किया गया।

अनुबंध 1,250 की जगह एक हजार बसों की खरीद के लिए हुआ था। गुप्ता के अनुसार, बैठक का विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया था। जब भाजपा विधायकों ने विगत आठ मार्च को यह मामला उठाया तो उसी दिन डीटीसी की वेबसाइट पर बैठक का विवरण अपलोड कर दिया गया। इसमें वित्तीय गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर भाजपा विधायकों ने 12 मार्च को एसीबी से शिकायत की थी।

नई दिल्ली में हुमायूँ के मकबरे के मुख्य प्रवेश द्वार पर तैनात एक गार्ड, एएसआई-संरक्षित स्मारक और संग्रहालय 16 जून से फिर से खुलेंगे।

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह के घर पर हमला, नेम प्लेट पर पोती कालिख

नई दिल्ली । राम जन्मभूमि ट्रस्ट की जमीन खरीद में घोटाले का आरोप लगाने वाले आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पर मंगलवार दिन में हमला हुआ। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर दी है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो घर के अंदर घुस रहे थे मुझपर हमले के लिए। लेकिन मेरे साथियों ने उन्हें रोक लिया फिर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि हमलावरों में चार-पांच लोग शामिल थे। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ट्वीट किया है- मेरे घर पर हमला हुआ है। कान खोलकर सुन लो भाजपाइयों। चाहे जितनी गुंडागर्दी कर लो प्रभु श्री राम के नाम पर बनने वाले मंदिर में चंदा चोरी नही करने दूंगा।इसके लिए चाहे मेरी हत्त्या हो जाए।

बताया जा रहा हैकि आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पर नई दिल्ली स्थित घर पर मंगलवार दिन में हमला हुआ। इसके साथ संजय सिंह ने एक न्यूज टेलीविजन चैनल पर बात करते हुए कहा कि हमलावर उनके खिलाफ और रामजन्मभूमि ट्रस्ट को लेकर नारे लगा रहे थे। गौरतलब है कि पिछले दिनों संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश प्रवास के दौरान राम जन्मभूमि ट्रस्ट की जमीन खरीद में घोटाले का आरोप लगाया था। हमले के बाद संजय सिंह ने कहा कि इन चंदा चोरों को जेल भिजवाकर रहूंगा।

संजय सिंह ने ये भी बताया है कि कुछ महीने पहले भी मुझे मिट्टी का तेल छिड़क कर जलाने की धमकी मिली थी। गौरतलब है कि संजय सिंह ने लखनऊ में 13 जून को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर जमीन घोटाले के आरोप लगाए थे। इस दौरान संजय सिंह ने कहा था कि चंपत राय ने संस्था के सदस्य अनिल मिश्रा की मदद से दो करोड़ रुपये कीमत की जमीन 18 करोड़ रुपए में खरीदी। संजय सिंह ने इस मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बताते हुए इसकी जांच सीबीआइ और केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय से करने की मांग की थी।

संयुक्त किसान मोर्चा की इस जिद ने नर्क बना दी लाखों लोगों की जिंदगी, गांवों के लोग घरों में कैद

नई दिल्ली । तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को रद करवाने की जिद करके सिंघु बॉर्डर पर बैठे प्रदर्शनकारियों ने 200 दिन से न सिर्फ आसपास के लोगों की जिंदगी मुहाल कर रखी है, बल्कि इससे हरियाणा पंजाब, हिमाचल से आने वाले भी परेशान हो रहे हैं। ऐसे में कई राज्यों को दिल्ली से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग- एक अब मुसीबतों का हाई-वे बन गया है। इन राज्यों के लाखों लोगों को इससे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के प्रदर्शन के चलते दिल्ली के आसपास के गांवों के लोग घरों में कैद हो गए हैं। इन गांवों के बच्चे घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। छात्रों को स्कूल जाते समय परेशानी उठानी पड़ रही है। आसपास की फैक्टियां व पेट्रोल पंप बंद होने से लोग बेरोजगार हो रहे हैं। नौकरी करने जाने वाले लोग रोज कई किलोमीटर घूम कर जा रहे हैं। हालात इतने बदतर हैं कि दिल्ली के किसानों को अपनी खड़ी फसल खेतों में ही जोतनी पड़ रही है।

राजीव जैन (एग्जिक्यूटिव कमेटी सदस्य, दिल्ली पेट्रोल डीलर एसोसिएशन) कहना है कि 200 दिन से पेट्रोल पंप बंद हैं। हर रोज लाखों रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है। काम न होने की वजह से आधा स्टाफ कम करना पड़ा है। इससे बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की वजह से लाखों यात्रियों को भी परेशान होना पड़ रहा है।

प्रभुदयाल (श्रमिक, सिंघु बॉर्डर) के मुताबिक, 200 दिनों से काम ठप पड़ा है। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। आसपास के किसानों ने परेशान होकर बीते महीने गोभी की खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया था। यहां दुकानदारों का भी धंधा चौपट है। बंद दुकानों का किराया देना पड़ रहा है। ऐसे में भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। प्रदर्शनकारियों को यहां से उठा देना समय की जरूरत है।

सचिन (स्थानीय निवासी, सिंघु गांव) ने बताया कि रात के समय काम से जब घर लौटते हैं तो सिंघु बार्डर पर प्रदर्शनकारी गाड़ियों के सामने लाठियां लेकर खड़े हो जाते हैं। हमारे गांव में आकर हमसे ही पूछते हैं कि कहां जाना है।

इनमें से कोई किसान नहीं है, सभी नशे में धुत रहते हैं। यातायात गांवों से होकर गुजर रहा है, बच्चे घरों से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। रविवार को हरियाणा के सोनीपत जिले के एक व्यक्ति पर भी प्रदर्शनकारियों ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। तब जाकर हरियाणा के लोगों की आंखे खुलीं और उन्होंने इनका विरोध किया। जब तक दिल्ली के गांवों के लोग इकट्ठा नहीं होंगे तब तक ये नहीं उठेंगे।

हाई कोर्ट में बोला इंस्ट्राग्राम, हिंदू देवी-देवताओं से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री को हमने हटाया

नई दिल्ली । सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया है कि उसके मंच पर एक उपयोगकर्ता द्वारा पोस्ट की गई हिंदू देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक सामग्री उसने हटा दी है. न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने नोटिस भी जारी किया और फेसबुक तथा इंस्टाग्राम से एक याचिका पर जवाब मांगा. याचिका के जरिए सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश एवं डिजिटल आचार संहिता) नियम 2021 का पूर्ण रूप से क्रियान्वयन के लिए निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है.

इंस्टाग्राम का मालिकाना हक रखने वाले फेसबुक का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि (आपत्तिजनक)सामग्री हटाई जा चुकी है. उन्होंने यह भरोसा भी दिलाया कि याचिकाकर्ता की

शिकायत के मद्देनजर प्रतिवादी किसी तीसरे असंबद्ध पक्ष को याचिका की प्रतियां नहीं वितरित करेंगे.

रोहतगी ने कोर्ट में दी ये दलील

रोहतगी ने यह दलील भी दी कि नये सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियम के तहत फेसबुक द्वारा एक शिकायत निवारण अधिकारी भी नियुक्त किया गया है और संबद्ध व्यक्ति इंस्टाग्राम के लिए भी समान जिम्मेदारी के साथ काम करेगा.

अदालत ने नोटिस भी जारी किया और इस अनुरोध पर केंद्र से जवाब मांगा कि सरकार और सोशल मीडिया नेटवर्क को अपनी कार्यकारी, सांविधिक और अन्य सभी दायित्वों का निर्वहन बगैर विलंब के आईटी नियमों के आलोक में करने का निर्देश दिया जाए. इसके साथ ही अदालत ने विषय की अगली सुनवाई नियमित पीठ के समक्ष 16 अगस्त के लिए निर्धारित कर दी. याचिकाकर्ता आदित्य सिंह देशवाल ने दलील दी कि इंस्टाग्राम पर उन्होंने 'इस्लाम की शेरनी' नाम के एक उपयोगकर्ता द्वारा पोस्ट की गई बहुत ही आपत्तिजनक सामग्री पाई थी और इसमें हिंदू देवी-देवताओं के बारे में अश्लील कार्टून और ग्राफिक्स के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था. याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता जी तुषार राव और अधिवक्ता आयुष सक्सेना ने किया। उन्होंने इंस्टाग्राम से यथाशीघ्र यह सामग्री हटवाये जाने का अनुरोध किया था.

संपादकीय

आर्थिक गैर-बराबरी भी बीमारी

पिछले साल मार्च में जब पूर्ण लॉकडाउन लगाकर और आजीविका पर होने वाले इसके नुकसान से आंखें मूंदते हुए मजदूरों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया था, तब वे गांवों की ओर लौटने को मजबूर हो गए थे। घर वापसी की उनकी वह लंबी यात्रा पहली लहर से मिली पीड़ा और कठिनाई का प्रतीक थी। एक साल बाद, आज आम जनमानस पर देश की बदहाल स्वास्थ्य सेवा और विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के भी परेशान होने की तस्वीरें हावी हैं। विडंबना यह है कि स्वास्थ्य संकट ने आजीविका के संकट को मानो गायब कर दिया है, जिसका भारत सामना कर रहा है। इससे वे आवाजें भी मंद पड़ गई हैं, जो एक साल पहले अपने अधिकारों के लिए मुखर थीं। यह इस बात का पैमाना है कि राष्ट्र किस आसानी से अपने लोगों को छोड़ देता है। दूसरी लहर में आजीविका के आसन्न संकट को समझने के लिए सरकारें तैयार नहीं हैं और लोगों को दी जा रही राहत अब भी नाकाफी है। नतीजतन, देश का वंचित और गरीब तबका अब अपने मृत परिजन की सम्मानजनक अंतिम विदाई भी नहीं कर पा रहा।

दूसरी लहर ने एक ऐसी अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है, जो कोविड-19 के कारण ढांचागत असमानता के गहराने के संकेत दे रही है। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने हाल ही में देश में कामकाजी वर्गों की स्थिति का जायजा लेते हुए 'द स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया' रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि 2020 में देश के अधिकांश श्रमिकों की आमदनी में तेज गिरावट दिखी है। गरीब परिवारों की कुल आमदनी में यह गिरावट काफी ज्यादा थी। अंतिम पायदान के 10 फीसदी घरों में 27 फीसदी कम पैसे आए। गरीबों की आमदनी कम होने से उपभोग पर खासा असर पड़ा है। 'हंगर वाच' नामक संस्था बताती है कि अक्तूबर, 2020 में उसने जो सर्वे किया था, उसमें भाग लेने वाले हर तीन में से एक ने 'कभी-कभी' या 'अक्सर' एक समय भूखे रहने बात कही थी, और 71 फीसदी परिवारों ने भोजन में पोषक तत्वों की कटौती की बात मानी थी।

लॉकडाउन के बाद के आर्थिक सुधारों ने अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक गड़बड़ी को बेपरदा कर दिया, जिससे भारत पिछले साल निपटने में विफल रहा था। अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी के मुताबिक, औपचारिक अर्थव्यवस्था में यह दिखा कि महामारी के दौरान सूचीबद्ध कंपनियां छोटी व असंगठित इकाइयों की कीमत पर फायदे कमा रही हैं, जबकि प्रतिकूल हालात में भी देश के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार छोटी व असंगठित इकाइयां देती हैं। इस बेरोजगारी बढ़ाते आर्थिक सुधार के कारण संगठित क्षेत्र के वेतनभोगी कर्मी असंगठित क्षेत्र में काम करने को मजबूर हुए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी सीएमआईई के आंकड़ों के आधार पर 'द स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया' रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले साल भारत के संगठित वेतनभोगियों में से लगभग आधे असंगठित क्षेत्र में चले गए। उन्होंने या तो खुद का काम शुरू किया (30 फीसदी), निविदा पर काम करना शुरू किया (10 फीसदी) या फिर वे बिना सामाजिक सुरक्षा वाले रोजगार से जुड़ गए (नौ फीसदी)। दिक्कत यह है कि सरकार ने उन्हें राहत देने के लिए कोई खास जतन नहीं किए। सीमित आर्थिक प्रोत्साहन और आय-समर्थन की कमी ने देश में असमानता को और गहरा कर दिया। हालांकि, भूख और भुखमरी के खिलाफ सरकार ने कुछ मदद जरूर की।

दूसरी लहर अपने साथ तमाम तरह की चुनौतियां लेकर आई है, जो असमानता को और बढ़ाएगी। इसकी पहली वजह है- चूंकि केंद्र ने कुछ जिम्मेदारियों से अपने हाथ खड़े कर लिए हैं, इसलिए राज्य सरकारें अब अपने तईं योजनाएं बना रही हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि राज्यवार लॉकडाउन की खिचड़ी बन गई, और वंचित तबकों को आर्थिक राहत देने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकारों पर आ गई। लोगों को राहत पहुंचाने या आर्थिक मदद करने जैसे काम सैद्धांतिक तौर पर राज्य सरकारों के हवाले ही होने चाहिए, क्योंकि उन्हीं पर कई तरह के आर्थिक प्रभाव पड़ने की आशंका होती है। मगर, अब जब राज्यों को टीकाकरण, स्वास्थ्य ढांचा और राहत के लिए आर्थिक बोझ खुद उठाने को कहा जा रहा है, तब गरीबों को पर्याप्त आर्थिक सहायता मिल पाना मुश्किल जान पड़ता है। इसके अभाव में विशेषकर गरीब राज्यों में राहत के उपाय शायद ही परवान चढ़ सकेंगे।

दूसरी वजह, राज्य सरकारें साल 2020 के महत्वपूर्ण सबक सीखने में विफल रहीं। केंद्र द्वारा घोषित एकमात्र राहत उपाय, और जिसे राज्यों की सहयोग से पूरा किया गया, वह था जन-वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से खाद्यान्न बांटना। हालांकि, प्रवासी मजदूरों को इससे दूर रखा गया, जिसके कारण आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को दखल देकर कहना पड़ा कि राज्य सरकारें खाद्यान्न बंटवारे की अपनी योजना का विस्तार कर उसमें प्रवासी मजदूरों को भी शामिल करें। मगर आज भी कागजी कार्रवाई को लेकर नौकरशाही मनोग्रंथी और अस्थाई राशनकार्ड बांटने में हीला-हवाली खाद्यान्न तक आसान पहुंच की राह में बाधा बनी हुई है। आखिरी कारण, पिछले साल के विपरीत, इस वर्ष कोरोना ग्रामीण इलाकों में फैल रहा है। साल 2020 में श्रमिकों ने संकट से बचने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर खासा भरोसा किया था, और अर्थव्यवस्था ग्रामीण मांग पर निर्भर थी। लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं है। सीएमआईई के आंकड़े बताते हैं कि मई में ग्रामीण भारत में बेरोजगारी बढ़ी है, और मनरेगा के लिए जितनी मांग हो रही है, आपूर्ति उससे बहुत कम है। साफ है, आजीविका का संकट स्पष्ट और विकट है। बहरहाल, खबरें हैं कि केंद्र आर्थिक पैकेज देने के बारे में सोच रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि राजकोषीय घाटे और खौफ खाए बाजार पर इसके असर को लेकर चिंता है। फिर भी, सरकार जितनी देर से कदम उठाएगी, मांग पैदा होने में उतना ही वक्त लगेगा। लिहाजा, हमें वही रास्ता अपनाना चाहिए, जो जगजाहिर है। राज्य सरकारों की आर्थिक मदद को बढ़ाना, जन-वितरण प्रणाली का विस्तार करना और मनरेगा को लगातार जारी रखते हुए उसके बजट को बढ़ाना आवश्यक है। सरकार का उदार रुख अभी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। यदि नागरिकों के लिए नहीं, तो कम से कम बाजार के लिए ही वह तत्काल कदम उठाए।

प्रवीण कुमार सिंह

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता द्वारा केंद्र सरकार के साथ असहयोग का रवैया चिंता का विषय

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा केंद्र सरकार के साथ असहयोग का रवैया अपनाना निश्चित ही चिंता पैदा करने वाला मामला है। सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं, बल्कि संस्था होते हैं, जिन पर जनता का विश्वास होता है। लिहाजा आपदा काल में बंगाल की जनता को सहायता देने के लिए वहां गए प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री द्वारा यथोचित व्यवहार नहीं करना निंदनीय है। राजनीतिक मतभेदों को जनसेवा के संकल्प व संवैधानिक कर्तव्य से ऊपर रखने का यह एक दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण कहा जा सकता है।

पिछले दिनों बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात 'यास' जहां एक ओर पूर्व तटीय प्रदेशों में तबाही मचा गया, वहीं जाते-जाते यह एक ऐसा सियासी तूफान भी खड़ा कर गया, जिसमें संघीय ढांचे की कड़ियां कमजोर पड़ती दिख रही हैं। ऐसी आपदा से निपटने के लिए केंद्र-राज्य में समन्वय और सहयोग अपेक्षित होता है। यही वजह है कि 'यास' से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पर समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शामिल न होकर आपदा से निपटने में केंद्र का सहयोग नहीं करने का मुखर संदेश दिया। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री से मिलने पहुंची जरूर थीं, पर आधे घंटे की देरी और ऊपर से बैठक में हिस्सा लेने के बजाय प्रधानमंत्री को नुकसान पर रिपोर्ट सौंपकर उनकी अनुमति लेकर वहां से निकल गईं। ध्यातव्य है कि आपदा से नुकसान जनता का होता है, जिससे निपटने और राहत देने के लिए राज्य और केंद्र मिलकर काम करते हैं। जहां तक बात मुख्य सचिव की है तो वह राज्य सचिवालय का प्रमुख होता है, राज्य की प्रशासन व्यवस्था का नेतृत्व करता है तथा केंद्र एवं राज्य शासन के बीच संचार की कड़ी के रूप में कार्य करता है। लेकिन प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव का भी देरी से पहुंचना यह दर्शाता है कि मुख्य सचिव पर कर्तव्यों से इतर राजनीतिक बल ज्यादा प्रभावी था। उल्लेखनीय है कि राज्य का मुख्य सचिव आपदा के समय अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

लिहाजा आपदा की स्थिति में मुख्य सचिव को दिल्ली बुलाना उचित नहीं माना जा सकता। यही वजह है कि ममता ने केंद्र से मुख्य सचिव को प्रतिनियुक्ति पर बुलाने का आदेश रद करने की अपील की थी।मुख्य सचिव केंद्र और राज्य के बीच समन्वय का कार्य करते हैं, लेकिन राजनीति से प्रेरित होना प्रशासनिक अधिकारी आचार संहिता में प्रतिबंधित है। ऐसी स्थिति में अगर मुख्य सचिव उदासीनता बरतते हैं, तो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश में मुख्य सचिव को 31 मई की सुबह 10 बजे तक दिल्ली स्थित प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय में रिपोर्ट करना था, लेकिन उन्होंने दिल्ली नहीं जाने का फैसला लिया। इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से अनुशासनात्मक निर्णय लिए जाने की चर्चा थी, जिसके पहले ही उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। मुख्य सचिव अलापन बंद्योपाध्याय का कार्यकाल मई के आखिर में खत्म होने वाला था, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनका कार्यकाल केंद्र सरकार से कहकर तीन महीने बढ़वा दिया। मुख्य सचिव का कार्यकाल नियमों का पालन करने के लिए ही जाना जाता है। लेकिन अलापन बंद्योपाध्याय के उपरोक्त व्यवहार के कारण गृह मंत्रालय ने उनके खिलाफ चार्जशीट जारी करने की तैयारी कर ली है। मुख्य सचिव पद से रिटायरमेंट के बावजूद केंद्र की ओर से उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई के तौर पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मंगलवार को उन्हें नोटिस जारी किया गया है।

केंद्र सरकार के पास शक्ति है कि वह किसी भी राज्य के अधिकारियों की संख्या को कम कर सकता है, यानी ज्यादा से ज्यादा अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर ला सकता है। लेकिन जब तक कोई अधिकारी राज्य सरकार के अधीन है, केंद्र उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। इन सेवाओं के जरिये सेवा शर्तें तो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं, लेकिन उनकी सेवाएं केंद्र और राज्य दोनों ले सकते हैं। बहरहाल, इसी बात को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय सेवाओं की नियमावलियां इस तरह बनाई गई हैं, ताकि अधिकारी दबाव मुक्त रहकर अपना काम कर सकें। इसीलिए कैडर (संवर्ग) आवंटित करते समय ध्यान रखा जाता है कि हर राज्य में पर्याप्त संख्या में दूसरे राज्यों के निवासी पहुंचें, ताकि स्थानीय पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर काम कर सकें। केंद्र और राज्य दोनों की सहमति से ही किसी अधिकारी को केंद्र की प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है। इसके पीछे वजह सिर्फ राजनीतिक है, प्रशासनिक नहीं। लेकिन यह देश के संघीय ढांचे के लिहाज से ठीक नहीं है। इसी विवाद पर अलापन बंद्योपाध्याय को दिल्ली बुलाने के केंद्र के आदेश को असंवैधानिक बताते हुए ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख यह आदेश वापस लेने का अनुरोध किया था। फिलहाल, अगर देश के संघीय ढांचे की बात की जाए तो ममता बनर्जी ने पहले भी प्रधानमंत्री के साथ अनेक बैठकों में भाग न लेकर देश के परिसंघीय ढांचे को धता बताया है, चाहे वह कोरोना आपदा के दौरान मिलकर काम करने से संबंधित हो या तूफान से संबंधित राहत कार्ययोजना पर एकसाथ आना हो। संघीय ढांचे को कमजोर करने में ममता की भूमिका अग्रणी रही है। कोरोना रोधी वैक्सीन की आर्पूति को लेकर अभी हाल ही में इस तरह के मामले सामने आए हैं। इस प्रकार के टकराव की स्थिति अक्सर तब आती है, जब केंद्र और राज्यों में अलग-अलग राजनीतिक पॉटियों की सरकारें होती हैं, और प्रशासनिक अधिकारी किसी राजनीतिक दल की विचारधारा से प्रभावित होते हैं। ऐसी स्थिति में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर केंद्र या राज्य में से किसी एक के असीमित अधिकार संघीय ढांचे की भावना के खिलाफ होंगे, जो हमारे लोकतंत्र के लिए घातक साबित हो सकता है। प्रशासनिक अधिकारियों को तटस्थ होकर काम करना होता है, उनकी कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं होती है। ऐसे में राज्य सरकारों को विचार करना चाहिए कि समन्वयक अभिकरण अथवा कार्यकारी निकाय को कमजोर करना तथा उसका राजनीतिक हित में उपयोग करना क्या देश के लिए उचित होगा? क्या इससे संघीय व्यवस्था को चोट नहीं पहुंचेगी? क्या राज्य सचिवालयों को राजनीतिकरण करना जायज है?

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा केंद्र सरकार के साथ असहयोग का रवैया अपनाना निश्चित ही चिंता पैदा करने वाला मामला है। सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं, बल्कि संस्था होते हैं, जिन पर जनता का विश्वास होता है। लिहाजा आपदा काल में बंगाल की जनता को सहायता देने के लिए वहां गए प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री द्वारा यथोचित व्यवहार नहीं करना निंदनीय है। राजनीतिक मतभेदों को जनसेवा के संकल्प व संवैधानिक कर्तव्य से ऊपर रखने का यह एक दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण कहा जा सकता है।

निरंतर रंग बदल रहे कोरोना वायरस के सच की कहानी डेढ़ साल बाद भी रहस्यमय

कोरोना वायरस भले ही पूरी दुनिया में चीन से फैला, मगर इसकी उत्पत्ति नैर्सिगक थी या मानव जनित, यह बहस जारी है। निरंतर रंग बदल रहे इस वायरस के सच की कहानी डेढ़ साल बाद भी रहस्यमय है। शुरू से ही इस मामले में चीन का असहयोगी और आरोप लगाने वाला रवैया संदेह को बढ़ाता है। महामारी के शुरुआती दिनों में चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के विज्ञानियों की जांच टीम को अपने देश में प्रवेश देने से रोक दिया और जरूरी सूचनाएं हमेशा के लिए दफन कर दीं। चीन के एक विज्ञानी प्रो. झांग यांगझेन ने वायरस के जीनोम को ऑनलाइन पेश करना चाहा, तो उनकी प्रयोगशाला पर ही ताला लगा दिया गया। फिलहाल इस वायरस की उत्पत्ति के तीन प्रमुख सिद्धांत अस्तित्व में हैं। पहला, यह प्रयोगशाला में बना जैविक युद्ध का हथियार है। दूसरा, वुहान की वायरोलाजी लैब से लीक मानव निर्मित वायरस है और तीसरा एक चमगादड़ से वुहान के मीट मार्केट के जरिये इंसानों तक पहुंचा है। विभिन्न शोधों के बाद आज वायरस के मानव निर्मित होने की आशंका पर भ्रम बरकरार है। लगभग 17 महीने बाद वायरस के सेलेक्टिव एडवांटेज (प्राकृतिक विकास के आधार पर एक दिए गए परिवेश में किसी जीव की विशेषता उसे दूसरे जीव के मुकाबले जीवित रहने और बेहतर प्रजनन में सक्षम बनाती है) को देखें तो लगता नहीं कि यह किसी प्रयोगशाला की खुराफात का परिणाम था। ऐसा इसलिए, क्योंकि लैब निर्मित सूक्ष्मजीवों

का हमारे इतने विविधतापूर्ण पर्यावरण में जीवित रहना दुर्लभ है। विज्ञान अभी इतना विकसित नहीं हुआ कि प्रयोगशाला में कुछ ऐसा निर्मित कर दे, जो प्रकृति में भी सुगमता से रह सके। इसलिए इस वायरस को लैब में विकसित करने वाले सिद्धांत का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं बनता।

डब्ल्यूएचओ की 313 पेज की पहली रिपोर्ट में इस वायरस के वुहान की लैब से लीक होने की बात भी महज चार पन्नों में सिमट कर रह गई थी। इन चार पन्नों ने भी डब्ल्यूएचओ की जांच पर सवाल खड़े कर दिए थे। जांच टीम को वुहान के मीट मार्केट के 188 जानवरों के सैंपल में कोरोना वायरस नहीं मिला। वहीं दूसरी ओर, जीनोमिक सिक्वेंसिंग में वुहान के कई संक्रमण के मामले इस मार्केट से अलग म्यूटेशन दिखाते हैं। यानी वायरस पहले से इस कम्युनिटी में मौजूद था। इसलिए रिपोर्ट के मुताबिक वुहान का सीफूड मार्केट वायरस की उत्पत्ति का स्रोत न होकर सुपर स्प्रेडर बना। रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि लैब से वायरस के लीक होने की संभावना न के बराबर है। इसे जांचने के लिए वुहान लैब के विज्ञानियों का एंटीबाडी टेस्ट भी किया गया। उनके नतीजे निगेटिव आए थे। हालांकि वायरस के लैब से लीक होने और एंटीबाडी टेस्ट कराने के बीच में एक साल से ज्यादा का अंतराल था। हाल के शोधों में यह बात साफ हो चुकी है कि छह माह के बाद ज्यादातर लोगों में एंटीबाडी नहीं रह जाती। इस तरह डब्ल्यूएचओ की जांच में कोरोना वायरस की उत्पत्ति का सिद्धांत उलझ कर रह गया है।

डब्ल्यूएचओ ने एक महत्वपूर्ण तथ्य की अनदेखी की है कि यह वायरस चीनी वंशजों से संबंधित लोगों पर कम और यूरोप से संबंधित वंशजों पर ज्यादा हमलावर क्यों है? रिपोर्ट पर डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक ने टिप्पणी की थी कि वायरस के लैब से लीक होने की आशंका पर पर्याप्त शोध नहीं किया गया है। उन्होंने इसके लिए अतिरिक्त संसाधन मुहैया कराने की पेशकश भी की है। चीन ने वायरस को जिस तरह सिर्फ वुहान तक सीमित रखा और डब्ल्यूएचओ की टीम को शुरू में आने की इजाजत ही नहीं दी, इससे साफ है कि वहां की सरकार पारदर्शिता नहीं बरत रही है। इस कारण वायरस की उत्पत्ति की कहानी अधर में लटकी हुई है।

कोरोना: जान का हिसाब

बिहार सरकार ने कोरोना महामारी से राज्य में हुई मौतों की आधिकारिक संख्या में बुधवार को संशोधन किया, जिससे अगले दिन 24 घंटे में देश में हुई कुल मौतों की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई। हालांकि, तत्काल यह भी साफ हो गया कि मामला बिहार सरकार के आंकड़ों की गफलत से जुड़ा है और इससे देश में कोरोना महामारी के निरंतर सुधरते हालात पर कोई सवाल नहीं उठता। दरअसल, मौतें छुपाए जाने के आरोपों के बीच पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अप्रैल और मई में कोरोना से हुई मौतों की संख्या का ऑडिट कराने का आदेश दिया था। उसी आदेश का पालन करते हुए सरकार ने संशोधित आंकड़े जारी किए, जिससे राज्य में कोरोना से हुई मौतों की संख्या में एक ही दिन में 3951 का इजाफा हो गया। इस संख्या में उन मौतों को भी शामिल किया गया है, जो निजी अस्पतालों या होम क्वारंटीन में हुईं। एक बार ठीक हो जाने के बाद पोस्ट कोरोना कॉम्प्लिकेशंस से हुई मौतें भी इनमें शामिल हैं और अस्पताल के रास्ते में हुई मौतें भी। यह काम पहले ही होना चाहिए था। महामारी से जुड़ी हर मौत दर्ज होनी चाहिए।

अच्छी बात यह है कि बिहार सरकार ने न केवल अपनी संख्या दुरुस्त की, बल्कि आगे भी सबूत मिलने पर इस संख्या को संशोधित करने की तैयारी दिखा रही है। अन्य राज्यों को भी बिहार सरकार के इस रुख से प्रेरणा लेकर अपने आंकड़ों में आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। यह कोई छुपी हुई बात नहीं है कि भारत जैसे विशाल देश में सरकारी तंत्र की पहुंच की एक सीमा है। कोरोना संक्रमण का हर मामला और उससे हुई हर मौत तत्काल सरकारी रेकॉर्ड पर आ जाए, यह संभव नहीं है। इसीलिए यह बात पहले दिन से कही जा रही है कि भारत में कोरोना से हुई मौत के सरकारी आंकड़े वास्तविक संख्या से कम है। अंतरराष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं ने तो अपनी-अपनी गणना के अनुसार मौत की अनुमानित संख्या सरकारी आंकड़े से पचास गुना तक ज्यादा बताई। सरकार को अपने संसाधनों के मुताबिक इन अनुमानों की जांच-पड़ताल करते हुए अपने आंकड़े दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए थी। मगर कई राज्य सरकारें सही आंकड़े को छुपाने की कोशिश करती नजर आईं। यह गंभीर बात है। अगर इस पर आपत्ति हुई, तो वह ठीक था। सिर्फ इसलिए नहीं कि एक सभ्य समाज के रूप में हमें हर मौत को सम्मान देना और देते हुए दिखना चाहिए, इसलिए भी कि किसी भी महामारी से निपटने के लिए उसकी व्यापकता, गहनता और आक्रामकता की सटीक समझ बहुत जरूरी है। मौत के सही आंकड़ों से हमें भविष्य में आने वाली महामारियों से निपटने की तैयारी में भी मदद मिलेगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि बिहार से दूसरे राज्य भी सीखेंगे और अपने आंकड़े सही करेंगे। याद रखना होगा कि यह हमारे आज के साथ बेहतर कल के लिए भी जरूरी है।

महामारी से निपटने के लिए हुए प्रयासों को दर्ज करने से भविष्य में बहुत कुछ सीखा जा सकेगा

यहां किसी पक्ष या विपक्ष की बात करने की अपेक्षा इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि इस आपातकाल में राजनीति से बचा जा सकता था। राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर एकजुट होकर इस आपदा से और अधिक प्रभावी ढंग से लड़ा जा सकता था। आम आदमी में भ्रम के कारण वैक्सीन की स्वीकार्यता में हुए विलंब समेत महामारी के नाम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश के विरुद्ध हुए दुष्प्रचार से भी बचा जा सकता था। अत- हम सबको इस दौरान अपने अपने आचरण का ईमानदारी से विवेचन एवं आकलन करने की आवश्यकता है। इस आकलन में सभी पक्षों को ईमानदारी और निष्पक्षता से अपने अंदर झांकना होगा।

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जिलाधीशों की एक बैठक में कोरोना काल की महत्वपूर्ण घटनाओं एवं अनुभवों को जिला गजट में रिकॉर्ड करने का आवाहन एक भविष्योन्मुखी सोच है। वैसे भी यह प्रथा अंग्रेज हुकूमत के सिविल सेवा अधिकारियों से लेकर आजादी के बाद भी काफी अर्से तक जिलाधीशों की कार्यप्रणाली का हिस्सा रही है। हर जिलाधिकारी अपने अनुभव की एक डायरी लिखता था तथा कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को न केवल जिला गजट में स्थान मिलता था, अपितु हर उत्तरगामी अधिकारी के लिए यह एक जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत था। परंतु धीरे-धीरे यह प्रथा खत्म हो गई। प्रधानमंत्री का आवाहन संभवत- इसे पुनर्जीवित करने में सहायक बने। कोरोना महामारी मानव जीवन की एक असामान्य घटना है जो मनुष्य के जीवन में एक चुनौती के रूप में सामने आई है। विज्ञान के अभूतपूर्व आविष्कारों के बावजूद मनुष्य को इस प्रकोप ने अपना विकराल स्वरूप दिखाया जो इस पीढ़ी के मानस पटल पर जीवन पर्यंत एक वीभत्स घटना के रूप में अंकित रहेगा। इस महामारी का अनुभव एवं प्रभाव व्यापक एवं बहुमुखी है। अत- इसका अवलोकन, विवेचन, मूल्यांकन एवं संकलन जनहित में एक दूरगामी कदम साबित होगा। प्रधानमंत्री का आवाहन कि हमें इस संकट से निपटने में जिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और जिन समाधानों ने इससे लड़ने के हमारे संकल्प को मजबूत किया है, उन सबको ईमानदारी से संकलित करने की आवश्यकता को रेखांकित

करता है, ताकि भविष्य की ऐसी घटनाओं से निपटने में यह संकलन महत्वपूर्ण मार्गदर्शन का एक स्रोत बन सके।

इस समस्त घटनाक्रम में जिलाधीश के अतिरिक्त भी केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभागों समेत अनेक ऐसे व्यक्ति, वर्ग एवं समूह हैं जिन्होंने इस महामारी को नजदीक से देखा है। ऐसे अनेक संकट, समस्याएं एवं व्यवधान उनके समक्ष आए हैं जिनको न केवल सहन किया, अपितु उनका समाधान भी तलाशा है। भविष्य के लिए ये अनुभव अमूल्य संसाधन हो सकते हैं। कुछ ऐसे अनुभव देशव्यापी रहे हैं जिसमें सहयोग एवं व्यवधान दोनों ही शामिल हैं। कुछ अनपेक्षित घटनाएं एवं व्यवधान भी ऐसे हैं जिन्होंने सरकारों के समक्ष चुनौती को और अधिक गंभीर बना दिया। कुछ ऐसे विचार एवं समाधान भी हैं जिन्होंने संकट से बाहर जाने का मार्ग प्रशस्त किया। अत- उनके द्वारा दिया गया विवरण अधिक यथार्थवादी व उपयोगी होगा।

लिहाजा ऐसे सभी भागीदारों द्वारा अपने अपने स्तर पर ऐसे अनुभवों का संकलन करना सार्थक हो सकता है। इससे न केवल भविष्य के लिए इस अभूतपूर्व संकट के अनुभव से सीखने को मिलेगा, अपितु हर ऐसे विभाग और संस्था को स्वयं का आकलन करने का भी एक अवसर मिलेगा। इस संकट से लड़ने में अधिकांश सहभागियों ने अपना सर्वस्व लगाने का प्रयास किया है। परंतु इस आशंका से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि शीर्ष स्तर तक बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं व्यवस्थाजनित व्यवधानों के कारण पहुंच ही नहीं पाई। हर सरकार अपने स्तर पर जनहित में अधिकांश फैसले लेने का प्रयास करती है। परंतु कई बार नीतिगत फैसलों में निहित जनकल्याण आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने से पहले ही विभिन्न खामियों के कारण अपनी चमक खो देता है। इस महामारी के दौरान भी ऐसी आशंकाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता। अत- इस दौरान किए गए प्रयासों का वास्तविक मूल्यांकन खुले मन से करना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक विभाग द्वारा इस दौरान निभाई गई जिम्मेदारियों का ईमानदार आकलन विभाग के भविष्य के लिए भी एक अमूल्य धरोहर होगा। इस महामारी काल का एक और पक्ष भी अभूतपूर्व है जिसका चिंतन किया जाना आवश्यक है।

स्वतंत्र भारत के इतिहास में जितनी भी आपात स्थिति देश के समक्ष आई हैं, वे देश के दुश्मनों के साथ युद्ध के समय की रही हैं। इस देश का एक गौरवमय इतिहास रहा है कि हमने आपात स्थिति में हमेशा एकजुटता का परिचय दिया है। हर बार ऐसी स्थिति में समस्त राष्ट्र देश के सत्तासीन नेतृत्व के पीछे एकजुट खड़ा दिखाई दिया। परंतु दुर्भाग्यवश वर्तमान आपातकालीन स्थिति में जो पूर्वगामी आपात स्थितियों से कई मायनों में अधिक गंभीर एवं चुनौतीपूर्ण है, देश इस गौरवमयी परिपाटी से भटक गया और उस समय भी राजनीति हो रही है, जब एकजुट होकर देश को बचाने के लिए सबको मिलकर प्रयत्न करना चाहिए।

यहां किसी पक्ष या विपक्ष की बात करने की अपेक्षा इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि इस आपातकाल में राजनीति से बचा जा सकता था। राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर एकजुट होकर इस आपदा से और अधिक प्रभावी ढंग से लड़ा जा सकता था। आम आदमी में भ्रम के कारण वैक्सीन की स्वीकार्यता में हुए विलंब समेत महामारी के नाम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश के विरुद्ध हुए दुष्प्रचार से भी बचा जा सकता था। अत- हम सबको इस दौरान अपने अपने आचरण का ईमानदारी से विवेचन एवं आकलन करने की आवश्यकता है। इस आकलन में सभी पक्षों को ईमानदारी और निष्पक्षता से अपने अंदर झांकना होगा। हमारी अंतरात्मा को हमारी कमजोरियों से साक्षात्कार करना होगा, तभी हम भविष्य में स्वयं को अपनी कमजोरियों से बाहर निकालने में सफल होंगे।

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91 से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

संक्षिप्त खबर

नगर निगम सदन में हंगामा, पार्षद बोले- कानपुर में सपा के लिए अच्छा माहौल तैयार कर रहे अफसर

कानपुर । नगर निगम सदन की शुरुआत हंगामे के साथ हुई, पहले तो पार्षदों ने विकास कार्य न होने और नाला सफाई को लेकर अफसरों को घेरा। वहीं सपा पार्षदों ने अफसरों द्वारा सपा के लिए चुनावी माहौल बनाने की बात कही तो भाजपा पार्षद भड़क गए और नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं सपा पार्षद सुहेल अहमद ने हाउस टैक्स एरियर का मुद्दा उठाया तो महापौर के पास भी कोई जवाब नहीं रहा। कानपुर नगर निगम सदन महापौर प्रमिला पांडेय की मौजूदगी में मगंलवार की सुबह 11ः15 बजे शुरू हुआ तो पार्षद नवीन पंडित ने जागेश्वर अस्पताल को चालू कराने के लिए मांग रखी। उन्होंने कहा चाचा नेहरु अस्पताल की तरह जागेश्वर अस्पताल चालू कराया जाए। इसके बाद उपसभापति कैलाश पांडे ने नगर निगम और जल कल का बजट पेश किया। बजट में विकास कार्यों में खर्च की बात सुनते ही पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया। पार्षदों ने अफसरों पर विकास कार्य न कराने में लापरवाही का आरोप लगाया।

पार्षदों के हंगामे के बीच सपा पार्षद सुहेल अहमद ने कहा कि विकास कार्य न होने से भले ही जनता को परेशानी से जूझना पड़ रहा है लेकिन आने वाले चुनाव के लिए अधिकारी सपा के लिए अच्छा माहौल तैयार कर रहे हैं। समस्याओं से जूझ रही जनता के सामने सपा ही विकल्प होगी। इसपर दूसरे सपा पार्षदों ने भी हामी भरते हुए चुटकी लेना शुरू कर दिया। इस बात पर नाराजगी जताते हुए भाजपा पार्षद विरोध पर उतर आए और योगी-मोदी जिंदाबाद व जय श्रीराम के नारे लगाने शुरू कर दिये। शोर शराबा और हंगामा होते देखकर महापौर ने खड़े होकर सभी फटकार लगाई और शांत कराया। सपा पार्षद दल के नेता ने कहा साढ़े तीन साल बाद भी विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। नाली खड़ंजा सड़क को बनवाने को लेकर पार्षद जूझ रहे हैं। कहा, स्मार्ट सिटी के नाम पर खर्च हुए करोड़ों रुपये कहां गए, इसकी जांच होनी चाहिए। ऐसे बजट से क्या फायदा जो केवल दिखावा हो।

शादी के लिए रख दी अजीब सी शर्त, तैयार नहीं हुई महिला तो शाखा प्रबंधक ने रच दी इंतकाम की साजिश

बक्सर । महिला माइक्रो फाइनेंस कर्मी की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसी कंपनी की यूपी के गाजीपुर जिले के गहमर थाना अंतर्गत सेवराई सतरामगंज शाखा के शाखा प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी नीरज कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि पूछताछ में शाखा प्रबंधक ने महिला कर्मी की हत्या की बात स्वीकार कर ली है। उन्होंने बताया कि मामला आत्मीय संबंधों से जुड़ा है, जिसमें वह और आगे जाना चाह रहा था लेकिन महिला तैयार नहीं थी। इसी बात से खफा शाखा प्रबंधक ने इंतकाम में साजिश रचने के बाद गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं घटना को अंजाम देने के बाद अपराध बोध होते ही उसने भी अपनी जान देने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि शाखा प्रबंधक का उक्त महिला से काफी दिनों से संबंध था। महिला से मिलने के लिए वह उत्तर प्रदेश से अक्सर तियरा आया करता था। शादी के लिए उसने महिला के सामने अपने एक बच्चे को लेकर भाग जाने की शर्त रखी थी। जबकि महिला अपने तीनों बच्चों में से किसी को छोडने के लिए तैयार नहीं थी। इसी बात पर दोनों की सहमति नहीं बन रही थी। तभी उसे आशंका हुई कि गीता देवी के अन्य लोगों से भी संबंध हैं जिसके कारण वह उसके साथ जाने से इंकार कर रही है। बस इतनी बात दिमाग में आते ही उसे यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। इसी बात को लेकर उसके दिमाग में हत्या का खाका तैयार होने लगा और आखिरकार प्रबंधक ने गीता की नृशंस तरीके से हत्या कर दी।

ऐसी रची साजिश – एसपी ने बताया कि भदौरा के समीप सतरामगंज स्थित कैशपार माइक्रो फाइनेंस कंपनी के शाखा प्रबंधक कौशांबी निवासी शिवबरन आर्य का पत्नी से तलाक होने के बाद तियरा शाखा में कार्यरत महिला गीता देवी के साथ आत्मीय संबंध जुड़ गया था। मामला यहां तक पहुंच गया था कि प्रबंधक महिला कर्मी पर शादी करने का दबाव बनाने लगा था लेकिन, मृतका गीता देवी उनकी शर्तों पर तैयार नहीं थी। इसी बीच प्रबंधक को इस बात की आशंका हुई कि गीता देवी का अन्य लोगों से भी संबंध था और यह बात उसे बेहद नागवार गुजरी। इसी बात को लेकर वह 9 जून को तियरा आकर गीता देवी से मिला भी था। जिसके बाद योजनाबद्ध तरीके से उसने गीता की हत्या कर दी। बताते चलें कि बुधवार की शाम अपने ग्राहक से कागजात लेने के लिए रौनी गई गीता देवी अचानक गायब हो गई थी। इस बीच सारी रात खोजबीन करने के बाद अगली सुबह देवढिया़ गांव के बधार से गला और कलाई रेत कर हत्या किया गीता देवी का शव पुलिस ने बरामद कर लिया। घटना के बाद तरह तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, पर इन सबसे अलग पुलिस हत्यारे की खोज में दिन रात एक कर लगी रही और आखिरकार हत्यारे को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिल गई।

अब कानों पर भी असर डाल रहा कोरोना, सुनने की शक्ति प्रभावित, पंजाब में आ रहे हैं ऐसे मरीज

लुधियाना । कोरोना से ठीक हो चुके लोगों की परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। लोगों को नई-नई बीमारियां जकड़ रही हैं। ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, मेंटल डिसआर्डर के बाद अब कुछ मरीजों को कानों में घंटी और सीटी बजने की आवाज महसूस हो रही है। कई लोगों को तो सुनना भी बंद हो गया है। इस कारण उन्हें हेयरिंग एड तक लगानी पड़ रही है। शहर के प्राइवेट अस्पतालों में इएनटी विशेषज्ञों के पास रोजाना कई मरीज इस तरह की शिकायत के साथ पहुंच रहे हैं। फोर्टिस अस्पताल के ईएनटी विभाग के हेड डा. रजत भाटिया का कहना है कि ओपीडी में रोजाना 30 से 50 साल की उम्र के 20 से 30 प्रतिशत कोरोना से ठीक हो चुके मरीज आ रहे हैं जिन्हें कान में घंटी या सीटी की आवाज सुनाई दे रही है। इस समस्या के कारण उन्हें रात को नींद नहीं आ रही है। उनका कहना है कि कानों में घंटी या सीटी बजने के कई कारण हो सकते हैं। इसमें एक कारण यह है कि कोरोना वायरस नाक से जरिए ओवरआल इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है। हालांकि अब तक इस बात का पुख्ता सुबूत नहीं है। उन्होंने कहा चूंकि नाक और कान बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं, ऐसे में जो भी इंफेक्शन नाक में आ रही है, वो अगर कान में जाती है तो वायरल इंफेक्शन की वजह से रिएक्शन आता है। इसके चलते कान के सेल्स डैमेज हो जाते हैं। दूसरी वजह यह हो सकती है कि जब नाक में वायरस का असर आता है, तो कोल्ड टाइप सिमटम हो जाता है। रेशा या म्यूकरर्स की वजह से कान के अंदर भारीपन या कान के अदंर फ्लूड आ जाता है। इससे भी कानों में घंटी बजने जैसा महसूस होने लगता है। इसके अलावा एक वजह यह भी हो सकती है कि कोरोना संक्रमित होम आइसोलेशन या अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान अकेलेपन को दूर करने के लिए कई दिनों तक हेड फोन इस्तेमाल करते हैं। हेड फोन का अत्याधिक इस्तेमाल भी सुनने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है।

उत्तराखंड सरकार ने तीन जिलों के लोगों के लिए चारधाम यात्रा खोलने के आदेश को किया स्थगित

देहरादून । उत्तराखंड सरकार ने तीन जिलों (चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी) के लोगों के लिए चार धाम यात्रा खोलने के अपने आदेश को स्थगित कर दिया है। मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि चार धाम यात्रा को लेकर नैनीताल हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। राज्य सरकार 16 जून के बाद यात्रा शुरू करने पर फिर से विचार करेगी। उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार को तीन जिलों चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के लोगों के लिए चारधाम यात्रा खोलने के अपने आदेश को स्थगित कर दिया है। सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि चारधाम यात्रा को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 16 जून के बाद यात्रा खोलने पर पुनर्विचार करेगी। बता दें कि कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के साथ ही सरकार ने बीते रोज चारधाम यात्रा को खोलने की घोषणा की थी। जिसमें चमोली, रुद्रप्रयाग व उत्तरकाशी जिलों के स्थानीय निवासियों के लिए यात्रा खोली गई थी। इन जिलों के निवासी 72 घंटे पहले तक की आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट होने पर धामों में दर्शन करने की अनुमित थी। उत्तराखंड सरकार ने सोमवार को राज?य में कोविड -19 कर्फ्यू को एक और सप्ताह बढ़ाकर 22 जून कर दिया है। विस्तारित कोविड कर्फ्यू के दौरान सप्ताह में तीन दिन बाजार, पांच दिन मिठाई की दुकानें खुलेंगी।

उत्तर प्रदेश में बसपा में बगावत, निलंबित 11 विधायक बनाएंगे अपना नया दल

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति काफी गरमा गई है। बहुजन समाज पार्टी से निलंबित 11 विधायक अब एकजुट हो गए हैं। इन सभी ने लालजी वर्मा के नेतृत्व में नया दल भी बनाने का फैसला कर लिया है। बसपा से निलंबित नौ विधायक लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव से भी मिलने गए थे। बसपा में कुल 18 विधायकों में से नौ को पार्टी ने निलंबित और दो को निष्काषित किया। उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मची हुई है। बसपा पूरी तरह टूटने की कगार पर है और चर्चा यह भी है कि सभी बागी विधायक बहुत जल्द सपा का दामन थाम कर आगामी विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के बैनर तले लड़ेंगे। राज्यसभा चुनाव में बसपा से बगावत करने के बाद निलंबन झेल रहे श्रावस्ती के विधायक असलम राईनी ने कहा कि बसपा के बागी सभी 11 विधायक मिलकर अपनी नई पार्टी बनाएंगे। राईनी ने कहा कि हमारे नेता लालजी वर्मा होंगे। उनके साथ ही रामअचल राजभर भी हमारे साथ हैं। हम लोग तो लालजी वर्मा को अपनी पार्टी का मुखिया बनाएंगे। 11 विधायक अब एक साथ हैं। अभी हमारे पास एक विधायक की कमी है, जिसके कारण तत्काल नया दल नहीं बन पा रहा है। इस बीच अगर एक और विधायक साथ आया तो पार्टी बनाएंगे। नए दल का नाम लालजी वर्मा को डिसाइड करना है। लालजी वर्मा ने इस पर कोई टिप्पणी से इन्कार किया है।

राईनी ने कहा कि हमको बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती से तो कोई शिकायत नहीं है, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का व्यवहार स्तरीय नहीं है। राईनी का कहना है कि उनकी बसपा सुप्रीमो मायावती से कोई शिकायत नहीं है, उनकी मुख्य शिकायत सतीश चंद्र मिश्रा से है। वह जितना कहते हैं मायावती सिर्फ उतना ही करती हैं। सभी 11 विधायकों को बहन मायावती से कोई नाराजगी नही है, सतीश चंद्र मिश्रा पार्टी को खाक में मिलाने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि आज बसपा के साथ प्रदेश का एक भी मुसलमान नहीं है।

अखिलेश यादव से मुलाकात करने पर विधायक असलम राईनी ने कहा कि हम तो किसी भी नेता से मिल सकते हैं। पहले भी निलंबित नौ विधायक अखिलेश यादव से मिले थे और आज भी मिले हैं। आज मुलाकात हुई इसका कोई सबूत नहीं है। अखिलेश यादव से आज इन बागी विधायकों की भेंट के दौरान 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। पहले छह विधायक गए बाद में तीन और पहुंचे थे। भेंट के बाद यह सभी समाजवादी पार्टी कार्यालय के पिछले गेट से बाहर निकले। यह भी माना जा रहा है कि अब बसपा से निष्कासित नेताओं को बसपा के बागी जोड़ेंगे। इसके बाद इनको सपा में लाने की जिम्मेदारी दी गई है।

बसपा से निलंबित प्रतापपुर, प्रयागराज से विधायक मुजतबा सिद्दीकी ने कहा कि हम इंतजार में हैं कि बहन जी निलंबन वापस ले लें। अब अगर निलंबन वापस नहीं हुआ तो आगे कदम उठाएंगे। हम लोग तो बस बसपा की अयध्क्ष मायावती के स्टैंड का हम इंतजार कर रहे हैं। अभी हम बागी विधायकों के बीच में पार्टी बनाने को लेकर बात हुई है, लेकिन सहमति नहीं बनी है। उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता लालजी वर्मा के पास भी कोई विकल्प नहीं है। बसपा में तो हम लोगों को रोज प्रताड़ित किया जाता है। कभी टिकट तो कभी फंड को लेकर धमकी मिलती है। कोऑर्डिनेटर लोग धमकाते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव से आज औपचारिक मुलाकात हुई है। उनसे किसी तरह से न तो समाजवादी पार्टी में शामिल होने की बात हुई है और न ही टिकट लेने की बात हुई। आज हम सात विधायकों ने उनसे भेंट की। राज्यसभा चुनाव के बाद पार्टी से निलंबित होने के बाद भी हम लोग उनसे मिले थे।

सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का कहना है कि सभी बागी विधायकों के आने से समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा बल मिलेगा और सबके सहयोग से मिशन 2022 को पूरा करेंगे। तब जाकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी।अखिलेश यादव से मुलाकात करने वाले बागियों में असलम राईनी, असलम अली, मुज्तबा सिद्दीकी, हाकिम लाल, सुषमा पटेल और हरगोविंद भार्गव शामिल थे।

बसपा से निलंबित विधायक

असलम राइनी (भिनगा-श्रावस्ती)
असलम अली चौधरी (ढोलाना-हापुड़)
मुजतबा सिद्दीकी (प्रतापपुर-प्रयागराज)
हाकिम लाल बिंद (हांडिया-प्रयागराज)
हरगोविंद भार्गव (सिधौली-सीतापुर)
सुषमा पटेल (मुंगरा बादशाहपुर-जौनपुर)
वंदना सिंह (सगड़ी-आजमगढ़)
रामवीर उपाध्याय (सादाबाद-हाथरस)
अनिल सिंह (पुरवा-उन्नाव)।

बसपा से बर्खास्त विधायक

लालजी वर्मा (कटहरी-अम्बेडकरनगर)
रामअचल राजभर(अकबरपुर-अम्बेडकरनगर)।

प्रदेश में 21 जून से 50 फीसद क्षमता के साथ खुलेंगे रेस्टोरेंट, नाइट कर्फ्यू में भी दी जाएगी छूट से राहत

लखनऊ । वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के सेकेंड स्ट्रेन का असर कम होने के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार धीरे-धीरे राहत दे रही है। प्रदेश के सभी 75 जिलों से कोरोना कर्फ्यू हटाने के बाद अब योगी आदित्यनाथ सरकार ने नाइट कर्फ्यू में भी थोड़ी राहत दी है। इसके साथ ही कुछ बंदिशों के साथ रेस्टोरेंट, पार्क तथा स्ट्रीड फूड की दुकानों को भी 21 जून से खोलने की अनुमति दी है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को समीक्षा बैठक के बाद टीम-09 के छूट देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड संक्रमण के दृष्टिगत दिन पर दिन बेहतर होती स्थितियों के बीच सोमवार, 21 जून से रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू में और छूट दी जाएगी। प्रदेश सरकार का अब रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू रात नौ बजे से अगले दिन सुबह सात बजे तक प्रभावी होगा। इसके साथ ही सरकार ने कुछ और छूट तय कर ली है। प्रदेश के हर जिले में कोविड प्रोटोकॉल के साथ रेस्टोरेंट को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोला जा सकेगा। इसके साथ ही सभी पार्क तथा स्ट्रीट फूड आदि के संचालन की अनुमति भी दी गई है। सरकार का इसके बाद भी सख्त निर्देश है कि इन सभी स्थान पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य होगी। मास्क के साथ प्रवेश अनिवार्य होगा जबकि रेस्टोरेंट में आने वाले सभी लोगों का सैनिटाइजर से हाथ साफ करना भी जरूरी है। दुकान या शोरूम में पहले की तरह मास्क और सैनेटाइजर की अनिवार्यता रहेगी। साथ ही वहां हेल्प डेस्क भी बनानी होगी। आने- जाने वालों का रजिस्ट्रर बनाना होगा। इसमें नाम, पता और बाकी डिटेल रहेगी। दुकानों के साथ सब्जी मंडियां भी रात 9 बजे तक खुल सकेंगी। पर घनी आबादी की सब्जी मंडियों को प्रशासन खुले स्थान पर खुलवाएगी।सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि नई व्यवस्था के संबंध में विस्तृत गाइडलाइंस शीघ्र ही जारी कर दी जाएं।

रांची के सदर अस्पताल के सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर स्वास्थ्यकर्मि धरना देते हुए।

अयोध्या में जमीन खरीद का सच- ज्यादा नहीं, ट्रस्ट ने तो जमीन की कम कीमत दी

अयोध्या । राम नगरी अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के साथ ही दर्शन के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए कृतसंकल्पित श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जमीन खरीदने में घोटाले के आरोप को बेबुनियाद बताया है। ट्रस्ट का दावा है कि जिन जमीनों को खरीदा गया है, उनका मूल्य बाजार दाम से कम ही दिया गया है।

अयोध्या में श्रीरामजन्मभूमि परिसर से कुछ ही फासले पर बाग बिजेसी मुहल्ला में की भूमि की खरीद में रविवार को समाजवादी पार्टी के नेता तथा पूर्व मंत्री तेजनारायण पांडेय पवन के घोटाले के आरोप को ट्रस्ट ने बेबुनियाद बताया है। श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक जमीन का एग्रीमेंट पहले ही हो चुका था, हमने जमीन की औसत से भी कम कीमत चुकाई है।

समाजवादी पार्टी नेता के आरोप का मुख्य आधार यह था कि जिस भूमि का इसी वर्ष 18 मार्च को तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 18.50 करोड़ में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया, उस भूमि का एग्रीमेंट करने वाले रविमोहन तिवारी व सुल्तान अंसारी ने उसी तारीख को 10 मिनट पहले ही मात्र दो करोड़ रुपये में बैनामा कराया था। पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया था कि दो करोड़ की भूमि 18.50 करोड़ में एग्रीमेंट कराने के पीछे बड़ा घोटाला किया गया।

ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने सोमवार को कहा कि सच्चाई यह है कि संबंधित भूमि का चार मार्च, 2011 को यानी 10 वर्ष पहले मोहम्मद इरफान, कुसुम पाठक व हरिदास ने दो करोड़ में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया था। तीन वर्ष बाद इस एग्रीमेंट का नवीनीकरण भी कराया गया। इस भूमि का 2017 में हरिदास एवं कुसुम पाठक ने भू स्वामी नूर आलम, महफूज आलम एवं जावेद आलम से बैनामा करा लिया। हरिदास एवं कुसुम पाठक से इस भूमि का 17 सितंबर, 2019 को रविमोहन तिवारी, सुल्तान अंसारी आदि आठ लोगों ने एग्रीमेंट कराया। रविमोहन एवं सुल्तान अंसारी ने ही 18 मार्च, 2021 को इस भूमि का बैनामा कराया।

पूर्व मंत्री पवन पाण्डेय जिस भूमि को दो करोड़ का बता कर उसे 18.50 करोड़ में क्रय करने पर आपत्ति जता रहे हैं, तय सर्किल रेट चार हजार आठ सौ रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भी उसकी मालियत पांच करोड़ 79 लाख 84 हजार तय होती है। जबकि मालियत से इतर बाग बिजेसी एवं रामनगरी के आस-पास की जमीन का मौजूदा औसत मूल्य दो हजार रुपये प्रति वर्ग फीट है और इस हिसाब से देखें तो ट्रस्ट ने संबंधित भूमि के लिए औसत मूल्य से भी काफी कम कीमत चुकाई है। संबंधित भूमि का क्षेत्रफल 12 हजार 80 वर्ग मीटर यानी एक लाख 29 हजार 981 वर्ग फीट है और इस हिसाब से ट्रस्ट ने 1423 रुपये प्रति वर्ग फीट से जमीन की कीमत अदा की है।

राम मंदिर का फैसला आते ही जमीनों के दाम बढ़ गए– राम मंदिर के पक्ष में फैसला आते ही अयोध्या में जमीनों के दाम तेजी से बढ़ गए। अभी जिले में 20 लाख से 50 लाख रुपए बिस्वा जमीन का रेट है। उत्तर प्रदेश सरकार भी कई योजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहीत कर रही है। इससे भी जमीन के दाम में बढ़ोतरी हुई है। बड़े कारोबारी अयोध्या में होटल्स, मॉल और मार्केट खोलने के लिए जमीनें ले रहे हैं। कई तरह की इंडस्ट्री भी लगने वाली है।

आरोप लगाने वाले राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित : चम्पतराय

रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चम्पतराय बंसल ने कहा है कि आरोप लगाने वाले लोग राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित हैं। चम्पतराय की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि मंदिर के पूर्व व पश्चिम भाग में निर्माणाधीन परकोटा व रिटेनिंग वाल के लिए परिसर से लगे कुछ मंदिरों एवं स्थानों को परस्पर सहमति से क्रय किया जा रहा है।

इस प्रक्रिया में विस्थापित होने वाले प्रत्येक संस्थान या व्यक्ति का पुनर्वास किया जाएगा। पुनर्वास के लिए भूमि का चयन संबंधित पक्ष की सहमति से किया जा रहा है। बाग बिजेसी, अयोध्या स्थित 1.20 हेक्टेयर भूमि इसी प्रक्रिया के अंतर्गत पूरी पारदर्शिता से क्रय की गई है। इस भूमि के संबंध में वर्ष 2011 से वर्तमान विक्रेताओं के पक्ष में 2011, 2017 व 2019 में अनुबंध संपादित हुआ।

किसी के साथ कोई धोखा नहीं : सुल्तान

ट्रस्ट के नाम संबंधित भूमि का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करने वाले सुल्तान अंसारी का कहना है कि संबंधित भूमि के क्रय-विक्रय में न हमने और न ट्रस्ट ने कोई धोखा किया है। एक दशक पूर्व अयोध्या में जब जमीन की कीमत काफी कम थी, तभी हम लोगों ने दो करोड़ में संबंधित भूमि का एग्रीमेंट कराया था। सच्चाई यह है कि राम मंदिर में सहयोग को ध्यान में रखकर इस जमीन को बाजार भाव से काफी कम में एग्रीमेंट किया गया है।

उन्नाव में एयरफोर्स जवान की गोली मारकर हत्या, रात में मोबाइल पर किसकी आई थी कॉल

उन्नाव । गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के बसधना गांव में एयरफोर्स जवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मंगलवार सुबह ग्रामीणों ने गांव के बाहर उसका शव देखा तो सनसनी फैल गई। पुलिस ने जांच-पड़ताल की तो पता घटनास्थल पर एक खाली कारतूस पड़ा मिला है। वहीं रात में किसी अंजान की मोबाइल फोन पर कॉल आने के बाद एयरफोर्स कर्मी घर से निकल गए थे।

शुक्लागंज के प्रेमनगर निवासी 28 वर्षीय प्रतीक सिंह जम्मू में एयरफोर्स में एयरमैन के पद पर तैनात थे। वह 11 जून को छुट्टी लेकर जम्मू से घर आए थे। सोमवार की रात करीब आठ बजे उनके मोबाइल फोन पर किसी की कॉल आई थी और इसके बाद वह कुछ देर में वापस आने की बात कहकर घर से निकले गए थे। देर रात तक घर नहीं पहुंचे तो स्वजन ने तलाश की लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद घरवालों ने पुलिस को सूचना दी थी। मंगलवार की सुबह ग्रामीणों ने बसधना गांव के बाहर खेत में शव पड़ा देखा तो सनसनी फैल गई।

ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त का प्रयास किया। इसी बीच प्रतीक के स्वजन भी घटनास्थल पर पहुंचे और शव की पहचान कर ली। पुलिस के मुताबिक युवक की गोली मारकर हत्या की गई। उसकी दाहिनी आंख में गोली लगी है और पास ही 315 बोर कारतूस का खोखा पड़ा मिला है। गोली किसने मारी और क्यों मारी इस बात का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस मृतक के स्वजन से पूछताछ कर आरोपित की तलाश कर रही है।

पीएम मोदी के मार्गदर्शन से ही हम अच्छा प्रदर्शन कर पाए : योगी

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की फर्स्ट तथा सेकेंड स्ट्रेन पर प्रभावी नियंत्रण के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने थर्ड स्ट्रेन से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि थर्ड स्ट्रेन का बच्चों पर सर्वाधिक असर होगा। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के हर जिलों में बच्चों के लिए अलग आइसीयू यूनिट तैयार कराने के साथ ही उनको थर्ड स्ट्रेन से बचाने के लिए किट भी तैयार करवा ली है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कोरोना वायरस संक्रमण की थर्ड स्ट्रेन से बच्चों को बचाने के लिए बड़े अभियान का आगाज किया। उन्होंने इस अवसर पर बच्चों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने बच्चों को थर्ड स्ट्रेन के बचाव की दवा किट के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर 75 जिलों की ओर रवाना किया। योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए अभी से कमर कस ली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अपने सरकारी आवास से किट की खेप को जिलों से लिए रवाना किया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव वाली दवा की किट जिलों को भेजी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों और किशोरों को संक्रमण से बचाने के लिए दवाओं की किट जिलों को रवाना की है। उन्होंने अपने सरकारी आवास पांच कालिदास मार्ग से बच्चों की दवा की किट वाली गाडियों को हरी झंडी दिखाकर जिलों के लिए रवाना किया।

इन गाडियों में बच्चों को थर्ड स्ट्रेन से बचाने के लिए अभी 17 लाख दवाओं की किट जिलों को भेजी गई हैं। आगे 33 लाख दवाओं की किट और भेजी जाएंगी। प्रदेश के 75 जिलों में कुल 50 लाख किट भेजी जानी हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि कोरोना वायरस से जान गंवाने वालों को हमारी श्रद्धांजलि। हम उत्तर प्रदेश में अब तीसरी लहर से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। इस दौरान कई जिलों में कोरोना केस आने ही बंद हो गए, लेकिन हम सेकेंड स्ट्रेन को लेकर अभी भी काफी सजग हैं। हमने प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के दोनों स्ट्रेन को तेजी से कंट्रोल किया है।

यह तो सर्वविदित है कि टीम वर्क से हर लड़ाई जीती जा सकती है। इसी कारण हमको भी बेहतरीन प्रबंधन से कामयाबी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन से ही हम अच्छा प्रदर्शन कर पाए। इसी कारण यूपी का मॉडल देश-दुनिया के सामने है।

उन्होंने कहा कि अब हम कोरोना वायरस संक्रमण की थर्ड स्ट्रेन से लडने की तैयारी कर रहे हैं। इसी कारण प्रदेश में हर मेडिकल कॉलेज तथा जिला अस्पतालों में बच्चों के आइसीयू (पीकू) वार्ड तेजी से स्थापित हो रहे हैं। थर्ड वेव को लेकर निगरानी समितियां अच्छा काम कर रही हैं। इनके साथ ही आंगनबाड़ी व आशा वर्कर ने अच्छा काम किया है। हमारी तरफ से सभी कोरोना योद्धाओं का अभिनंदन है। अब आज ग्रामीण क्षेत्र भी सुरक्षित हैं। इसी कारण हमने बच्चों के लिए भी वैक्सीन आने से पहले दवा की किट की व्यवस्था की है। कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के हमारे प्रयास की डब्ल्यूएचओ तथा नीति आयोग ने सराहना की है। अब प्रदेश के 19 जिलों में कोई नया मामला नहीं है।

डीएमसीएच में कोरोना संक्रमित दो मरीजों की मौत, जांच में 15 नए मरीज मिले

दरभंगा । जिले में नए कोरोना संक्रमितों के मिलने और लोगों के मरने का सिलसिला जारी है। हालांकि, पिछले कुछ दिनों से धीरे-धीरे इसका प्रकोप कम होने लगा है। कोरोना से मौत, जांच में पॉजिटिव लोगों की संख्या में कमी, एक्टिव केस में कमी, दरभंगा मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल (डीएमसीएच) में मरीजों की भर्ती में कमी और होम आइसोलेशन में भर्ती मरीजों की संख्या में कमी के साथ-साथ कोरोना को मात देनेवालों की संख्या में इजाफा हो रहा है । इधर , डीएमसीएच में इलाज के लिए आनेवाले पांच जिलों के लिए सोमवार को एक अच्छी खबर रही । सुपौल, बेगूसराय, सहरसा समस्तीपुर और मधुबनी जिला के किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई । जबकि, डीएमसीएच में दरभंगा के दो मरीजों की जान चली गई। 24 घंटे में विभिन्न स्तरों पर हुई जांच में 15 नए संक्रमित मरीज मिले हैं । बता दें कि इस अवधि में कुल पांच हजार से अधिक लोगों के नमूनों की जांच की गई है । इसी के साथ जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 9562 पर पहुंची हैं ।

जिले से आज कुल 23 मरीज स्वस्थ होकर अस्पताल से घर के लिए विदा हुए। जिले में एक्टिव केस की संख्या लगातार घट रही है। जिले में कुल 185 एक्टिव मरीज हैं । इसमें डीएमसीएच में 37 मरीज भर्ती है ।

दरभंगा में सरकारी अभिलेख गबन के आरोप में नौ तत्कालीन दारोगा पर प्राथमिकी दर्ज

दरभंगा । लहेरियासराय थाने के नौ तत्कालीन दारोगा पर सरकारी अभिलेख गबन करने की प्राथमिकी दर्ज की गई है। इससे 2001 से लेकर अब तक 22 कांडों पर कुंडी मारकर बैठे नौ अनुसंधान दारोगा की मुश्किलें बढ़ गई है। कार्रवाई की जद में बिरौल के एक तत्कालीन एसडीपीओ भी शामिल हैं। हालांकि, उनके नाम की चर्चा प्राथमिकी में नहीं की गई है। यह लिखा गया हैं कि कांड संख्या 264/01 के अनुसंधानकर्ता अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिरौल के नाम से पुलिस निरीक्षक इंडेक्स में अंतिम दैनिकी संख्या 13 में 24 फरवरी 2009 की तिथि में अंकित है। आरोपित किए गए तत्कालीन दारोगा में जगदीश महतो, अबुलेश खां, महानंद यादव, ब्रजेश पाठक, कृष्ण चौधरी, मारकण्डेय ड्क्षसह, निर्मल राम और डीएन शर्मा का नाम शामिल है।

इसमें तत्कालीन दारोगा में जगदीश महतो पर कांड संख्या 202/12, 214/12, 286/12, 292/12, 447/12, 461/12, अबुलेश खां पर कांड संख्या 285/10, महानंद यादव पर 226/12, ब्रजेश पाठक पर 323/19, 371/19, कृष्ण चौधरी पर कांड संख्या 483/12, 295/12, 154/12, 247/12, 518/12, मारकण्डेय ड्क्षसह पर कांड 266/15, निर्मल राम पर 499/14 और डीएन शर्मा पर 562/13, 354/13, 402/13 और कांड संख्या 245/15 की संचिका गबन करने का आरोप है।

बेंगलुरु के सिटी रेलवे स्टेशन पर एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता कोविड-19 के लिए यात्रियों के परीक्षण से ब्रेक के बीच आराम करते हुए।

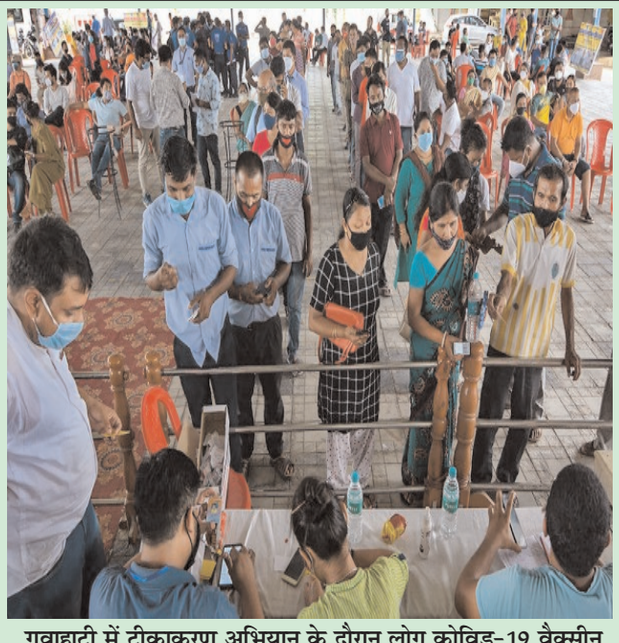

गुवाहाटी में टीकाकरण अभियान के दौरान लोग कोविड-19 वैक्सीन की एक खुराक प्राप्त करने की प्रतीक्षा करते हुए।

एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता गुवाहाटी के एक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड-19 परीक्षण के लिए एक इंडिगो कर्मचारी का स्वाब नमूना एकत्र करते हुए।

एक नजर

गलवन में झड़प का एक साल - फायर एंड फ्यूरी कोर और भारतीय सेना ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि

नई दिल्ली । पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गलवन घाटी में चीनी सैनिकों के साथ भारतीय जवानों की खूनी झड़प के एक साल पूरे हो गए हैं। पिछले साल 15 जून को पूर्वी लद्दाख सेक्टर में चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। इस मौके पर फायर एंड फ्यूरी कोर ने इन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। कोर के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल आकाश कौशिक ने लेह में युद्ध स्मारक पर पुष्पमाला अर्पित की। बता दें कि वार मेमोरियल पर उन सभी 20 शहीदों के नाम लिखे हैं, जिन्होंने अपने से दोगुने से भी अधिक चीनी सैनिकों को मार भगाकर दुश्मन में कभी न भूलने वाली दहशत पैदा कर दी थी।

भारतीय सेना ने भी गलवन घाटी में शहीद अपने सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सेना ने कहा कि थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवाने और सेना के सभी रैंक के अफसर उन बहादुरों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करते हुए गलवन घाटी में सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी वीरता राष्ट्र की स्मृति में सदैव अंकित रहेगी।

भारतीय सेना और मजबूती के साथ उभरी, नरम पड़े चीन के तेवर

पूर्वी लद्दाख के गलवन में पिछले साल आज ही के दिन (15 जून, 2020) भारतीय जवानों ने चीनी सेना को कभी न भूलने वाला सबक सिखाया था। चीनी सेना को सबक सिखाने वाली सेना की 16 बिहार रेजीमेंट के शहीदों के पदचिह्नों पर चल रहे भारतीय सेना के जवानों का जोश सातवें आसमान पर है। शहादत पाने वाले गलवन के वीरों से प्रेरणा लेकर भारतीय सेना के जवान चीन से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा पर (एलएसी) की रक्षा करने के लिए डटे हुए हैं। गलवन के वीरों की शहादत का एक साल पूरा होने पर पूर्वी लद्दाख के गलवन वार मेमोरियल में मंगलवार को शहीदों के सम्मान में होने वाला कार्यक्रम दुर्गम हालात में दुश्मन के सामने डटे भारतीय वीरों के देश पर मर मिटने के जज्बे को और बल देगा।

महाराष्ट्र में भी हो रहा है कोविड की पुरानी मौतों का समायोजन, जिलावार विवरण ने खोला राज

मुंबई । कोविड की दूसरी लहर परवान चढ़ने के बाद सोमवार को पहली बार नए मरीजों की संख्या 10,000 से कम एवं कोविड से हुई मौतें भी सबसे कम, यानी 200 हुईं। लेकिन राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों की ओर से जारी दैनिक आंकड़ों से पता चलता है कि महामारी के दौरान पहले हुई मौतें भी अब सामने लाई जा रही हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 14 जून को एक दिन की कोविड मौतों का आंकड़ा जहां 200 बताया गया है, वहीं यह भी स्पष्ट किया गया है कि इनमें 132 मौतें पिछले 48 घंटे में एवं 68 पिछले सप्ताह भर में हुई हैं। जबकि विभिन्न जिलों एवं स्थानीय निकायों में एक सप्ताह से पहले हुई ऐसी मौतों की संख्या 1392 रही है, जिन्हें अब तक कोविड पोर्टल पर दिखाया नहीं जा सका था। राज्य सरकार द्वारा इन 1392 मौतों का जिलावार विवरण भी जारी किया गया है। इससे पता चलता है कि सिर्फ सोमवार का बताकर जारी किए गए मौतों के आंकड़े में न सिर्फ एक सप्ताह की मौतें शामिल हैं, बल्कि उससे पहले की अब तक सामने न आई मौतों को मिलाकर यह संख्या 1592 हो जाती हैं।

सामने आ रहे हैं पुराने आंकड़े - राज्य सरकार द्वारा इसी पद्धति से पेश किए गए आंकड़ों को सही माना जाए तो 13 जून को सामने आई कुल मौतों की संख्या 2,771 बैठती है। 12 जून को सामने आई मौतों की संख्या 1966 होती है। 11 जून की 2619 होती है। 10 जून की 1915 होती है। 9 जून की 661, 8 जून की 702 एवं 7 जून की संख्या 340 बैठती है। इससे यह भी पता चलता है कि राज्य में जैसे-जैसे कोविड के नए मरीजों की संख्या कम हो रही है, वैसे-वैसे कोविड से हुई मौतों के पुराने आंकड़े सामने आ रहे हैं। प्रशासनिक सूत्रों की मानें तो कोविड से हुई मौतों के आंकड़ें विभिन्न स्रोतों से सरकार के पास पहुंचते हैं। इनमें विशेष तौर पर इस बार मरीजों की उनके घरों में हुई मौतें भी शामिल होती हैं। ये मौतें उसी दिन कोविड पोर्टल पर दर्ज नहीं हो पातीं। उन्हें बाद में पता चलने पर दर्ज किया जाता है। ऐसी ही मौतें अब सप्ताह भर से पहले हुई मौतों के रूप में सामने आ रही हैं।

मुंबई के धारावी में रुकी संक्रमण की रफ्तार, नहीं मिला एक भी नया संक्रमित

मुंबई । कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर आने के बाद पहली बार देश की सबसे बड़ा स्लम एरिया धारावी में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। इस इलाके में वर्तमान समय में सक्रिय मामलों की संख्या मात्र 13 बतायी गई है जबकि दो माह पहले 1 हजार से अधिक थे। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के अनुसार, नागरिक अधिकारियों के प्रयासों के अलावा यहां के निवासी निर्देशों का पालन करने में सक्रिय थे। इसलिए संक्रमण को नियंत्रित करने में मदद मिली। इसके अलावा संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए गैर सरकारी संगठनों और स्वयंसेवकों की भागीदारी ने भी बहुत मदद की। पिछले साल 1 अप्रैल में धारावी में कोरोना संक्रमण का पहला मामला दर्ज किया गया था। अब तक यह सातवीं बार है जब झुग्गी में एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ। यह सोमवार को दूसरी लहर में पहली बार हुआ। दूसरी लहर के दौरान धारावी में दर्ज किए गए एकल-दिवसीय मामलों की संख्या इस साल 8 अप्रैल को 99 थी। इसके बाद, यह संख्या पूरे अप्रैल में 60 और 70 के बीच रही, कभी-कभी 50 तक गिर गई। मई में ही यह 50 से नीचे चला गया था और मई के अंत तक यह 20 से नीचे गिरना शुरू हो गया था। जून के पहले सप्ताह में कुछ उम्मीदें दिखी क्योंकि सक्रिय मामले कम होने लगे और कम दैनिक मामले दर्ज किए गए। क्षेत्र के 13 सक्रिय मामलों में से छह होम क्वारंटाइन में हैं, तीन आइसोलेशन सेंटर में और चार अस्पताल में भर्ती हैं। सूत्रों के अनुसार क्षेत्र में टीकाकरण अभियान की गति तेज होने से संक्रमण को और फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। क्षेत्र में अब तक 22,000 से अधिक लाभार्थियों का टीकाकरण किया जा चुका है। क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों और स्वयंसेवकों के साथ समन्वय में नागरिक अधिकारियों ने नागरिकों तक पहुंचना शुरू कर दिया है ताकि वे टीका लगवा सकें। संक्रमित लोगों को समय पर आइसोलेट किया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए बीएमसी वार्ड कार्यालय क्षेत्र में बड़ी संख्या में परीक्षण कर रहा है। सहायक नगर आयुक्त, किरण दिघवकर ने कहा, मोबाइल परीक्षण वैन, घर-घर स्क्रीनिंग और हमारे अधिकारियों, स्वयंसेवकों और गैर सरकारी संगठनों के समन्वित प्रयासों ने इस लक्ष्य को बार-बार हासिल करने में मदद की है।

केंद्र सरकार ने सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए

नई दिल्ली । कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने सोमवार को अंडर सेक्रेटरी और उससे ऊपर के स्तर के सभी अधिकारियों को 16 जून से 30 जून तक सभी कार्य दिवसों पर कार्यालयों में उपस्थित रहने का निर्देश दिया। दिव्यांग व्यक्ति और गर्भवती महिला कर्मचारी घर से काम करना जारी रखेंगे। अंडर सेक्रेटरी से नीचे के स्तर के 50 प्रतिशत सरकारी अधिकारी सभी कार्य दिवसों पर कार्यालय में उपस्थित होंगे और शेष घर से काम करेंगे। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को जारी आदेश में यह बात कही गई है। कोरोना के मामलों और पॉजिटिविटी रेट में रेट में भारी गिरावट आने के बाद कार्मिक मंत्रालय ने सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों की उपस्थिति को लेकर यह दिशानिर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अंडर सेक्रेटरी और उससे ऊपर के स्तर के सभी सरकारी कर्मचारी सभी कार्य दिवसों पर कार्यालय में उपस्थित रहें। सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को कोरोना संबंधी नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

आदेश में कहा गया है कि बार-बार हाथ धोना/सेनिटाइजेशन, मास्क पहनना, हर समय शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। इस संबंध में जरा भी ढिलाई को गंभीरता से लिया जाएगा। कार्यालयों में भीड़भाड़ से बचने के लिए अधिकारी/कर्मचारी अलग-अलग समय यहां आएंगे - सुबह 9 से शाम 5.30 बजे तक, सुबह 9.30 से शाम 6 बजे तक, और सुबह 10 से शाम 6.30 बजे तक। आदेश में यह भी कहा गया है कि दिव्यांग व्यक्तियों और गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय में आने से छूट जारी रहेगी, लेकिन उन्हें अगले आदेश तक घर से काम करना होगा। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को तब तक कार्यालयों में आने से छूट दी जाएगी जब तक कि वो इलाका कंटेनमेंट जोन से बाहर नहीं आ जाता। वे अधिकारी/कर्मचारी जो कार्यालय नहीं आ रहे हैं वे घर से काम करेंगे और वे हर समय संपर्क के लिए टेलीफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर उपलब्ध रहेंगे। बैठक, जहां तक संभव हो वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित होगी। ये निर्देश 16 जून से 30 जून तक लागू रहेंगे। आदेश में कहा गया है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस फिलहाल नहीं लगेगा और अगले आदेश तक रजिस्टर का इस्तेमाल होगा।

ट्विटर को संसदीय स्थायी समिति का समन, 18 जून को संसद परिसर में होगा जवाब-तलब

नई दिल्ली । सूचना व प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने ट्विटर को समन भेजा है। दरअसल इंटरनेट जगत से जुड़े अधिकारों व सुरक्षा मामलों पर जवाब तलब के लिए ट्विटर को संसद परिसर में बुलाया गया है। इस क्रम में संसदीय स्थायी समिति ने 18 जून को माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट से 18 जून को संसद में पेश होने को कहा है। यह मामला जनता के अधिकारों व सोशल व ऑनलाइन न्यू मीडिया प्लेटफार्म के दुरुपयोग के अलावा डिजिटल स्पेस में महिला सुरक्षा से जुड़ा है।

बता दें केंद्र व ट्विटर के बीच नए IT नियमों को लेकर मतभेद है। समिति के पैनल के समक्ष 18 जून शाम 4 बजे ट्विटर की ओर से यह बताया जाएगा कि सोशल मीडिया व ऑनलाइन न्यूज के दुरुपयोग को कैसे रोका जा सकता है। उल्लेखनीय है कि इस साल फरवरी में केंद्र की ओर से ट्विटर को कुछ कंटेंट ब्लॉक करने को कहा गया था। इसके बाद सरकार नए ढ्ढञ्ज नियम के साथ आई। इन्हीं नियमों को लेकर ट्विटर और केंद्र के बीच तकरार है।

पैनल सदस्यों के सूत्रों ने बताया कि हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि किस वजह से ट्विटर देश में बनाए गए नए नियमों को मानने से इनकार कर रहा है। इससे पहले भी कई मुद्दों पर संसदीय समिति ने Twitter को समन भेजा है। ट्विटर के प्रवक्ता ने कहा, भारत के लिए ट्विटर प्रतिबद्ध रहा है। हमने भारत सरकार को इस बात को सुनिश्चित कराया है कि नए दिशानिर्देशों पर चलने के लिए हमारी ओर से भरसक प्रयास किया जा रहा है।

हाल में ही केंद्र ने ट्विटर को नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि बार-बार मंत्रालय की ओर से पत्र दिए जाने के बावजूद ट्विटर की ओर से पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। MeitY में साइबर कानूनों के ग्रुप कोऑर्डिनेटर राकेश माहेश्वरी ने ट्विटर को यह पत्र लिखा है।

सुप्रीम कोर्ट ने इटली के नाविकों के मामले को किया बंद, परिजनों को मिलेगा 4-4 करोड़ मुआवजा

नई दिल्ली, एजेंसी । सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फरवरी 2012 में केरल तट पर दो मछुआरों की हत्या के आरोपी दो इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ भारत में आपराधिक कार्यवाही बंद करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एमआर शाह की अवकाशकालीन पीठ ने दोनों इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ मामले से जुड़ी प्राथमिकी और कार्यवाही को रद्द कर दिया।

पीठ ने कहा कि भारत द्वारा स्वीकार किए गए अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थ निर्णय के अनुसार, इटली गणराज्य मामले में आगे की जांच फिर से शुरू करेगा। शीर्ष अदालत ने इटली गणराज्य द्वारा भुगतान किए गए 10 करोड़ रुपये के मुआवजे को उचित और पर्याप्त करार दिया। इससे पहले कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि पीड़ितों के परिवार के हितों की रक्षा के लिए मुआवजे का पैसा केरल हाई कोर्ट में जमा किया जाए।

बता दें कि वर्ष 2012 में इटली के दो नाविकों ने दो भारतीय मछुआरों की हत्या कर दी थी। भारत ने इटली के तेल टैंकर एमवी एनरिका लेक्सी पर तैनात दो इतालवी नाविकों -सल्वाटोरे गिरोने और मैस्सीमिलियानो लटोरे पर भारत के आर्थिक क्षेत्र में 15 फरवरी 2012 को मछली पकड़ने वाली नौका में सवार दो भारतीय मछुआरों की गोली मार कर हत्या करने का आरोप लगाया था।

हत्या के मामले में दोनों नाविकों को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बाद में अंतरराष्ट्रीय पंचाट के फैसले के अनुसार दोनों नाविकों को इटली की जेल भेज दिया गया और नाविकों को 10 करोड़ का मुआवजा देने का फैसला किया गया। अब ये मुआवजा मिल चुका है। इसमें से चार-चार करोड़ रुपये उन नाविकों के स्वजनों को दिए जाएंगे और दो करोड़ रुपये उस नौका मालिक को मिलेंगे जिसकी नाव में सवार होकर ये मछुआरे मछली पकड़ने समुद्र में गए थे।

केंद्र ने जुलाई 2020 को शीर्ष अदालत में इतालवी नाविकों के खिलाफ चल रही कार्यवाही बंद करने के लिये एक आवेदन दायर किया था। केंद्र ने कहा था कि उसने हेग स्थित पंचाट की स्थाई अदालत का 21 मई, 2020 का फैसला स्वीकार कर लिया है कि भारत इस मामले में मुआवजा पाने का हकदार है, लेकिन नाविकों को प्राप्त छूट की वजह से वह इन पर मुकदमा नहीं चला सकता।

माइंस संचालक से रुपये मांगने का आरोपित आरएएस ऑफिसर जयपुर से गिरफ्तार

उदयपुर । एक माइंस मालिक से मासिक पचास हजार रुपये मांगने के मामले में सोमवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने प्रदेश के राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (आरएएस) के एक ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। आरोपित आरएएस ऑफिसर उदयपुर जिले के लसाड़िया के उपखंड अधिकारी के रूप में नियुक्त हैं। एसीबी के मामला दर्ज किए जाने के बाद से आरएएस ऑफिसर फरार हो गए थे। गिरफ्तारी के बाद आरोपित आरएएस ऑफिसर को उदयपुर लाया जा रहा है, जहां मंगलवार को उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। उदयपुर जिले के लसाड़िया के उपखंड अधिकारी सुनील झिंगोनिया के खिलाफ एक माइंस कारोबारी ने एसीबी मुख्यालय जयपुर में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसकी जांच विशेष अनुसंधान इकाई कर रही थी।

जिसमें माइंस कारोबारी ने आरोप लगाया कि लसाड़िया के उपखंड अधिकारी सुनील झिंगोनिया उनकी वैध तरीके संचालित माइंस को बंद कराने की धमकी देकर हर महीने पचास हजार रुपये की मासिक बंधी के लिए धमकी दे रहे हैं। इस शिकायत का सत्यापन चित्तौड़गढ़ एसीबी टीम के जरिए कराया गया। एसीबी की टीम उनके खिलाफ ट्रेप की कार्रवाई करती उससे पहले भनक लगते ही वह फरार हो गए। किन्तु उनके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच एसीबी के उप अधीक्षक सचिन शर्मा को सौंपी गई। एसीबी की टीम उनकी तलाश में जुटी थी। एसीबी ने उनके लसाड़िया स्थित सरकारी आवास, चित्तौड़गढ़ और जयपुर के आवास पर सर्चिंग की कार्रवाई की योजना बनाई। इसी बीच पता चला कि आरोपित आरएएस ऑफिसर सुनील झिंगोनिया अपने मुरलीपुरा स्थित निजी आवास पर मौजूद हैं। एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर पहुंची टीम ने उन्हें जयपुर स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर की टीम ने सोमवार को पेट्रोल पंप के लिए भूमि रूपांतण के एवज में पचास हजार रुपये की रिश्वत लेते सलूम्बर तहसील कार्यालय से एक पटवारी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। उसने भूमि रूपांतरण के एवज में डेढ़ लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी और पिछले छह महीने से मामले को लटकाए हुए था। सलूम्बर निवासी भूपेन्द्र मीणा ने तहसील कार्यालय के पटवारी राजेंद्र चौहान के खिलाफ शिकायत की थी। जिसमें उसने बताया कि उसने अपनी पत्नी के नाम पेट्रोल पंप के लिए आवेदन किया था और उसके लिए सभी तैयारियां कर ली थीं। किन्तु भूमि रूपांतरण के बगैर पेट्रोल पंप की स्वीकृति रूकी हुई थी। उसने अपनी पत्नी के नाम की कृषि भूमि के भूमि रूपांतण को लेकर छह महीने पहले पटवार कार्यालय में आवेदन किया था। पिछले छह महीने से पटवारी राजेंद्र चौहान उसे टालता आ रहा था। पिछले दिनों ने उसने भूमि रूपांतरण के एवज में डेढ़ लाख रुपए की रिश्वत की पेशकश की थी।

जिसकी शिकायत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर की टीम ने सत्यापित की और सोमवार को ट्रेप की कार्रवाई को अंजाम दिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा ने बताया कि पटवारी राजेंद्र चौहान ने रिश्वत की राशि के साथ भूपेंद्र मीणा को तहसील कार्यालय बुलाया था। जहां उसके रिश्वत लेते के बाद इशारा मिलते ही एसीबी की टीम ने उसे धर दबोचा। एसीबी ने प्रकरण से संबंधित फाइल भी जब्त की है। गिरफ्तार पटवारी को उदयपुर लाया गया है और उसे पूछताछ जारी है। एएसपी ओझा ने बताया कि उसके यहां भूमि रूपांतरण और अन्य लंबित मामलों से जुड़ी फाइलों को खंगाला जाएगा और उनके आवेदकों से पूछताछ की जाएगी। साथ ही पिछले एक साल में उसके द्वारा किए गए भूमि रूपांतरण एवं अन्य मामलों की भी जांच की जाएगी।

गुजरात में कोरोना संक्रमण के 405 नए मामले, मौत का कुल आंकड़ा 10 हजार के पार

अहमदाबाद । गुजरात में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 8 लाख के पार चली गई है। वही कोरोना से मरने वालों की संख्या 10003 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 405 केस दर्ज किए गए जबकि 6 लोगों की मौत हुई। राज्य में कोरोना के सक्रिय केसों की संख्या 9542 है जबकि अब तक 8 लाख 01181 लोग स्वस्थ होकर घर पहुंच गए हैं। राज्य में अब तक कुल 8 लाख 20731 लोग संक्रमित हो चुके हैं। अहमदाबाद महानगर पालिका में 47 केस दर्ज किए गए जबकि मरने वालों की संख्या 2 रही। वडोदरा में 37 केस 0 मौत, सूरत में 54 केस 1 की मौत, जामनगर में 8 केस 0 मौत, भावनगर में 2 केस मौत शून्य, जूनागढ़ में 12 केस मौत का आंकड़ा शून्य, वही गांधीनगर में भी संक्रमण के 8 मामले सामने आए जबकि मौत का आंकड़ा शून्य रहा।

पिछले 24 घंटे में 8 में से 5 महानगर पालिकाओं में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई इनमें वडोदरा, जूनागढ़, जामनगर, गांधीनगर तथा भावनगर महानगर पालिका शामिल है। विविध जिलों में कोरोना संक्रमण के आंकड़े इस प्रकार रहे सूरत में कोरोना संक्रमण के 24 केस दर्ज किया गए। वडोदरा 24, जूनागढ़ 18, पोरबंदर 16, राजकोट 13, अमरेली 12, भरूच नो खेड़ा 8, पंचमहाल 7, आणंद 6, साबरकांठा 4, जामनगर 3, अरवल्ली 3 जबकि अहमदाबाद जिला बोटाद, छोटा उदेपुर, दाहोद, मेहसाणा, पाटण, सुरेंद्रनगर में संक्रमण का एक भी नया मामला सामने नहीं आया।

गौरतलब है कि गुजरात में रविवार को कोरोना संक्रमण के 455 नए मामले सामने आये थे और छह संक्रमितों की मौत दर्ज की गई थी। कोरोना से स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 8 लाख के पार बताया गया था। वहीं राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 10249 थी जबकि कुल 8 लाख 75 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके थे।

43 फीसद उपभोक्ताओं ने 12 महीनों में नहीं खरीदा एक भी चीनी उत्पाद

नई दिल्ली । लद्दाख की गलवन घाटी में भारतीय व चीनी सैनिकों में हुए संघर्ष के एक साल बाद भी दोनों देशों के व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में इसका असर देखा जा सकता है। भारत सरकार ने सीमा पर हुए संघर्ष के बाद चीन को आर्थिक मोर्चे पर पटखनी देने और स्वदेशी उत्पादों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके जरिये देश को आर्थिक मोर्चे पर मजबूत करना चाहते थे, क्योंकि गत वर्ष कोरोना लाकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियां लंबे समय तक बंद रही थीं। बाद में सरकार ने टिकटाक समेत 100 चीनी एप को प्रतिबंधित कर दिया। गलवन घाटी संघर्ष के बाद भारतीय काफी गुस्से में थे। नवंबर 2020 के त्योहारी सीजन में इंटरनेट मीडिया लोकल सर्कल्स की तरफ से कराए गए सर्वे में 71 फीसद भारतीयों ने कहा था कि उन्होंने चीन निर्मित कोई भी सामान नहीं खरीदा।

ऐसे किया गया सर्वे- 281 जिलों में रहने वालों लोगों की 18 हजार प्रतिक्रियाएं ली गईं। प्रतिक्रिया देने वालों में 33 फीसद महिलाएं व 67 फीसद पुरुष थे। 44 फीसद लोग टियर एक, 31 फीसद टियर दो व 25 फीसद टियर तीन, चार और ग्रामीण इलाकों से थे।

पाकिस्तान सीमा से सटे राजस्थाान के जैसलमेर में जासूसी के आरोप में एक युवक गिरफ्तार

जयपुर । पाकिस्तान सीमा से सटे राजस्थाान के जैसलमेर में जासूसी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। जैसलमेर जिले के चांदण गांव निवासी युवक पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के जाल में फंसकर हैनीट्रैप का शिकार हुआ और जासूसी करने लगा। चांदण में भारतीय वायुसेना की फायरिंग रेंज है। यहीं का निवासी यह युवक हैं। सेना के महत्वपूर्ण परीक्षण यहां होते रहते हैं। परमाणु परीक्षण भी यहां हुए हैं।

सीमावर्ती यह इलाका सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है। यहीं से गिरफ्तार किए गए युवक पर सुरक्षा और इंटेलीजेंस एजेंसियों पिछले कई दिनों से नजर रख रही थी। सोमवार देर रात एटीएस और इंटेलीजेंस की टीम ने मोबाइल फोन की कॉल रिकॉर्ड के आधार पर युवक को गिरफ्तार किया है ।

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि युवक पाकिस्तान में बात होने के बाद कॉल की डिटेल को तत्काल हटा देता था। खुफिया एजेंसियों उसके मोबाइल फोन का डाटा रिकवर करने में जुटी है। यह पता किया जा रहा है कि उसने क्या-क्या जानकारी आईएसआई को भेजी है। एटीएस, इंटेलीजेंस और स्थानीय पुलिस युवक से पूछताछ में जुटी है।

प्रारंभिक पूछताछ में युवक ने बताया कि वह केवल पाकिस्तान में बात करता था, लेकिन यहां से जुड़ी कोई जानकारी शेयर नहीं की है। लेकिन उसने जिस तरह से मोबाइल का डाटा उड़ाया है, उससे युवक की बात पर यकीन नहीं हो पा रहा है। आईएसआई की स्लीपर सेल सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय है। पहले भी इससे जुड़े लोग पकड़े जा चुके हैं। जानकारी के अनुसार युवक मोबाइल फोन कॉल पर एक युवती से बात करता था। उसी के हनीट्रैप में वह फंसा है। सेना अथवा एटीएस ने फिलहाल गिरफ्तार किए गए युवक के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी है।

संदिग्ध कबूतर मिला

राजस्थान के ही पाक से सटे श्रीगंगानगर जिले के गांव 9 जीएम में एक संदिग्ध कबूतर मिलने से हड़कंप मच गया । कबूतर को देखते ही ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कबूतर को अपने कब्जे में लिया है। कबूतर के पंख पर लाल और नीले रंग के निशान के साथ एक मुहर लगी है। कुछ नंबर और शब्द उर्दू में भी लिखे हुए हैं। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां संदिग्ध कबूतर की जांच में जुटी है। उल्लेखनीय है कि श्रीगंगानगर में पिछले दिनों कुछ संदिग्ध गुब्बारे भी मिले थे, जिनके पाकिस्तान से आने की खबर है।

मैंने बॉलीवुड की रूढ़ियों को चुनौती दी

विद्या बालन ने अपनी भूमिकाओं से बॉलीवुड की रूढ़ियों को बार-बार चुनौती दी है, अपने किरदारों को दमदार अभिनय के साथ जिया है। अभिनेत्री का कहना है कि यह ऐसा कुछ नहीं था जो उन्होंने होशपूर्वक किया। जब से उन्होंने 2005 में 'परिणीता' के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरूआत की, विद्या ने 'भूल भुलैया', 'नो वन किल्ड जेसिका', 'द डर्टी पिक्च र', 'पा', जैसी फिल्मों में अपने काम से हिंदी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। 'कहानी', 'इश्किया', 'मिशन मंगल', 'तुम्हारी सुलु' और 'शकुंतला देवी'। वह अगली बार 'न्यूटन' निर्माता अमित मसुरकर की 'शेरनी' में दिखाई देंगी, जो उन्हें एक वन अधिकारी के रूप में पेश करेगी। राष्ट्रीय पुरस्कार और पद्मश्री से नवाजी गई विद्या ने कहा, ''मैं रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि जीवन में अपने अनुभवों के माध्यम से, विशेष रूप से एक अभिनेता के रूप में, मैंने महसूस किया है कि मैं अपने रास्ते में कुछ भी आने नहीं दूंगी।'' 42 वर्षीय अभिनेत्री ने आगे कहा, ''तो अगर आप मुझे बताते हैं कि मैं एक अभिनेता होने के लिए बहुत छोटी हूं और बहुत मोटी हूं। मैं बहुत बोल्ड हूं, बहुत बेशर्म या बहुत बुद्धिमान हूं या जो भी हूं, मैं सिर्फ रेन्डम बातें कह रही हूं, मैं नहीं बदल सकती कि मैं कौन हूं लेकिन मैं अभी भी अपना रास्ता खोज सकती हूं।'' उन्होंने कहा, ''मैं जो करती हूं उसके लिए मैंने खुद में जुनून देखा है क्योंकि मैं वास्तव में अपने बारे में कुछ भी नहीं बदल सकती, इसलिए मैंने रूढ़ियों को तोड़ने के लिए खुद को तैयार नहीं किया। मैंने सिर्फ इतना कहा कि अगर यह काम नहीं करता है, तो बहुत बुरा है इसे काम करना होगा, क्योंकि मैं इसके लिए काम करने जा रही हूं। इसे काम करना है क्योंकि मैं एक अभिनेता बनना चाहती हूं।'' अभिनेत्री, जिसने 16 साल की उम्र में सिटकॉम 'हम पांच' में अभिनय किया और सिटकॉम में राधिका की भूमिका निभाई, 'एक सचेत दिमाग के साथ स्टीरियोटाइप को चुनौती नहीं दी।' उन्होंने कहा ''तो, मुझे लगता है कि उन रूढ़ियों को जानबूझकर नहीं बल्कि शायद अनजाने में चुनौती दी गई थी।'' वर्तमान में, वह 'शेरनी' की रिलीज का इंतजार कर रही है, जहां वह पितृसत्तात्मकसमाज द्वारा निर्धारित सामाजिक बाधाओं और अपने विभाग के भीतर कमजोर रवैये से जूझ रही एक ईमानदार वन अधिकारी की भूमिका निभाती है। 'हम में से हर एक शेरनी है, लेकिन यह कहलाना बहुत अच्छा लगता है!' वह मुस्कुराई, और आगे कहा, ''वे सभी महिलाएं हैं जो अपने काम से अपनी पहचान बनाती हैं। वे अपने काम के प्रति बहुत भावुक हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं भी वह महिला हूं। इसलिए, मैं इन पात्रों की ओर बढ़ रही हूं। मुझे उद्देश्य वाली महिलाएं पसंद हैं और इसलिए मैं उन्हें चुनती हूं।'' विद्या ने आगे कहा, ''जितना अधिक मैं अपने चारों ओर देखती हूं, हम में से ज्यादा से ज्यादा उस उद्देश्य को ढूंढ रहे हैं, अपने सपनों को जी रहे हैं। मुझे लगता है कि यह हमारे आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है इसका भी प्रतिबिंब है क्योंकि सिनेमा वास्तविकता का प्रतिबिंब है।'' 'शेरनी' 18 जून को अमेजन प्राइम वीडियो पर डिजिटल रिलीज के लिए तैयार है।

कोविड के बाद खुद के प्रति होना होगा सहनशील

बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ ने कोरोना से उबरने के बाद सामान्य जिंदगी में वापस लौटने पर खुलकर बात कीं। कैटरीना ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा है, ''वापस आ गई। कोविड के बाद एक्सरसाइज में वापस लौटने की बात करूं, तो मुझे अपने साथ धैर्य बरतना होगा। आपको अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ना होगा और अपनी बॉडी की सुननी होगी। शुरू में भले ही अच्छा लगे, लेकिन फिर आप थका हुआ महसूस करेंगे। धीरे-धीरे आगे बढ़ें और अपनी बॉडी की ठीक होने की प्रक्रिया पर यकीन रखें। कदम-दर-कदम।'' कैटरीना इस साल की शुरूआत में कोरोना की चपेट में आई थीं और 17 अप्रैल को अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने अपनी रिकवरी का भी ऐलान किया था। कोरोना से ठीक होने के बाद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा था, ''नेगेटिव, उन सभी को धन्यवाद जिन्होंने बार-बार मेरी खबर ली और मुझे खूब सारा प्यार दिया। शुक्रिया।''

तापसी को डर है कि दिनेश पंडित की 'भयानक' किताब से सुजॉय घोष प्रेरित ना हो जाए

अभिनेत्री तापसी पन्नू, जो दिनेश पंडित द्वारा लिखी गई किताबों को पढ़ना पसंद करती हैं, उन्होंने सुजॉय घोष को भी लेखक की कहानियां पढ़ने पर मजबूर कर दिया है। तापसी को उम्मीद है कि फिल्म निर्माता इस थ्रिलर से प्रेरित नहीं होंगे। तापसी ने गुरुवार को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक तस्वीर पोस्ट की। तस्वीर में घोष हिंदी किताब 'डकैती 60 लाख की' पढ़ते नजर आ रहे हैं। तापसी ने कैप्शन में लिखा, ''मुझे आशा है कि वह अब इस थ्रिलर से प्रेरित नहीं होंगे। हैशटैग दिनेश पंडित।'' घोष ने किताब पढ़ने के बाद ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की। उन्होंने तापसी को टैग करते हुए लिखा, ''ये क्या भयानक किताब है यार। दिल की धड़कन बढ़ गई।'' तापसी को पंडित की 'डकैती 60 लाख की', 'हवस का आतंक' और 'प्यार का आतंक' जैसी किताबें पढ़ते हुए अपनी फोटोज इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी। अभिनेत्री जल्द ही मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म 'हसीन दिलरुबा' में दिखाई देंगी।

कोरोना से उबरने के बाद अपनी स्टैमिना को वापस लाने में जुटीं भूमि

अभिनेत्री भूमि पेडनेकर कोरोनावायरस महामारी से ठीक होने के बाद अपनी शारीरिक मजबूती पर काम कर रही हैं। भूमि ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट-वर्कआउट की अपनी एक तस्वीर साझा की हैं, जिसमें वह स्पोर्ट्स ब्रा और योगा पैंट्स में नजर आ रही हैं। तस्वीर को कैप्शन देते हुए अभिनेत्री ने लिखा है, ''कोविड के बाद स्टैमिना बढ़ाना मुश्किल है, लेकिन मुझे ऐसा करना अच्छा लग रहा है। हैशटैगहैप्पी हैशटैगग्रेटफुल हैशटैगस्ट्रॉन्ग।'' भूमि ने हाल ही में बताया कि वह अगली फिल्म 'रक्षा बंधन' में अक्षय कुमार के साथ नजर आएंगी। इसके अलावा, वह राजकुमार राव के साथ 'बधाई दो' और विक्की कौशल के साथ 'मिस्टर लेले' में भी दिखाई देंगी।

मनोज बाजपेयी के हाथ लगी नेटफ्लिक्स की नई वेब सीरीज

एक्टर मनोज बाजपेयी अपनी हालिया रिलीज हुए 'द फैमिली मैन 2' की सफलता के बाद इन दिनों सातवें आसमान पर हैं। इस वेब सीरीज में एक बार फिर उन्होंने अपने बेहतरीन अभिनय का परिचय दिया है। इसी बीच एक्टर को लेकर एक और गुड न्यूज आई है। रिपोर्ट की मानें तो मनोज ने एक और वेब सीरीज साइन कर ली है।

अभिषेक चौबे और मनोज की बनेगी जोड़ी

पीपींगमून की रिपोर्ट के मुताबिक, 'द फैमिली मैन 2' की सफलता के बाद नेटफ्लिक्स ने अपनी एक नई वेब सीरीज के लिए मनोज बाजपेयी से संपर्क किया है। इस सीरीज के निर्देशन की कमान अभिषेक चौबे संभालेंगे, जो 'मकबूल' और 'इश्किया' जैसी फिल्मों के निर्देशक रह चुके हैं।

ब्लैक कॉमेडी होगी नेटफ्लिक्स की अपमकमिंग वेब सीरीज

मनोज बाजपेयी की इस अपमकमिंग वेब सीरीज का टाइटल तय नहीं हुआ है। लेकिन रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि आने वाली यह वेब सीरीज एक ब्लैक कॉमेडी होगी। इसमें साउथ सिनेमा के भी कई शानदार चेहरे दिखाई देंगे और फीमेल लीड का भी एक अहम रोल होगा। इसके लिए अभिनेत्री को साइन भी कर लिया गया है। मनोज जल्द ही वेब सीरीज 'रे' दिखाई देंगे, जिसका का ट्रेलर भी रिलीज हो गया है। यह सीरीज जो भारतीय सिनेमा के महान फिल्मकार सत्यजीत रे की कहानियों पर आधारित है। इसमें मनोज बाजपेयी भी अहम भूमिका निभा रहे हैं।

कृति सैनन ने 'आदिपुरुष' को बताया अपना सबसे रोमांचक प्रोजेक्ट

अभिनेत्री कृति सैनन का कहना है कि आगामी पीरियड ड्रामा 'आदिपुरुष' उनके अब तक के सबसे रोमांचक प्रोजेक्टस में से एक है। फैन्स के साथ इंटरेक्टिव सेशन में एक यूजर ने उनसे इस फिल्म के बारे में बात करने को कहा। फिल्म के निर्देशक ओम राउत के लिए एक नोट के साथ कृति ने जवाब दिया, ''मेरी सबसे रोमांचक परियोजनाओं में से एक है। इसके हर हिस्से का बिल्कुल अलग अनुभव है।'' फिल्म 'रामायण' का एक रूपांतरण है, जिसमें तेलुगु स्टार प्रभास भगवान राम के रूप में हैं, जबकि बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान ने रावण का किरदार निभाया है। एक प्रशंसक ने उनसे तेलुगु स्टार महेश बाबू का एक शब्द में वर्णन करने के लिए भी कहा। संयोग से, महेश बाबू उनकी 2014 में पहली डेब्यू फिल्म '1 नेनोक्कादीन' में उनके को स्टार थे। कृति ने जवाब दिया, ''बेस्ट, मेरे पहले सह कलाकार। इतने विनम्र और इतने अद्भुत। मुझे उम्मीद है कि मुझे उनके साथ फिर से काम करने का मौका मिलेगा।'' सफलता और असफलता को संभालने के सवाल पर कृति ने कहा, ''मेरा मंत्र सफलता को कभी भी अपने सिर पर न चढ़ने दें, असफलता को कभी भी अपने दिल पर न चढ़ने दे।'' एक प्रशंसक ने उनकी फिल्म 'मिमी' की रिलीज के बारे में पूछा, जिस पर अभिनेत्री ने कहा कि वह खुलासा नहीं कर सकती हैं लेकिन यह जल्द ही होगा।

जब रिश्ता टॉक्सिक हो जाए तो निकलना ही सही है

बॉलीवुड एक्ट्रेस और बिग बॉस सीजन 8 की कंटेस्टेंट रही मिनिषा लांबा अपने पति रेयान थाम से अलग होने के एक साल बाद तलाक को लेकर कुछ ऐसा कहा है, जिसे लेकर काफी बातें की जा रही हैं। एक्ट्रेस ने अपने बयान में कहा है कि पहले रिश्ते में सिर्फ महिलाओं को ही त्याग करना पड़ता था, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। इसके अवाला उन्होंने ये भी कहा कि अगर रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाए तो निकलना ही सही विकल्प होता है।

सभी को खुशी से जीने का अधिकार है

खास बातचीत में अभिनेत्री ने बॉलीवुड में अपने संघर्ष से लेकर अपनी आने वाले प्रोजेक्ट और पर्सलाइफ जुड़े कई सवालों का बिंदास जवाब दिया है। हालिया इंटरव्यू में यह पूछे जाने पर कि क्या से पति से तलाक लेना कठीन था, इस पर एक्ट्रेस ने कहा, ' मैं इसे इस तरह कहना चाहूंगी- सभी को खुशी से जीने का अधिकार है। हमारे समाज में तलाक को बहुत गलत कहा जाता रहा है। लेकिन ,अब महिलाएं आत्मनिर्भर हैं और अपनी आवाज उठाने और अपनी विचारों को स्वतंत्र रूप से रखने में सक्षम हैं।

महिलाएं अब अपने अधिकार के प्रति जागरूक हैं

वह आगे कहती हैं कि पहले संबंधों को निभाने की सारी जिम्मेंदारी औरतों पर हुआ करती थी। इतना ही नहीं रिश्ते को बचाए रखने के लिए सभी कुर्बानी उन्हें देनी पड़ती है लेकिन अब महिलाएं इस बात को समझ गई हैं कि अगर वह खुश नहीं हैं तो उन्हें उस रिश्ते से निकल जाने का पूरा अधिकार है। वह सेल्फ लव पर जोर देते हुए कहती हैं कि तलाक लेना आसान नहीं होता हैल लेकिन जब रिश्ता ही टॉक्सिक बन जाए तो उससे निकल जाना ही सही है।

तलाक, शादी और प्यार को लेकर कोई बुरी फीलिंग नहीं

वह आगे कहती हैं कि रिश्ता या शादी आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है, लेकिन यह आपका पूरा जीवन नहीं हो सकता। दुर्भाग्य से, महिलाओं को उनके रिश्तों और वैवाहिक स्थिति से पहचाना जाता है। हालांकि, चीजें अब बदल रही हैं।'' उसने यह भी कहा कि उनके मन में अब तलाक, शादी और प्यार को लेकर कोई कड़वाहट नहीं है।

मिनिषा अपकमिंग फिल्म

मिनिषा लांबा ने साल 2005 में शूजीत सरकार की डेब्यू फिल्म 'यहां' से अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म से उन्हें ओशियन सिनेफैन फिल्म फेस्टिवल में स्पेशल ज्यूरी का अवॉर्ड मिला था। इस फिल्म के अवाला लाबां को रणबीर कपूर के साथ फिल्म बचना ए हसीनों में देखा गया। इस फिल्म के इतर उन्हें कॉर्पोरेट, रॉकी, एंथनी कौन है, अनामिका और दस कहानियां जैसी फिल्मों में देखा गया। अब मिनिषा लांबा जल्द ही अपकमिंग कॉमेडी फिल्म 'कुतुब मीनार' में नजर आने वाली हैं।

निर्माता जैकी भगनानी के साथ एक्शन फिल्म में काम करेंगे अक्षय कुमार!

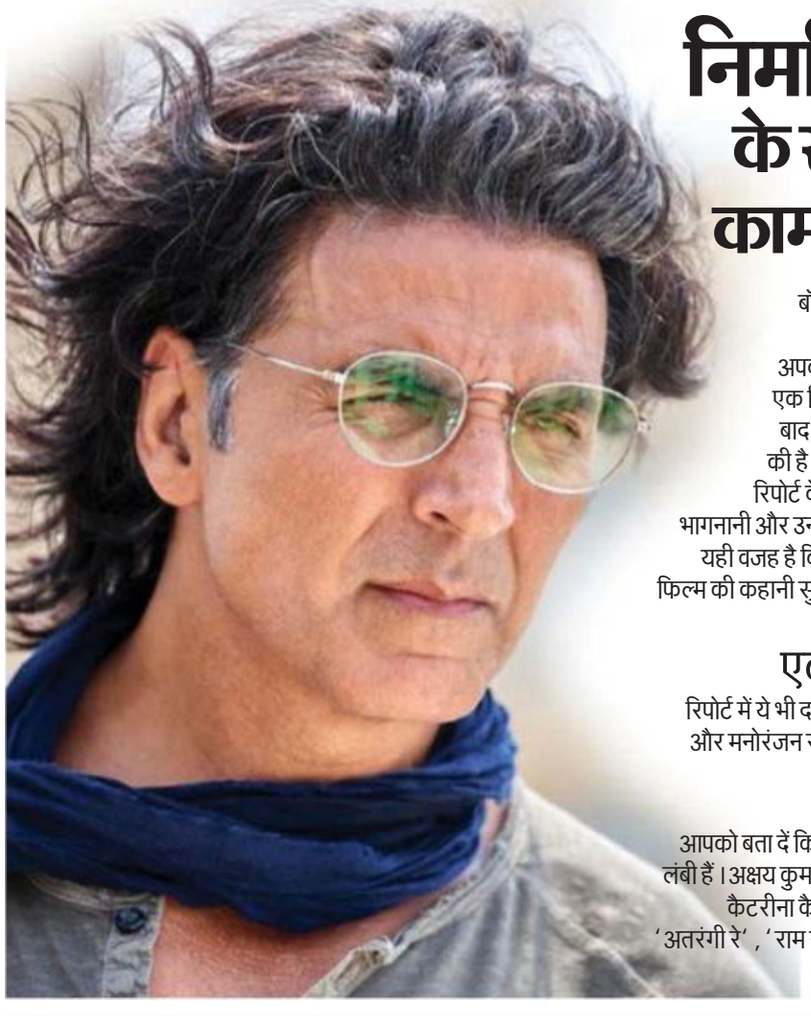

बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार के आस इन दिनों कई सारी फिल्में हैं। अभी हाल ही में उन्होंने निर्माता जैकी भागनानी की अपकमिंग फिल्म 'बेल बॉटम' की शूटिंग पूरी की है। अब इसी बीच एक रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया है कि अक्षय ने 'बेल बॉटम' के बाद निर्माता जैकी भागनानी के साथ एक और एक्शन फिल्म साइन की है और अभी से इस फिल्म के लिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, 'बेल बॉटम' की शूटिंग के दौरान ही अक्षय-जैकी भागनानी और उनके पिता वाशु भागनानी के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बन गई है। यही वजह है कि शूट पूरा होने के तुरंत बाद निर्माताओं ने अक्षय को अपनी नई फिल्म की कहानी सुना दी थी और स्क्रिप्ट देखने के बाद अक्षय ने भी इसका हिस्सा बनने के लिए राजी हो गए थे।

एक्शन और एंटरटेनर होगी फिल्म

रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि अक्षय की आने वाली यह फिल्म में एक्शन और मनोरंजन से भरी होगी, जिसकी शूटिंग इस साल ही शुरू कर दी जाएगी।

अक्षय की आने वाली फिल्में

आपको बता दें कि अक्षय कुमार की आने वाली फिल्मों की लिस्ट इस बार काफी लंबी हैं। अक्षय कुमार को जल्द ही निर्देशक रोहित शेट्टी की फिल्म 'सूर्यवंशी' में कैटरीना कैफ के साथ देखा जाएगा। इसके इतर उनकी आने वाली फिल्में 'अतरंगी रे', 'राम सेतु'.'बच्चन पांडे', 'रक्षाबंधन', 'पृथ्वीराज' में, 'बेल बॉटम' और ओह माई गॉड है।

टी20 विश्व कप को लेकर बीसीसीआई के अंतिम फैसले का इंतजार करेगा आईसीसी : अलार्डिस

दुबई, (एजेंसी)। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के अंतरिम सीईओ ज्यौफ अलार्डिस ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए अभी सभी जगह यात्रा प्रतिबंध लगे हुए हैं। ऐसे में आईसीसी भारत में होने वाले टी20 विश्व कप की मेजबानी को लेकर भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के अंतिम फैसले का इंतजार करेगा। इससे पहले बीसीसीआई ने भारत में टी20 विश्व कप की मेजबानी को लेकर आईसीसी से 28 जून तक का समय मांगा था। अभी विकल्प के रूप में संयुक्त अरब अमीरात और ओमान जैसे स्थलों को रखा गया है।

अलार्डिस ने कहा, हमें टूर्नामेंट के लिए स्वीकृत समय सीमा के दौरान पूर्ण प्रतियोगिता कराने की जरूरत है। योजना बनाने के नजरिए से, हमें निश्चितता चाहिए, कोविड-19 से जुड़ी पाबंदियों के समय वैश्विक प्रतियोगिताओं के आयोजन को लेकर परेशानियां बढ़ गयी हैं।

उन्होंने कहा, यात्रा को लेकर पाबंदियां हैं और अन्य देशों में प्रवेश को लेकर पृथकवास सहित कई अलग-अलग नियम हैं, होटलों में इंतजाम आदि। अलार्डिस ने कहा कि अंतिम फैसले में अब भी कुछ दिन का समय बाकी है। उन्होंने कहा, हमें फैसले को लेकर निश्चितता की जरूरत है, टूर्नामेंट का आयोजन कहां किया जा सकेगा। हम मैचों का कार्यक्रम तैयार करना शुरू कर सकते हैं और सभी योजनाएं बना सकते हैं, बोर्ड महीने के अंत में फैसला करेगा और इस समय हम इस मामले में लगातार बीसीसीआई के साथ बात कर रहे हैं जिससे कि मैचों के कार्यक्रम को अंतिम रूप देने का प्रयास कर सकें।

टेस्ट में इंग्लैंड का सामना करने के लिए तैयार है भारतीय महिला टीम : हरमनप्रीत

ब्रिस्टल, (एजेंसी)। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा है उनकी टीम मेजबान इंग्लैंड का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारतीय टीम को सात साल टेस्ट खेलने का अवसर मिल रहा है जिससे वह बेहद उत्साहित है। इसके अलावा उसे पुरुष टीम के बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे से भी खेल को लेकर अहम टिप्स मिले हैं उन्हें वह मैदान में अमल में लायेगी। हरमनप्रीत ने कहा, मैंने लाल गेंद से अधिक क्रिकेट नहीं खेला है, मैंने सिर्फ दो टेस्ट खेले हैं पर इस बार हमें रहाणे से बात करने का मौका मिला, हमने उनकी बातें सुनकर समझा कि लंबे प्रारूप में कैसे बेहतर बल्लेबाजी करनी है, हम मानसिक रूप से तैयार हैं। हरमनप्रीत ने कहा, हम नेट पर भी सही मानसिकता के साथ उतरने का प्रयास करते हैं। जब आप खुश होते हो तो आप अच्छा क्रिकेट खेलते हो। हम अपने मजबूत पक्षों के अनुसार खेलने का प्रयास करते हैं। साथ ही कहा कि हमें अनुभवी बल्लेबाज रहाणे से जो टिप्स मिले हैं उससे भी लाभ होगा। हरमनप्रीत ने कहा, रहाणे के पास इतना अधिक अनुभव है जो उन्होंने हमारे साथ बांटा, हमें टिप्स दिए कि कैसे बल्लेबाजी करनी हैं, बल्लेबाजी करते हुए क्या रवैया अपनाना है क्योंकि यह लंबा पारूप है और इसमें अपनी पारी को टुकड़ों में कैसे बांटा जाए यह अहम रहता है।

वहीं प्रतिभाशाली बल्लेबाज शेफाली वर्मा के टेस्ट पदार्पण को लेकर हरमनप्रीत ने कहा , शेफाली ऐसी खिलाड़ी है जिसे हम हमेशा खिलाना चाहते हैं, वह ऐसी खिलाड़ी है जो विरोधी पर दबाव बना सकती है। हमने कभी उसके खेल में बदलाव का प्रयास नहीं किया क्योंकि वह स्वाभाविक खिलाड़ी है, उसके साथ तकनीक या रणनीति के बारे में काफी अधिक बात करना अच्छा नहीं है। हरमनप्रीत ने कहा, हम सभी शेफाली के लिए अच्छी स्थिति तैयार करने का प्रयास करते हैं जिससे कि वह दबाव महसूस नहीं करे और अपने खेल का आनंद उठाए। नेट्स पर वह काफी अच्छी लय में लग रही है और उम्मीद करती हूं कि अगर उसे खेलना का मौका मिले तो वह अच्छा प्रदर्शन करेंगी।

टोक्यो में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के वाइस प्रेसीडेंट जॉन कोटस हेनेडा एयरपोर्ट पहुंचे।

इटली में एफआईवीबी वॉलीबाल नेशंस लीग में खेलते हुए चीन के डिंग झिया व यूवान जिनयूई।

डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए हालातों के अनुरूप ढलना होगा : वेंकटेश प्रसाद

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने कहा है कि न्यूजीलैंड के साथ 18 जून से साउथम्पटन में होने वाले विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल के लिए भारतीय टीम को हालातों के अनुरुप ढ़लना होगा। भारतीय टीम के पास हर क्षेत्र में पर्याप्त विकल्प हैं। जिससे वह इस मुकाबले में एक कहीं से भी पीछे नहीं है। प्रसाद का मानना है कि अस भारतीय टीम के पास तीसरा या चौथा तेज गेंदबाज उस स्तर का है जो नयी गेंद से बनाये गये दबाब को बरकरार रख सकता है जबकि उनके जमाने में ऐसा नहीं था। उन्हें लगता है कि टीम के पास किसी भी हालात में 350 रन बनाने की क्षमता वाले बल्लेबाज भी हैं। प्रसाद ने कहा, दो बेहतरीन टीमें फाइनल खेल रही हैं। भारत के पास बहुत सारे विकल्प हैं क्योंकि उसके अंतिम एकादश में जगह नहीं बना पाने वाले खिलाड़ी भी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा, पिच चाहे बल्लेबाजी के लिए आसान हो या तेज गेंदबाजों की मददगार हो, भारतीय टीम के पास बेहतर प्रदर्शन की क्षमता है। नब्बे के दशक और 2000 के दशक की शुरूआत में टीम के पास दो अच्छे तेज गेंदबाज होते थे पर तीसरा या चौथा विकल्प उतना बेहतर नहीं होता था।

उन्होंने कहा, अब टीम में वह ताकत है और उसके पास कुछ बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। हमारे पास हमेशा विश्व स्तरीय स्पिनर रहे है लेकिन अब हमारे पास विश्व स्तरीय तेज आक्रमण भी है। प्रसाद ने कहा, इसके साथ ही हमारे पास स्कोर बोर्ड पर 350 रनों बनाने वाली बल्लेबाजी भी है। अब हमने हर कमी को दूर कर लिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस तरह की पिच होगी। वहां हर तरह से भारत का दबदबा होना चाहिए।

भारतीय टीम के अंतिम एकादश के बारे में पूछे जाने पर प्रसाद ने कहा यह कप्तान विराट कोहली के लिए ज्यादा मुश्किल फैसला नहीं होगा। वह खुद चाहेंगे की दो स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और रविन्द्र जडेजा के साथ तीन तेज गेंदबाज इशांत शर्मा, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह इस मैच में खेले। उन्होंने कहा, अश्विन और जडेजा के साथ तीन तेज गेंदबाजों का संयोजन सबसे अच्छा लगता हैं। बुमराह, शमी और इशांत शर्मा को अलग-अलग परिस्थितियों में खेलने का अनुभव है, वे अपनी भूमिकाएं बखूबी जानते हैं।

हरभजन की पत्नी ने गोद भराई की तस्वीरें साझा कीं

जालन्धर, (एजेंसी)। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह दूसरी बार पापा बनने वाले हैं। हरभजन की पत्नी गीता बसरा ने सोशल मीडिया पर अपनी गोद भराई रस्म की तस्वीरें साझा की हैं। इस दौरान गीता नीले रंग की पोल्का डॉट ड्रैस में नजर आ रहीं हैं। वहीं पास में ही बेबी लिखा हुए नजर आ रहा है। गीता ने इसके साथ ही अपने पति और नजदीकि रिश्तेदारों, दोस्तों के लिए भी संदेश दिया।

क्या सुंदर और मधुर गोद भराई सरप्राइज था। पता नहीं मैं आप सभी के बिना क्या करूंगी लेकिन आप सभी ने मुझे इतना खास महसूस कराया और मुझे खुश किया ऐसे समय में जब आप एक-दूसरे को याद करते हैं तो ऐसे पलों को एक साथ नहीं मना पाते हैं और इतने सारे विशेष उत्सव होते हैं। लेकिन तुम लड़कियों ने वास्तव में कर दिखाया। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बैठे सभी लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करें जो हमें जोड़े रखते हैं। धन्यवाद, मेरे प्यार और मैं आपको अपने जीवन में पाकर बहुत धन्य हूं।

मेरे पति हरभजन सिंह आप सच में अच्छे साथी हैं।

गीता ने बीते दिनों ही पति भज्जी और बेटी हिनाया के साथ दूसरे बेबी के आने की घोषणा की थी। गीता ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें हिनाया के हाथ में एक टीशर्ट पकड़ी हुई थी जिसपर लिखा था कि जल्द ही मैं बढ़ी बहन बनने वाली हूं। सोशल मीडिया पर तभी से गीता और हरभजन सिंह को ढेरों बधाइयां मिल रही थीं।

हसन अली ने बदला अपना फैसला, पीएसएल में खेलेंगे

लाहौर, (एजेंसी)। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली अब पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) के बचे हुए सत्र में खेलने के लिए तैयार हैं। हसन के परिवार में चल रहा विवाद उनकी पत्नी ने सुलझा दिया है। उसी के बाद अब हसन खेलने के लिए तैयार हुए हैं। इससे पहले उन्होंने पारिवारिक कारणों से लीग से अपना नाम वापस ले लिया था , तब उन्होंने कहा था कि परिवार क्रिकेट से ज्यादा अहम है।

हसन संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में ही रहेंगे और इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेलना जारी रखेंगे। हसन के खेलने से इस्लामाबाद फ्रेंचाइजी भी उत्साहित है। वह इस लीग में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने छह मैचों में 14 की औसत से 10 विकेट लिए हैं। इस तेज गेंदबाज ने कहा कि उनकी पत्नी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह पारिवारिक मामलो को संभाल लेंगी और उन्हें अपने खेल पर ही ध्यान देना चाहिए।

इसके अलावा, हसन ने उनका समर्थन करने और फैसले का सम्मान करने के लिए टीम प्रबंधन की भी तारीफ की है। वहीं इस्लामाबाद टीम की ओर से जारी बयान में हसन ने कहा, वह हमेशा सबसे मुश्किल समय में मेरे साथ खड़ी रही हैं। उनके साथ सलाह के बाद मैंने पीएसएल-6 के शेष सत्र के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ रहने का फैसला किया है।

आईसीसी और पीसीबी पर बरसे अजमल

लाहौर, (एजेंसी)। पाकिस्तान के पूर्व ऑफ स्पिनर सईद अजमल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी)के नियमों पर सवाल उठाने के साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) पर भी निशाना साधा है। अजमल ने कहा कि पाकिस्तानियों को बस पैसा आना चाहिए, उन्हें अन्य किस बात से मतलब नहीं है। पीसीबी ने कभी भी आईसीसी के सामने विरोध दर्ज नहीं कराया।

अजमल ने इसके साथ ही उनपर लगे प्रतिबंध के लिए भी आईपीसी पर हमला बोला और कहा कि बल्लेबाजों का पावरप्ले जैसी सुविधाएं मिली हैं तेज गेंदबाज दो बाउंसर फेंक सकते हैं लेकिन स्पिनरों के लिए कुछ नहीं हैं।

आईसीसी ने स्पिनर्स को बेचारा बना दिया है। ऑफ स्पिनर की अगर आप विविधता ही खत्म कर दोगे तो वो हर ओवर में 15-20 रन देगा। जिस तरह के मोटे-मोटे बैट हैं और बाउंड्री छोटी कर दी गई है तो रन बनेंगे ही। हर लीग में 55 मीटर की बाउंड्री कर दी गई है जब तक स्पिनर के अंदर विविधता नहीं होगी उसका असर उतना नहीं होगा।

अजमल ने आगे कहा, राशिद खान से अगर उनकी गुगली छीन ली जाए तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वहीं सकलैन भाई दूसरा लेकर आए थे और आईसीसी ने उसे ही बंद करवा दिया। जिन गेंदबाजों ने 500-500 विकेट ले रखे हैं उन्हें आईसीसी ने प्रतिबंधित कर दिया था। मैं 8 साल से क्रिकेट खेल रहा था और आईसीसी ने सारे नियम मेरे पर ही लगा दिये।

विदेशी क्रिकेटरों की पसंद बन रहे भारतीय हेलमेट

नई दिल्ली, (एजेंसी)। क्रिकेट के खेल में हेलमेट का अहम स्थान है। इससे खिलाड़ी सिर में लगी चोट से बच जाते हैं। अब भारतीय हेलमेट दुनिया भर के क्रिकेटरों की पसंद बनते जा रहे हैं। जालंधर के श्रेय स्पोर्ट्स के तैयार किए हुए हेलमेट ना सिर्फ भारत के खिलाड़ी बल्कि विदेशी क्रिकेटर भी पहन रहे हैं। समय के साथ ही इन हेलमेटों में कई बदलाव भी आये हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात करें तो 60 से 70 प्रतिशत तक ये हेलमेट इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर पहनते हैं।

दिवंगत ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर फिल ह्यूज की मौत के बाद हेलमेट के साथ नेकगार्ड को भी लाया गया। यह गेंद को खिलाड़ी के सिर के पीछे लगने से बचाता है, क्योंकि हेलमेट पूरा नीचे तक नहीं होता। ऐसे में गेंद के गर्दन की तरफ लगने का खतरा बना रहता है। नेकगार्ड खिलाड़ियों की सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए लाया गया है। ह्यूज को सिर के पीछे गेंद लगी थी।

कंपनी के प्रमोटर के अनुसार इंटरनेशनल ब्रांड होने के कारण हमारे लिए खिलाड़ियों की सुरक्षा सबसे पहले है। इसलिए हमने आईसीसी और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर नए सुरक्षा स्तर लॉन्च किए थे। इन्हें ब्रिटिश सेफ्टी स्टैंडर्स कहा जाता है। इसके तहत यह फैसला हुआ था कि अब मार्केट में जो भी हेलमेट आएगा, वह टेस्ट किया हुआ होगा और स्टीफाइड होगा। कोई भी खिलाड़ी टेस्ट किया हुआ हेलमेट पहनकर ही क्रिकेट के मैदान पर उतर सकता है। अगर खिलाड़ी का हेलमेट टेस्ट नहीं किया हुआ है तो वह मैदान पर खेलने नहीं उतरेगा।

बट्ट ने पाक गेंदबाजों पर निशाना साधा, खेल की जगह फिटनेस पर है ध्यान

नई दिल्ली, (एजेंसी)। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सलमान बट्ट ने पाकिस्तानी टीम के युवा गेंदबाजों का जमकर मजाक बनाया है। बट्ट ने कहा कि ये गेंदबाज बिना डिग्री वाले डॉक्टर की तरह ही हैं।

उन्होंने कहा है कि आज के युवा गेंदबाज प्रथम श्रेणी क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय फिटनेस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। यह इसी प्रकार है जैसे कोई बिना एमबीबीएस की डिग्री लिए ही डॉक्टर बन जाए।

बट्ट पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) के छठे सीजन में कुछ पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों की कमियों से नाराज दिखे। उन्होंने कहा, 140 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि अगर आप सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी नहीं करते हैं तो बल्लेबाजों को इस तरह की हाफ वॉली वाली गेंदों को खेलने में कोई परेशानी नहीं होगी। उन्हें केवल शॉट लगाना होगा।

उन्होंने कहा, गति आपकी सहायता करेगी, जब आप सही लाइन और लेंथ पर स्विंग और गेंदबाजी करना जानते हों। इसलिए गेंदबाजों को प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलने में ज्यादा समय बिताना चाहिये पर इसकी जगह वे जिम में जाते हैं।

ऐसा लगता है जैसे तेज गेंदबाज अब सिर्फ 140 से अधिक की गति से गेंदबाजी चाहते हैं, वे स्विंग, लाइन और लेंथ पर निर्भर रहने की जगह केवल तेज गेंदबाजी करना चाहते हैं। बट्ट का संकेत नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन की युवा तेज गेंदबाजी जोड़ी की तरफ था जो युवा गेंदबाज लगातार 140-145 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं पर वे अपने घरेलू खेल पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं।

इंजमाम ने भारतीय टीम के पाकिस्तान और श्रीलंका से आगे निकलने का कारण बताया

लाहौर, (एजेंसी)। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम-उल-हक ने कहा हि पिछले एक दशक में किये अपने सुधारों के बल पर ही भारतीय टीम अपने प्रतिद्वंद्वियों पाकिस्तान और श्रीलंका से कहीं आगे निकल गई है। इंजमाम ने कहा कि भारतीय क्रिकेट ने इन वर्षों में अपने खेल में काफी सुधार किया है और उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट संरचना और आईपीएल पर विशेष ध्यान दिया जिसका परिणाम इस रुप में आया है। इंजमाम ने कहा साल 2010 तक इन तीन टीमों के बीच तगड़ी टक्कर होती थी पर पिछले 10-12 वर्षों में भारत ने अपने खेल में काफी सुधार किया है और निश्चित रूप से पाकिस्तान और श्रीलंका से आगे निकल गया है। इसका श्रेय निश्चित रूप से आईपीएल को भी जाता है, लेकिन मैं यह स्वीकार करना चाहिए कि भारत ने अपने प्रथम श्रेणी क्रिकेट ढांचे पर बहुत ध्यान केंद्रित किया है और इसने विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। पाक के इस पूर्व कप्तान ने कहा, संघों को पैसा और खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के साथ ही विश्व स्तरीय सुविधाएं मिली हैं वहीं पाक और श्रीलंका अपने प्रथम श्रेणी क्रिकेट को विकसित करने में विफल रहे।

इस पूर्व क्रिकेटर ने इस साल की शुरूआत में ऑस्ट्रेलिया पर भारत की यादगार जीत पर कहा कि टीम अपने कप्तान विराट कोहली की अनुपस्थिति के बाद भी ऑस्ट्रेलियाई टीम को हराने में सफल रही यह बड़ी बात है। शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज, ऋषभ पंत, शार्दुल ठाकुर और वाशिंगटन सुंदर जैसे युवाओं ने टीम की जीत में योगदान दिया। इंजमाम ने कहा, करीब 15 साल पहले, जब कोई युवा टीम में आता था तो उसे कुछ साल का समय मिलता था, लेकिन अब सांस लेने की कोई जगह नहीं है। जैसे ही कोई टीम में प्रवेश करता है, हम उससे प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं।

पीएसएल में मुनरो और इफ्तेखार ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत दिलाई

दुबई, (एजेंसी)। कोलिन मुनरो और इफ्तेखार अहमद की शानदार पारियों से पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने करांची किंग्स को 8 विकेट से पराजित किया। इफ्तेखार ने 71 रन बनाये ओर वह आउट नहीं हुए जबकि मुनरो ने सबसे ज्यादा 88 रन बनाये । इस बल्लेबाज ने अपनी इस पारी में 5 चौके और 5 छक्के लगाये। वहीं कराची की ओर से बाबर आजम ने भी 81 रन की शानदार पारी खेली पर वह अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाये। कराची की तरफ से खेल रहे कीवी खिलाड़ी मार्टिक गुप्टिल भी इस मैच में नाकाम रहे। वह मोहम्मद वसीम का शिकार बने और आउट होने के बाद स्वयं से ही नाराज दिखे।

इस मैच में

कराची किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 190 रन बनाए। आजम ने 54 गेंद पर 81 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उनके अलावा नजीबुल्लाह जादरान ने 42 गेंद पर 71 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 4 छक्के शामिल थे।

इस्लामाबाद की पारी की शुरूआत अच्छी नहीं रही। उस्मान ख्वाजा और मोहम्मद अखलाक जल्दी आउट हो गए। उसके बाद कोलिन मुनरो और इफ्तेखार ने पारी संभाली। मुनरो ने 88 और अहमद ने 71 रन बनाकर इस्लामाबाद को जीत दिलाई।

हाले में स्विटजरलैंड के टेनिस स्टार रोजर फेडरर एटीपी टूर के एकल मुकाबले में खेलते हुए।